चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

काले धन का सौदागर हसन अली

पेज-3

सत्ता के दावेदारों में घमासान

पेज-5

भारत में ख़तरनाक भूकंप आ सकते हैं

पेज-7

साई की महिमा

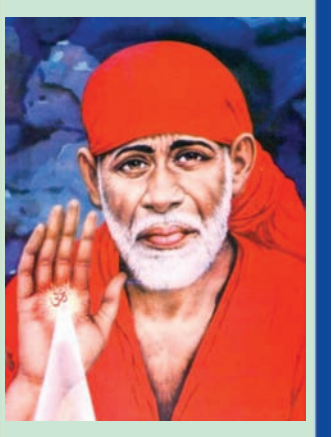

पेज-12

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 04 अप्रैल-10 अप्रैल 2011

मूल्य 5 रुपये

पीछे हट गए रामदेव

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

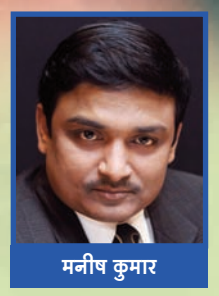

मनीष कुमार

- रामदेव के राजनीतिक भाषण के सीधे प्रसारण पर रोक
- रामदेव को कांग्रेस के एक नेता ने धमकी दी
- रामदेव की आरएसएस की विचारधारा से निकटता
- संतों ने रामदेव की पुस्तक जलाई

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, योगगुरु बाबा रामदेव के दोस्त और दुश्मन खुलकर सामने आने लगे हैं. बाबा के ख़िलाफ़ हरिद्वार के संत समाज के कुछ संत, अखाड़ा परिषद के कुछ बड़े-बड़े धर्माचार्य दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं. कांग्रेस पार्टी से उनकी दुश्मनी अब गहराती जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दोस्ती रंग बिखेरने लगी है. जैसे-जैसे बाबा रामदेव की राजनीति परवान चढ़ेगी, वैसे-वैसे सवाल भी उठने लगेंगे. इन सवालों का जवाब रामदेव को देना होगा. मसलन, अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसकी विचारधारा क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होगी, दलितों-किसानों-मजदूरों के लिए रामदेव की पार्टी क्या करेगी, विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी. बाबा रामदेव अपने भाषणों में व्यवस्था बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन व्यवस्था बदल कर वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी, यह उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए.

कांग्रेस पार्टी अब बाबा रामदेव को सरकारी ताक़त का एहसास कराने में लगी है. पहली बार बाबा रामदेव बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं. काले धन और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनके स्वाभिमान आंदोलन को 23 मार्च को झटका लगा. उस दिन हरियाणा के झज्जर में उनकी रैली थी. इसका ऐलान वह पहले ही कर चुके थे. क़रीब 20 हज़ार लोग जमा भी हुए, लेकिन देश में किसी को पता नहीं चल सका कि बाबा रामदेव ने क्या कहा, उनके साथियों ने राजनीतिक दलों पर क्या नए आरोप लगाए, भ्रष्टाचार और काले धन से रामदेव की लड़ाई में क्या नया मोड़ आया. दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद रामदेव से देश की जनता की उम्मीदें बढ़ गई थीं, लेकिन आस्था चैनल पर रामदेव के भाषण को लाइव दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि आस्था चैनल को धार्मिक कार्यक्रम दिखाने के लिए लाइसेंस दिया गया है. उस चैनल पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं दिखाया जा सकता है. सरकार कहती है कि आपका धार्मिक चैनल है. आप धर्म की बात करें, आत्मा-परमात्मा की बात करें. राजनीति की बातें धार्मिक चैनल पर करना मना है. झज्जर में रैली हुई, लेकिन आस्था पर इसका लाइव प्रसारण नहीं हुआ. दूसरे चैनलों ने भी इसे न तो लाइव दिखाया और न ही बाद में इस रैली के बारे में कोई ख़बर दी. देश के कई चैनलों के मालिकों से बाबा रामदेव की दोस्ती है, फिर भी किसी ने बाबा रामदेव को न तो दिखाया और न ही कोई ख़बर दी. इसकी वजह जानना भी दिलचस्प होगा. दिल्ली के अख़बारों में भी बाबा रामदेव की रैली का नामोनिशान नहीं मिला.

इस मामले में हमने बाबा रामदेव के साथियों से बातचीत की, जो स्वाभिमान आंदोलन में उनके साथ हैं. उनका मानना है कि यह नोटिस ग़ैर कानूनी है. यह आर्टिकल 19 के विरोध में है, जिसके तहत विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार है. इस पर दो तरह की रोक है. पहली यह कि अपने विचारों से हिंसा भड़काने पर मनाही है और दूसरी यह कि भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ बोलना मना है. अब सवाल उठता है कि क्या बाबा सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हिंसा भड़काने वाला भाषण देते हैं या फिर संविधान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात स्वाभिमान आंदोलन में रामदेव के सहयोगी एवं इनकम टैक्स विभाग के पूर्व कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता ने बताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब बाबा रामदेव को धमकी दे रहे हैं कि तुम राजनीति में मत आओ. तुम अपना धर्म-कर्म का काम करो. ये कांग्रेसी नेता किस हैसियत से बाबा रामदेव को धमकी दे रहे हैं. बाबा को टेलीफोन पर यह धमकी दे गई है. वहीं भारत स्वाभिमान आंदोलन में रामदेव के क़रीबी इस्मालिक धर्मगुरु मौलाना क़ल्बे रूशैद रिज़वी ने कहा कि इतनी बड़ी सरकार, जिसका नाम भारत सरकार है, अगर वह सरकार रामदेव की आवाज़ बंद कर रही है तो उससे रामदेव का कद बढ़ रहा है. दिलों में रामदेव बड़े थे ही, अब दलों में भी रामदेव बड़े हो गए हैं, वर्ना एक फकीर की आवाज से सरकार को क्या ख़तरा हो सकता है. झज्जर की रैली में लोग उत्तेजित थे. सब यह सवाल कर रहे थे कि बाबा रामदेव के भाषण के सीधे प्रसारण को सरकार ने सेंसर क्यों किया. बाबा रामदेव ने इन लोगों से कहा-सब्र रखो, मैंने तो बाण छोड़ दिया है, लगेगा ज़रूर. जल्दी नहीं लगेगा तो देर से लगेगा, लेकिन छाती के बीच में लगेगा. आस्था चैनल पर रामदेव की रैलियों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने अपनी ताक़त दिखाई, लेकिन इस पर बाबा रामदेव क्या करेंगे, यह देखना बाकी है.

कांग्रेस पार्टी और बाबा रामदेव आमने-सामने क्यों हो गए. क्या मतभेद सिर्फ़ काले धन को लेकर है, क्या कांग्रेस इसलिए नाराज़ है कि बाबा रामदेव के मंच से गांधी परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं. बाबा की दोस्ती गांधी परिवार के दुश्मनों से हो गई है, इसलिए तो कांग्रेस आगबबूला नहीं है. वैसे रामदेव ने कई बार यह कहा है कि उनकी किसी पार्टी से शत्रुता नहीं है, लेकिन वह देश के भ्रष्ट तंत्र के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. इसलिए बाबा रामदेव के निशाने पर वर्तमान सरकार है. बाबा रामदेव यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार में भाजपा भी होती तो भी वह आंदोलन करते. क्या सचमुच ऐसा है.

रामदेव के आंदोलन का पहला लक्ष्य काला धन वापस लाना है और विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों को बेनक़ाब कर उन्हें दंडित करना है. इस मुहिम में बाबा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए. विदेशी बैंकों में जमा भारत का धन अगर वापस आ गया तो सचमुच देश के वारे-न्यारे हो जाएंगे, इसमें कोई शक़ नहीं है. बाबा की इस मुहिम का विरोध करना देशद्रोह की तरह है. लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या देश का काला धन सिर्फ़ विदेशी बैंकों में है. देश में जो काला धन है, जमाखोरी है, कालाबाज़ारी है, उसका क्या होगा. काले धन से बाबा रामदेव का आशय देश के बड़े पूंजीपतियों से है, जिन्होंने देश के लोगों के ख़ून-पसीने की कमाई विदेश में जमा कर रखी है. लेकिन हमारे देश में मध्यमवर्गीय पूंजीपति भी हैं, जिसका सीधा रिश्ता भी आम लोगों से होता है. पूंजीपतियों की जो बी श्रेणी है, इस काले धन की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है. देश में जो काला धन पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा. विदेश से काले धन को लाया जाए, उसमें पूरा हिंदुस्तान बाबा रामदेव के साथ है. बाबा रामदेव को विदेश में जमा काले धन के साथ देश के अंदर मौजूद काले धन को बाहर निकालने के लिए भी अपनी मुहिम में जगह देनी चाहिए. दिल्ली की एक मशहूर दुकान है, जब भी वहां छापा पड़ता है तो घी के कनस्तर में हज़ार रुपये की गड्डी मिलती है. असलियत यह है कि जितना विदेश में काला धन है, उससे कई गुना ज़्यादा भारत में काला धन है. जो कहीं हीरे के रूप में है, सोने के रूप मे है, कैश के रूप में है, जिसे लोग जमीन के अंदर गाड़कर रखते हैं. देश में मौजूद काला धन ही भ्रष्टाचार की जननी है. घूस में जो पैसा दिया जाता है, वह सफ़ेद नहीं, काला धन ही होता है. अगर देश के अंदर मौजूद काले धन को पकड़ा जाए तो देश के वारे-न्यारे होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाएगा. उसके ख़िलाफ़ बाबा रामदेव

(शेष पृष्ठ 2 पर)

> कांग्रेस पार्टी के नेता अब बाबा रामदेव को धमकी दे रहे हैं कि तुम राजनीति में मत आओ. तुम अपना धर्म-कर्म का काम करो. ये कांग्रेसी नेता किस हैसियत से बाबा रामदेव को धमकी दे रहे हैं.
>
> -विश्वबंधु गुप्ता

> रामदेव की आवाज़ बंद करने से रामदेव का क़द बढ़ रहा है. दिलों में रामदेव बड़े थे ही, अब दलों में भी रामदेव बड़े हो गए हैं, वर्ना एक फ़क़ीर की आवाज़ से सरकार को क्या ख़तरा हो सकता है.
>
> -कल्बे रूशैद रिज़वी

कृषि वैज्ञानिकों और इससे संबंधित शिक्षकों एवं छात्रों की सर्वोच्च संस्था है, ने लड़ाई आर-पार की करने की ठान ली है.

दिल्ली का बाबू

कृषि बाबुओं का विरोध

कृषि विभाग के अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने मांग रखी है कि अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे ईइएस और ईपीएस की तर्ज़ पर भारतीय कृषि सेवा भी शुरू की जाए. पहले भी इस तरह की मांग उठती रही है. यहां तक कि सरकारी कमेटियों और कमीशनों ने भी ऐसा करने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं. इस बार इस मुहिम का नेतृत्व कर रही आल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ एग्रीकल्चरल एसोसिएशन, जो कृषि वैज्ञानिकों और इससे संबंधित शिक्षकों एवं छात्रों की सर्वोच्च संस्था है, ने लड़ाई आर-पार की करने की ठान ली है. उनकी सबसे बड़ी शिक़ायत यह है कि भारत में जहां 65 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से अर्जित होती है, वहां इस क्षेत्र में, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, वे लोग नियोजित हैं जिन्हें कृषि की ज़रा भी जानकारी नहीं है. कृषि से संबंधित अफसरों की इस मांग पर न शरद पवार और न ही कृषि सचिव प्रबीर कुमार बासु ने कोई वक्तव्य दिया है.

नया ज़मीन घोटाला

दिलीप चेरियन

ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ़ लालची बिल्डरों ने ही मुनाफ़े के लिए उम्दा ज़मीनों का अधिग्रहण किया है. अगर सरकार को भी मौक़ा मिला है तो वह भी ऐसा करने से नहीं चूकती. सरकारी दफ्तरों को आवासीय परिसर बनाया गया है. सूत्रों के अनुसार, नागरिक विमानन के डायरेक्टर जनरल (डीजीसीए) ने अपने जोरबाग स्थित कई सौ करोड़ के ऑफिस को अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाने का फ़ैसला किया है. ऐसा पता चला है कि यह योजना एक साल पहले ही बना ली गई थी. इसके तहत वर्तमान ऑफिस को आवासीय सोसाइटी बना दिया जाएगा और नागरिक विमानन मंत्रालय नए फंड से नया ऑफिस निर्मित करेगा. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस योजना को योजना आयोग ने भी हरी झंडी दिखा दी. यह योजना सफल हो जाती, अगर वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय ने उंगली न उठाई होती. शहरी विकास मंत्रालय ने डीजीसीए से कहा है कि यह ज़मीन सीपीडब्ल्यूडी की है, यह उसी को वापस कर दी जानी चाहिए. सूत्रों के अनुसार, अब डायरेक्टर जनरल कह रहे हैं कि इस योजना को रद्द कर दिया गया है. ऐसे में इस दौरान नए ऑफिस के लिए जगह की खोज जारी है.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

हेमंत सीएमडी पद की दौड़ में आगे

हेमंत कांट्रेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी पद की दौड़ में प्रतीप चौधरी को पीछे छोड़ते हुए फ्रंट पर आ गए हैं. हेमंत वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीएफओ के पद पर कार्यरत हैं. अब तक प्रतीप को ही ओ पी भट्ट की कुर्सी का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब दौड़ में हेमंत का नाम सबसे आगे आ रहा है.

गुजराल को सेवा विस्तार

हरियाणा कैडर और 1976 बैच के आईएएस अधिकारी आर एस गुजराल, जिन्हें हाल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन का पद सौंपा गया था, को तीन महीने का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिल गया है. ग़ौरतलब है कि गुजराल सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय में सचिव भी हैं. गुजराल को चेयरमैन पद का अतिरिक्त प्रभार ब्रजेश्वर सिंह के 31 दिसंबर, 2010 को सेवानिवृत्त होने के बाद मिला था.

इलियास की जगह उपेंद्र

उड़ीसा कैडर और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है. उनसे पहले इस पद पर केरल कैडर और 1982 बैच के आईएएस अधिकारी जी इलियास काबिज थे, जो बीते दिसंबर माह में ट्राई में बतौर प्रधान सहायक नियुक्त हुए हैं.

हठयोगी समेत दर्जनों संतों के ख़िलाफ़ मुक़दमा

राजकुमार शर्मा

बाबा रामदेव और उनके स्वाभिमान ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संतों के ख़िलाफ़ हरिद्वार कोतवाली में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हठयोगी समेत बीस-पच्चीस लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर आग में घी डालने का काम कर दिया है. संत समाज का मुखर विरोध झेल रहे योगगुरु की दिव्य योग पीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत दर्शन के एक लेख ने रामदेव की हिंदू विरोधी मानसिकता की कलई खोलकर रख दी है. महाकुंभ आयोजित कराने वाली संतों की संस्था अखाड़ा परिषद के सैकड़ों संतों ने एकजुट होकर दिव्य योग प्रकाशन की पुस्तकों कों हिंदू जनमानस विरोधी घोषित करते हुए सरेआम उनकी होली जलाई.

इस घटना के बाद अपने बढ़ते विरोध से बचने के लिए बाबा समर्थकों ने आनन-फानन में हरिद्वार कोतवाली पहुंच कर धर्मनगरी के छब्बीस संतों के ख़िलाफ़ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया. हरिद्वार कोतवाली में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश कुमार ने जो तहरीर संतों के खिलाफ दी, उसके आधार पर हरिद्वार पुलिस ने बीते 23 मार्च को मुकदमा अपराध संख्या 122, भारतीय दंड संहिता की धारा

353 ए-बी, 295 ए और 504 के तहत हठयोगी सहित 26 संतों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके जांच दारोगा आर पी कनौजिया को सौंप दी है.

मामले के विवेचनाधिकारी कनौजिया का कहना है कि धार्मिक भावना भड़काने का आरोप सही पाए जाने पर इन संतों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. विवेचनाधिकारी के थाना क्षेत्र से बाहर होने के कारण दो दिनों तक पुलिस इन संतों पर कोई दबाव नहीं बना सकी. सर्वाधिक मुखर विरोध करने वाले संत हठयोगी का कहना है कि रामदेव एवं उनकी संस्था की हिंदू विरोधी कार्यवाही का हर स्तर पर विरोध करने के फ़ैसले पर वह और परिषद के संत अभी भी कायम हैं. उनका कहना है कि सनातन हिंदू धर्म का अपमान और उस पर प्रहार हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नही करेंगे, चाहे हम संतों पर एक नहीं, हज़ार मुकदमे लाद दिए जाएं. बाबा की दिव्य योग पीठ से प्रकाशित संत दर्शन नामक उक्त पुस्तक के पेज नंबर 186 पर लिखा गया है-हिंदू समाज ऐसे आततायियों का दल है, जो अपने किसी भी सदस्य को एक क्षण भर के लिए सुख की सांस नहीं लेने देता. अत्याचारी हिंदू समाज अपने सदस्यों को पिछले जन्मों में किए गए पापों का फल भी इसी जन्म में भोगने के लिए विवश करता है. अहिंसा का साइन बोर्ड लगाकर दया का ढ़िढोरा पीटकर कसाइयों की तरह व्यवहार करना, धर्म के नाम पर बड़ी-बड़ी लीलाएं करना, धर्म के लेबल में पाप का बंडल बांधना, चंदन-कपूर का तिलक लगाकर दिन-रात अपनी अंतरात्मा को द्वेषानल से दग्ध करना और संसार की आंखों में मिथ्याचार की धूल झोंकना हिंदू समाज का पेशा है. पुस्तक के पेज नंबर 189 पर भी हिंदुओं को भड़काने वाली बातें लिखी हैं, जैसे-हिंदू समाज कितना मूर्ख है, जो दिन-रात झूठ बोलता हुआ दूसरों से सत्य बोलने की आशा करता है. स्वयं तो व्याभिचार में लीन रहता है, परंतु दूसरों को सदाचार का उपदेश देना अपना परम धर्म समझता है. वह इतना भी नहीं समझता कि एक दर्जन बच्चों का बाप भी अपनी विषय वासना पर काबू नहीं कर सकता तो सोलह-सत्रह वर्ष की अबोध बालिका अपने यौवन को कैसे संभाल सकती है. धर्म नगरी हरिद्वार के संत अब तक योग गुरु को बाबा मानने से इंकार कर रहे थे, अब वही संत बाबा को हिंदू धर्म विरोधी और संत समाज विरोधी बताकर उन्हें आईना दिखाने पर आमादा हैं. संतों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों एवं संत समाज ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है. प्रतिनिधिमंडल ने रामदेव पर हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है.

feedback@chauthiduniya.com

पीछे हट गए रामदेव

पृष्ठ एक का शेष

क्यों नहीं बोलते हैं. इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सिर्फ़ विदेश में जमा काले धन को वापस लाने से भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा.

बाबा रामदेव देश को नई दिशा पर ले जाना चाहते हैं. काले धन को वापस लाना, भ्रष्टाचार ख़त्म करना आदि किसी भी दल का एक एजेंडा हो सकता है. देश को चलाने के लिए एक संगठित विचारधारा की जरूरत होती है, जिससे देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति और विकास का रास्ता तय होता है. बाबा रामदेव से यह सवाल इसलिए पूछा जाना लाजिमी है, क्योंकि उन्होंने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 542 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. देश की जनता का यह हक़ बनता है कि चुनाव से पहले वह यह जाने कि रामदेव की पार्टी की विचारधारा क्या है.

बाबा रामदेव ने अब तक अपने आंदोलन या पार्टी की कोई समग्र और संगठित विचारधारा पेश नहीं की है. वह अपने शिविरों और रैलियों में राजनीति के बारे में बातें करते हैं. उनकी बातों से लगता है कि बाबा रामदेव भारत में स्वदेशी व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार, गोहत्या के विरोध और अखंड भारत के पैरोकार हैं. रामदेव के भाषणों से जो बात समझ में आती है, उससे यही लगता है कि बाबा रामदेव की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा एक जैसी है. रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने कहा कि स्विस बैंकों से चार सौ करोड़ भारत लाना है और गौ हत्या के पाप से भी देश को बचाना है. गो हत्या को अपराध संघ भी मानता है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में आती है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाती है. बाबा रामदेव कहते हैं कि वह देश में स्वदेशी तंत्र, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं. अब यह स्वदेशी व्यवस्था क्या है. कई सालों से आरएसएस स्वदेशी का आंदोलन चला रहा है. बाबा के स्वदेशी और संघ के स्वदेशी में कोई अंतर है भी या नहीं. यह रामदेव को सफ़ाई से बताना चाहिए. बाबा रामदेव अपने भाषणों में कहते हैं कि भाषा के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. दुनिया का कोई स्वतंत्र देश विदेशी भाषा में नहीं पढ़ता है. यह अन्याय भी मिटाना है. स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेजी तंत्र चल रहा है, उसे भी मिटाना है. अब सवाल है कि अगर हिंदी को हम पूरे देश में लागू करेंगे तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन होंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा. मज़ेदार बात यह है कि आरएसएस भी अंग्रेजी के बहिष्कार और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्षधर है. काले धन पर भी रामदेव ने भाजपा वाली लाइन ले ली. विदेश में जमा काले धन को

निशाना बनाया. आश्चर्य की बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी ने काले धन का मामला उठाया, तबसे बाबा रामदेव ने भी उस काले धन को मुख्य मुद्दा बनाया, जो विदेश में है. एक और मुद्दा चौंकाने वाला है. देश में यह अकेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, जो इक्कीसवीं सदी में भी अखंड भारत की बातें करता है और यही सपना बाबा रामदेव की आंखों में नज़र आता है. दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में बाबा रामदेव ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कैलाश मान सरोवर जो भारत का मुकुट है, उसे भी भारत में वापस लाना है. हो सकता है, बाबा रामदेव अति उत्साह में यह बात कह गए होंगे, लेकिन मंच पर बैठे मुस्लिम नेता भी बाबा की इस बात को सुनकर सहम गए. बाबा रामदेव की बातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा झलकता है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि भारत में जितनी भी पार्टियां या संगठन हैं, उनमें बाबा रामदेव की सबसे ज़्यादा वैचारिक निकटता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है.

सरकार ने आस्था चैनल पर राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध ज़रूर लगा दिया, लेकिन बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को एक न्यूज चैनल लगाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा. जिस पर दिन भर बाबा रामदेव बोलेंगे. भारत एक अजीबोग़रीब देश है. यहां धर्म और राजनीति में फ़र्क़ कर पाना बड़ा मुश्किल है. हिंदुस्तान ऐसा देश है, जहां धर्म और राजनीति एक-दूसरे के विरोधाभासी नहीं, बल्कि कई मायनों में पूरक भी हैं. हिंदुस्तान में तो मजहब के बिना सियासत अंधी है और सियासत के बिना मजहब लंगड़ा है. बाबा रामदेव पूरे देश को नेतृत्व देना चाहते हैं. इस देश में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी हैं. बाबा रामदेव को देश के हर धर्म, जाति एवं क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखना होगा. भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं लाया जा सकता. वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात से खुश होना चाहिए कि उनकी विचारधारा को फैलाने का काम देश का सबसे लोकप्रिय संत कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी को इस बात से खुश होना चाहिए कि जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने और मानने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, वह काम बाबा रामदेव कर रहे हैं. वैसे देश की राजनीति में दोस्त मिलना मुश्किल है और सामने से लड़ने वाले दुश्मन तो और भी मुश्किल से मिलते हैं. कांग्रेस पार्टी को इस बात से खुश होना चाहिए कि जिस विचारधारा से वह लड़ने का दंभ भरती हैं, उसी एजेंडे को लेकर रामदेव आमने-सामने लड़ने को तैयार हैं. वैसे भारत की राजनीति में छिपकर वार करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है. एजेंडे को सामने रखकर सीधी लड़ाई लड़ने वाले राजनेता रामदेव का स्वागत होना चाहिए.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 4
दिल्ली, 04 अप्रैल-10 अप्रैल 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हसन अली गोल्फ का शौक़ीन है, वह ज्यूरिक, लंदन और दूसरे देशों में गोल्फ खेला करता था. इसके पास भारत के ही छह पासपोर्ट हुआ करते थे.

काले धन का सौदागर हसन अली

हसन अली, एक ऐसा नाम, जिसकी ज़ुबान अगर खुल जाए तो देश में राजनीतिक भूकंप आ सकता है. यह देश के काले धन को विदेशी बैंकों में जमा कराने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है. इसके रिश्ते देश-विदेश के राजनेताओं, अंडरवर्ल्ड माफ़िया और हथियार के सौदागरों से है. हसन अली की असल पहचान क्या है, इसके काम करने का तरीक़ा क्या है, अब तक यह पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा आदि सवालों का जवाब पेश कर रही है हसन अली की यह पूरी कहानी.

रीतिका सोनाली

एक चोर प्रवृत्ति का ठग व्यक्ति हुआ करता था नटवर लाल. उसने तीन बार ताजमहल को, दो बार लालकिले को और एक बार तो राष्ट्रपति भवन को भी भोले-भाले विदेशी पर्यटकों को बेच डाला था. इस नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था. नटवर लाल ने अपनी चालाकी से सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपये मार लिए. वैसे ही अपना नाम बदल कर चोरी करने वाला एक शख्स बनकर उभरा है हसन अली. हसन अली की कहानी कई राज़ होने की वजह से परतों में दबी है. दरअसल, 1982 से पहले हैदराबाद में हसन अली को लोग चोर अली के नाम से जानते थे. बारहवीं पास अली एंटिक कलाकृतियां बेचने का काम करता था. उस वक़्त पूरे हैदराबाद में चर्चा थी कि अली के पास निज़ाम की पुरानी मूर्तियां और अन्य वस्तुएं हैं. पुलिस की तफ्तीश में यह चर्चा खोखली नहीं निकली और पता चला कि अली के पास नि-जाम के एंटिक कुछ तो असली थे और कुछ उसने नक़ली बनवा कर रखे थे, जिन्हें बेचकर वह अपना जीवन बसर करता था. हसन अली ख़ुद बारहवीं तक पढ़ा है, फिर भी वह बारहवीं कक्षा के छात्रों की ट्यूशन लेता था. अपने शातिर दिमाग़ के चलते वह छात्रों और स्कूलों को गुमराह करने लगा. हसन अली की पुलिस-प्रशासन में इतनी पैठ थी कि आधा दर्जन क्रिमिनल और धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने के बावजूद हैदराबाद पुलिस ने उसे यह कहकर क्लीन चिट दे दी थी कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

अमीर बनने का सपना लेकर बड़े हुए हसन अली को किसी भी तरह के सामान्य व्यापार या कामकाज में बड़ी-बड़ी गाड़ियों और हवेलियों के सपने पूरे होते नहीं दिखे तो इस शातिर दिमाग़ अली ने हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए. 1990 के दशक में यह चोर अली मशहूर हो गया और हैदराबाद के सबसे शानदार इलाक़े बंजारा हिल्स में रहने लगा. साथ में पत्नी महबूबा ख़ान और दो बेटे भी रहते थे, लेकिन इसी दरम्यान हसन अली ने हैदराबाद छोड़ने का मन बना लिया. वर्ष 1993 हसन अली के लिए ख़ास था. इस साल सिंगापुर के एक बैंक के किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो गई. उस व्यक्ति के किसी जानकार ने हसन अली को यह काम दिया कि वह मरने वाले व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकलवा दे. इसकी एवज़ में अली को अकाउंट से निकली भारी रकम का कुछ हिस्सा अदा करने का वादा किया गया. तब अली ने यह सीखा कि किस तरह किसी अकाउंट का होल्डर न होते हुए भी अकाउंट से पैसे निकलवाए जा सकते हैं. फिर हसन अली सिंगापुर पहुंच गया, पर अकाउंट से पैसे फ्लो कराने के लिए उसके द्वारा की गई तिकड़मबाजी नाकाम हो गई.

सिंगापुर में इसकी मुलाक़ात कोलकाता के दो स्विस बैंक ऑपरेटरों से हुई. सिंगापुर भी टैक्स हेवन है, यहां भी स्विस बैंकों की तरह काला धन जमा किया जाता है. इसलिए यहां दुनिया भर के माफ़िया और हवाला ऑपरेटर आसानी से मिल जाते हैं. हसन अली जिन दो लोगों से मिला, उनमें से एक बिरला परिवार की प्रियंवदा बिरला का भाई काशीनाथ तपोरिया था तो दूसरा होटल का बिज़नेस करने वाले फिलिप आनंदराज था, जिसके रेस्टोरेंट कम होटल ज्यूरिक में हैं. माना जाता है कि इन लोगों के देश के कई बड़े राजनीतिज्ञों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं. अली की इनसे गहरी मित्रता हो गई. 2000 में वहां से लौटकर हसन अली पहली पत्नी महबूबा खान को तलाक़ देकर पुणे में दूसरी पत्नी रीमा के साथ रहने लगा, जो हॉर्स ट्रेनर फैजल अली की बहन है. घुड़सवारी का शौकीन हसन अली रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब में अपने घोड़े रखकर सिर्फ़ उनकी मेंटेनेंस का ख़र्च वहन करता था. बाद में कथित तौर पर इसके माने जाने वाले स्टड फार्म को इसने धोखाधड़ी से हड़प लिया. दरअसल, जिस जगह पर यह स्टड फार्म चलाता है, वह जगह सरकार ने भूमिहीन मज़दूरों के लिए दी थी, लेकिन उस पर किसी गुंडे ने क़ब्ज़ा कर लिया और फिर हसन अली ने वह जमीन उससे ख़रीद ली. पुणे में रहते हुए अली 10 घोड़ों, ट्यूलिप अपार्टमेंट के दो फ्लोर, आनंद दर्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट, दो मर्सीडीज कारों और एक पोर्स का मालिक हो गया. वह रेस में घोड़ों पर बहुत कम, लगभग 15,000 से लेकर एक लाख रुपये तक की ही बेट करता था, लेकिन उस वक़्त उसके अकाउंट में तक़रीबन 300 मिलियन रुपये थे.

हसन अली ख़ुद को स्क्रैप डीलर और स्टड फार्म व्यापारी बताता था, लेकिन जांच एजेंसियों को यह मालूम था कि इतने ज़्यादा पैसे इन व्यापारों से कमाए नहीं जा सकते. दरअसल, ये रुपये उन नेताओं के थे, जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट थे, जिन्हें हसन अली ऑपरेट करता था. दरअसल, हसन अली नाम ड्रॉप करने में माहिर है. तपोरिया और आनंदराज को अपना काला धंधा चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी. अली ने उन्हें विश्वास दिलाया कि रुपये का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि वह कई लोगों के स्विस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करता है. अली ने उनसे विदेशी बैंकों में पैसे रखने, निकालने और हड़पने के गुर सीखे और विदेशी बैंकों में पैसों के ट्रीटमेंट के काम का धंधा तगड़ा कर लिया. 1982 से 1985 तक इसके पास डेढ़ मिलियन रुपये थे. ये पैसे सिंगापुर के यूबीएस बैंक के अकाउंट में थे, जिसे एक विदेशी डॉक्टर पीटर विली की मदद से सऊदी अरब के हथियार व्यापारी और हवाला डीलर अदनान ख़शोगी की सिफ़ारिश पर खोला गया था. 1985 में हसन अली के सिंगापुर के यूबीएस अकाउंट में पास तीन सौ मिलियन रुपये आए, जो अदनान ख़शोगी के मैनहेटन बैंक अकाउंट से डॉक्टर विली की मदद से ट्रांसफर हुए. इसके बाद हसन अली का सिंगापुर स्थित यूबीएस अकाउंट 1986 में ज्यूरिक में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन 1997 में अली के इस अकाउंट को हथियार की ख़रीद-फरोख्त में इस्तेमाल होने के अंदेशे से बंद कर दिया गया. यह पैसा किसी रशियन माफ़िया का था. इस वक्त तक अदनान ख़शोगी लिट्टे को हथियार बेचता था. उनसे अली ने जो डील कराई, यह पैसा उसी का रिवॉर्ड था.

हसन अली गोल्फ का शौक़ीन है, वह ज्यूरिक, लंदन और दूसरे देशों में गोल्फ खेला करता था. इसके पास भारत के ही छह पासपोर्ट हुआ करते थे. यह जानकारी निश्चित रूप से देश के पासपोर्ट विभाग पर सवाल खड़ा करती है. 1993 में अली ने ब्रिटिश हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर विभाग की तरफ़ से इसे नया पासपोर्ट दे दिया गया. नया पासपोर्ट आने पर भी इसका पुराना पासपोर्ट निरस्त नहीं हुआ. एयरपोर्ट पर पासपोर्ट डिटेल्स लॉग करने वाले अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर इसने अपना नाम चढ़वाने से रोक लिया. इसी तरीक़े से यह अपने सभी पासपोर्ट निरस्त होने से रोक देता था. 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ, तब अमेरिका और दूसरे देशों ने उन सभी बैंक खातों के ट्रांजेक्शन बंद कर दिए, जिनके आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की आशंका थी. तब अली हसन के अकाउंट में अचानक मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा आने लगा. ये पैसे उसके अकाउंट में इसलिए आए, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका ने सभी बैंकों को फ्रीज करने का फ़रमान जारी कर दिया था. ऐसे में अली हवाला के ज़रिए एक देश से दूसरे देश तक लोगों के पैसे पहुंचाया करता था. 2006 में भारत में टैक्स हेवन बैंक और स्विस बैंक के साथ क्रिमिनल्स का राज हो गया. 2005 के अंत में एक स्विस बैंक हैदराबाद में खोला गया. यूबीएस बैंक को खोलने की इजाज़त बिना किसी ख़ास कार्रवाई के किसी भी मुल्क को नहीं है, क्योंकि यह बैंक सिर्फ स्लीज में डील करता है. 2006 में भारत में 3 और स्विस बैंक खुले. इस साल हसन अली के अकाउंट में पड़े 529 करोड़ रुपये 100 गुना बढ़कर 54,268 करोड़ रुपये तक पहुंच गए. फरवरी 2007 में पता चला कि अली ने पिछले पांच सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा है. इस तरह अली हसन के अकाउंट में 2001-02 में 529 करोड़, 2002-2003 में 5404 करोड़, 2003-04 में 2444 करोड़, 2005-06 में 10,495 करोड़ और 2006-07 में 54,268 करोड़ रुपये थे, जिसके लिए उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, लेकिन उसके इन कारनामों की पूरी फाइल इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में रिकार्ड हो रही थी. इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता कहते हैं कि हसन अली की शिकायत पर इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया. इन अधिकारियों ने हसन अली की इतनी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि उस पर कार्रवाई सिर्फ़ भारत में ही नहीं, 11 और देशों में भी होती. वित्त मंत्री की तरफ से ईडी के डायरेक्टर को फोन जाने पर ही इन तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया और फिर इनकी जगह उन अधिकारियों को लाया गया, जिनके नाम हसन अली ने दिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी हसन अली की सुनवाई के दौरान इस बात पर सवाल उठाया था कि इन तीन अधिकारियों को बुलाकर उनके हलफ़नामे लिखवाए जाएं कि उन्होंने कौन-कौन सी जानकारियां हसन अली के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड की हैं. हसन अली के छह देशों में कई और बैंक अकाउंट हैं, जिनमें कई नेताओं और नौकरशाहों के पैसे हैं. ये अकाउंट सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, लंदन, मॉरीशस, मेडागास्कर जैसे देशों में है. सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर हसन अली पर कार्रवाई की गई और इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हसन अली को रिमांड पर लेकर पूछताछ की. फिर भी कभी काग़ज़ी खानापूर्ति की वजह से तो कभी सही डॉक्यूमेंट मौजूद न होने की वजह से ईडी ने हसन अली पर ठीक तरह से कार्रवाई होने में रोड़ा लगाया. यह सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का दबाव ही था, जिसकी वजह से हसन अली की बर्बर सच्चाइयां सामने आ सकीं.

अब ईडी द्वारा की गई जांच पर अली ने अपनी ज़ुबान खोली है और बताया कि इस खेल में वह सिर्फ़ एक छोटी मछली है और इसके तार बड़े-बड़े नेताओं और अफसरशाहों से जुड़े हैं. फ़िलहाल महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का पैसा अपने पास होने का ख़ुलासा वह कर चुका है. इन मुख्यमंत्रियों के नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले से भी जुड़े हैं. हालांकि उनके नाम नहीं लिए गए हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि 1999 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार है और 1999 से ही हसन ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है. 8 बिलियन डॉलर के अकाउंट होल्डर हसन अली के हवाले से और भी ख़ुलासे होने हैं. दरअसल इस खेल का असली पर्दाफ़ाश तो अब ही होगा जब इस संगीन जुर्म से सने नामों की असलियत खुलकर सामने आएगी.

ritika@chauthiduniya.com

हसन अली की शिकायत पर इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया. इन अधिकारियों ने हसन अली की इतनी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि उस पर कार्रवाई सिर्फ़ भारत में ही नहीं, 11 और देशों में भी होती. वित्त मंत्री की तरफ़ से ईडी के डायरेक्टर को फोन जाने पर ही इन तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया और फिर इनकी जगह उन अधिकारियों को लाया गया, जिनके नाम हसन अली ने दिए

-विश्वबंधु गुप्ता

(इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर)

पत्नी के साथ हसन अली

हसन अली ख़ान

काशीनाथ तपोरिया

2006 में भारत में 3 और स्विस बैंक खुले. इस साल हसन अली के अकाउंट में पड़े 529 करोड़ रुपये 100 गुना बढ़कर 54,268 करोड़ रुपये तक पहुंच गए. फरवरी 2007 में पता चला कि अली ने पिछले पांच सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा है. इस तरह अली हसन के अकाउंट में 2001-02 में 529 करोड़, 2002-2003 में 5404 करोड़, 2003-04 में 2444 करोड़, 2005-06 में 10,495 करोड़ और 2006-07 में 54,268 करोड़ रुपये थे, जिसके लिए उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, लेकिन उसके इन कारनामों की पूरी फाइल इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में रिकार्ड हो रही थी.

माकपा ने 46 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं. वहीं मुस्लिम प्रत्याशियों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है. पार्टी ने तीन बाहुबलियों माजिद मास्टर, लक्ष्मण सेठ और तपन घोष को टिकट नहीं दिए.

पश्चिम बंगाल

नया इतिहास गढ़ने की तैयारी

बिमल राय

चुनावी मौसम में मुद्दों का क़ब्रिस्तान खोद डालने का रिवाज नया नहीं है और जब मुक़ाबला ऐतिहासिक रूप से कांटे का हो तो उन मुर्दों के कंकाल से विरोधियों को डराने की कोशिश भी होती रही है. पश्चिम बंगाल में भी 17 सालों से दफ़न एक मामले में ममता के ख़िलाफ़ जारी वारंट प्रकट हुआ है. एक माकपा नेता ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, क्योंकि आयोग के डंडे से डरकर सभी पुराने वारंट तामील किए जा रहे हैं और इसकी चपेट में जब माकपा के कई नेता आ चुके हैं तो ममता क्यों बची रहें. 1994 में ममता ने बरासात के डीएम कार्यालय पर धावा बोला था. 13 अप्रैल, 1999 को आरोपपत्र दाख़िल हुआ और 11 नवंबर, 2005 में वारंट जारी हुआ. तबसे ममता दो बार सांसद बनीं, पर वारंट सोता रहा और क़ानून की नज़र में वह भगोड़ा हैं. यह मामला उठा तो तृणमूल नेताओं ने गिरफ़्तार करने की चुनौती दी, पर माकपा ने जोश में होश नहीं खोया और मुख्यमंत्री ने इस मामले में आगे कार्रवाई न करने का फ़ैसला किया है.

इससे पता चलता है कि माकपा ने अपनी भूलों से सीख ली है और वह सधी रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी है. हर बार की तरह उसने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की और कुल 294 में से 292 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें 149 नए चेहरे हैं. 9 मंत्रियों को बेटिकट होना पड़ा. इनमें पर्यटन मंत्री मानव मुखर्जी, स्कूल शिक्षा मंत्री पार्थ दे, पिछड़ा वर्ग मंत्री जोगेश बर्मन (माकपा), जल संसाधन मंत्री नंद गोपाल भट्टाचार्य (माकपा), सहकारिता मंत्री रबीन घोष (फारवर्ड ब्लाक), बंकिम घोष शामिल हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों एवं सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहे वाममोर्चे को लगा कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे इन मंत्रियों को टिकट न देने से मतदाताओं में कुछ सकारात्मक संकेत जा सकता है. नए चेहरे लाने के पीछे एक मक़सद सत्ता विरोधी रुख़ की धार भी कुंद करना है.

माकपा ने 46 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं. वहीं मुस्लिम प्रत्याशियों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है. पार्टी ने तीन बाहुबलियों माजिद मास्टर, लक्ष्मण सेठ और तपन घोष को टिकट नहीं दिए. लक्ष्मण सेठ के कारण ही नंदीग्राम की आग भड़की थी. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मानव मुखर्जी सरकारी कोष से 22 हज़ार रुपये में एक जोड़ा चश्मा ख़रीद कर बदनाम हुए तो स्कूल शिक्षा मंत्री पार्थ दे को शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाकाम होने के कारण टिकट से हाथ धोना पड़ा. विपक्षी खेमे में कांग्रेस और तृणमूल के बीच तालमेल को लेकर कई दिनों तक सस्पेंस बना रहा. कांग्रेस द्रमुक जैसा रुख़ तृणमूल के लिए नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि यहां के हालात अलग थे. जब बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 2006 में कांग्रेस के पास तृणमूल से ज़्यादा सीटें थीं तो समझौता बराबरी का होना चाहिए. इस पर ममता ने लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों के परिणामों के ज़रिए बदले हालात की ओर उनका ध्यान दिलाया. ममता ने वह फ़ार्मूला भी नहीं लागू होने दिया कि राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा में ज़्यादा सीटें ले और विधानसभा में ज़्यादा सीटें दें. बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ बग़ावत हुई है. मसलन चितरंजन दास, सुभाषचंद बोस, विधान राय, अजय मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी और आख़िर में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुईं. इनमें विधान राय तो कांग्रेस में बने रहे, पर दूसरे नेताओं ने स्वराज्य फारवर्ड ब्लॉक, विप्लवी बांग्ला कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी पार्टियां बनाईं. लेकिन ममता ने पिछले 12 सालों में जितना जन समर्थन हासिल किया, उसका एक चौथाई भी उन टूटकर बने दलों को नहीं मिला. इस तरह ममता ने कांग्रेस को जूनियर पार्टनर बनने पर मजबूर किया है.

समझौते के बाद भी कांग्रेस को कुछ ख़ास हाथ नहीं लगा. उसे आसनसोल के पास की जामुड़िया के बदले उत्तर बंगाल की फासीदेवा सीट मिली, जबकि कोलकाता पोर्ट के बदले कैनिंग ईस्ट मिली. ममता ने कांग्रेस को पश्चिम मेदिनीपुर, गड़बेता, केशपुर, खड़गपुर ग्रामीण, बीनपुर, हुगली के गोघाट, पुरुलिया के पारा, बर्दवान, बर्दवान के आउसग्राम, बांकुड़ा के तालडांगा और कोतलपुर की 17 सीटें दी हैं. इन्हें माकपा का गढ़ माना जाता है. दार्जिलिंग, कालिपोंग और कर्सियांग की सीटें गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के दबदबे वाली हैं. तमाम भीतरी विरोध और बाधाओं के बावजूद कांग्रेस गठबंधन की अहमियत को समझ रही थी. गठबंधन न होने पर सबसे बड़ा झटका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानस भुइयां को लगता. मानस पश्चिम मिदनापुर की साबोंग सीट से चुनाव लड़ते हैं और पिछली बार महज़ 6000 वोटों के अंतर से ही उन्हें जीत हासिल हुई थी. अगर इस बार तिकोना संघर्ष होता तो मानस का हारना तय था. यही वजह थी कि मानस ने दीपा दासमुंशी और अधीर चौधरी के कट्टरपंथी खेमे को नज़रअंदाज़ करते हुए गठबंधन के लिए प्रणव मुखर्जी पर पूरा दबाव बनाया. जीतने पर उनका कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनना तय हो गया है.

तृणमूल से समझौते के बाद राहुल गांधी का युवा कांग्रेस का हवाई बैलून फट गया है. राहुल ने बंगाल का मैराथन दौरा किया था और वह युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने के लिए 30 युवा नेताओं की सूची भी मंगवा चुके थे, पर हाल में राज्य युवा कांग्रेस के चुनाव ने मज़ा किरकिरा कर दिया. राहुल की चहेती और गनी ख़ान चौधरी परिवार की मौसम बेनजीर नूर जीत गईं तो प्रियरंजन दासमुंशी की पत्नी दीपा का खेमा भड़क उठा. एक चर्चा ममता के चुनाव न लड़ने को लेकर भी है. इश्तहारों में उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, लेकिन दो माह पहले आए एक बयान कि प्रणव मुखर्जी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, की वजह से इस चर्चा ने जोर पकड़ा. ऐसा लगता है कि ममता सोनिया गांधी की तरह किंगमेकर या त्यागमूर्ति बनना चाहती हैं. दूसरा पेंच रेल मंत्रालय को लेकर है. तृणमूल में ऐसा कोई वरिष्ठ नेता नहीं दिखता, जो रेलमंत्री की कुर्सी में फिट हो सके. ममता ने रेलवे के लिए इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि मंत्रालय को अपने खाते में रखना ज़रूरी हो गया है. वैसे ममता के अगले रुख़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. हालांकि वह अगर सीधे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के ख़िलाफ़ खड़ी होतीं तो नज़ारा कुछ और होता. बुद्धदेव की यादवपुर सीट जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, उस पर तृणमूल का क़ब्ज़ा है. चाय की दुकानों पर राजनीतिक चर्चा के दौरान मज़ाकिया लहजे में एक बात कही जाती थी कि तृणमूल के ज़्यादातर बड़े नेता तो सांसद बन गए, पर सरकार बनने के बाद ममता मंत्री बनाने लायक़ चेहरे कहां से लाएंगी? उन लोगों को ममता की उम्मीदवार सूची से संतुष्ट हो जाना चाहिए. उनकी सूची में फिक्की के महासचिव अमित मित्रा हैं, तो 800 करोड़ के चारा घोटाले में लालू को जेल में डालने वाले सीबीआई के सुपरकॉप उपेन विश्वास भी हैं. जीतने पर अमित के वित्तमंत्री बनने की संभावना है और वह मौजूदा वित्तमंत्री असीम दासगुप्त के ख़िलाफ़ खड़े हैं. ममता ने फिल्मी तड़का भी लगाया है. 90 के दशक की सुंदरी देवश्री राय और हीरो चिरंजीत राजनीति के मैदान के ग्लैमरस चेहरे हैं. इसके अलावा उन्होंने सुल्तान सिंह और रछपाल सिंह जैसे पूर्व आईपीएस अधिकारियों को भी टिकट दिए हैं. पूर्व नौकरशाह मनीष गुप्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है.

छह चरणों में होने वाले इस चुनाव में पक्ष–विपक्ष के सिपाही मैदान में डटे हैं और चुनावी घोषणापत्रों के रूप में वादों की बौछारें भी हो चुकी हैं. पहले चरण का मतदान उत्तर बंगाल में है, इसलिए कोलकाता में चुनावी गरमी फ़िलहाल उतनी नहीं दिख रही है. वामपंथी क़ानून की नज़र में ममता भले ही भगोड़ा हों, मगर इस बार की राजनीतिक जंग में वह वामपंथियों को बंगाल से भगाने में जी–जान से जुट गई हैं और बंगाल नया इतिहास गढ़ने के मुहाने पर खड़ा है.

feedback@chauthiduniya.com

ममता का 200 दिनों का लक्ष्य

- कोलकाता को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना.
- 10 मेडिकल कॉलेज और माटुआ विश्वविद्यालय बनाना.
- मदरसे, मुस्लिम विश्वविद्यालय और हिंदी स्कूल खोलना.
- दार्जिलिंग और जंगल महल के लिए विशेष विकास योजना.
- कोलकाता शेयर बाज़ार को फिर चालू करना.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बंद कारखानों को फिर चालू करना, नए कारखाने खोलना.
- औद्योगिक शहरों की चेन बनाना और 300 नए आईआईटी खोलना.
- पर्यटन का विकास, दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड और दीघा को गोवा जैसा बनाना.
- हर अनुमंडल में विकसित अस्पताल खोलना, आयुर्वेदिक और हर्बल दवा उद्योग में नई जान फूंकना.
- लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए सिगल विंडो भुगतान प्रणाली, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में रोज़गार पैदा करना, राज्य के कर ढांचे को तार्किक बनाना.

ममता ने अपने घोषणापत्र में चाय और जूट उद्योग में नई जान फूंकने, कुछ नए हवाई अड्डों के निर्माण, कोलकाता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, इलाहाबाद-हल्दिया नदी राजमार्ग योजना शुरू करने और ऊर्जा क्षेत्र के विकास जैसे वादे शामिल किए हैं.

हिंदीभाषी प्रत्याशी हाशिए पर

राम प्यारे राम

कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना ज़िले के उपनगरों, आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज को मिलाकर बने शिल्पांचल, सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्रों में हिंदीभाषी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. पंचायतों और नगरपालिकाओं में तो हिंदीभाषियों के प्रतिनिधित्व को लेकर शिकायतें कम हैं, पर आबादी के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. राज्य सरकार में हिंदीभाषियों की भागीदारी न के बराबर दिखती रही है. हालांकि 1977 से पहले ऐसे हालात नहीं थे. कांग्रेसी शासन में विधानचंद राय सरकार में हिंदीभाषी समुदाय के ईश्वरदास जालान को स्थानीय स्वशासन और क़ानून मंत्री बनाया गया था. उसके बाद कांग्रेस की ही सिद्धार्थ शंकर राय सरकार में रामकृष्ण सरावगी राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए थे. 1977 में वाममोर्चा के सत्ता में आने के बाद से किसी हिंदीभाषी को मंत्रालय में जगह नहीं मिल सकी. हिंदीभाषियों का मुद्दा कोलकाता पोर्ट सीट तृणमूल को देने से उठा है. कवितीर्थ विधानसभा सीट पर राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम प्यारे राम 6 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. परिसीमन के बाद उनकी सीट कोलकाता पोर्ट में समा गई है. कांग्रेस यह सीट मांग रही थी, पर ममता ने इसके बदले कैनिंग ईस्ट सीट दी है. चर्चा है कि ख़ुद प्रणव मुखर्जी ने राम प्यारे के लिए जोर नहीं लगाया.

विधानचंद्र और सिद्धार्थ शंकर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस एक हिंदीभाषी को मंत्रालय में शामिल कराकर अपनी राष्ट्रीय पहचान क़ायम रख सकती थी. राम प्यारे की जीत तय थी और सीनियर होने के नाते उन्हें मंत्री पद न देना काफी मुश्किल था. तो क्या इस गणित के कारण उनका पत्ता काटा गया? अगर राम प्यारे बग़ावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो तृणमूल को करारा जवाब मिल सकता है. समाजसेवी अभय प्रताप सिंह ने आशंका जताई कि अगर हिंदीभाषियों ने तृणमूल के ख़िलाफ़ वोट कर दिया तो माकपा के लिए राह आसान हो जाएगी. बिहारी समाज के संचालक मणि प्रसाद सिंह ने कहा कि राम प्यारे बैसे अकेले विधायक थे, जो बिना डरे हिंदीभाषियों के लिए लड़ते थे.

मीडिया के एक हलके में हिंदीभाषी नेता लगनदेव सिंह को बाहुबलियों की सूची में डाल दिया गया. सच तो यह है कि हिंदीभाषियों में लोकप्रिय और माकपा के अनुशासित नेता लगनदेव हावड़ा उत्तर सीट से चार बार विधायक रहे हैं. चौथी दुनिया से बातचीत में उन्होंने टिकट न मिलने पर खुले तौर पर तो नाराज़गी नहीं ज़ाहिर की, पर इलाक़े के हिंदीभाषियों में इसे लेकर भारी निराशा है. अगर इस निराशा ने वोटरों को तृणमूल की ओर जाने को मजबूर किया तो माकपा को तयशुदा जीत वाली सीट हारकर अपने फ़ैसले पर पछताना पड़ सकता है. सनद रहे कि अपने 35 साल के शासन में वाममोर्चे ने उन जैसे सीनियर विधायक को कभी मंत्री नहीं बनाया. जिस तरह ममता ने पिछले लोकसभा चुनावों में कोलकाता की सारी सीटों पर क़ब्ज़ा कर लिया, उसे देखते हुए हावड़ा में एक हिंदीभाषी प्रत्याशी के जीतने से पार्टी को बल मिलता. हालांकि माकपा ने कोलकाता की जोड़ासांको सीट पर लगनदेव की बहन जानकी सिंह को टिकट दिया है. भवानीपुर क्षेत्र में ही ममता का कालीघाट वाला घर आता है और यहां से माकपा ने नारायण जैन को खड़ा किया है, जबकि टीटागढ़ सीट से हिंदीभाषियों में लोकप्रिय डॉ. प्रवीण कुमार का भी टिकट काट दिया गया. ममता ने अपने चुनावी घोषणापत्र में हिंदीभाषी बहुल क्षेत्रों में हिंदी को दूसरी राजभाषा बनाने और अधिक से अधिक हिंदीभाषी स्कूल खोलने का ऐलान किया है. क्षत्रिय समाज, पश्चिम बंगाल के संरक्षक एवं वैसवाड़ा परिषद के अध्यक्ष दुर्गा दत्त सिंह उपेक्षा के लिए हिंदीभाषियों को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं. उनके मुताबिक़, हिंदीभाषी अपनी राजनीतिक ताक़त का सामूहिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. क्षत्रिय समाज से जुड़े दारोगा सिंह का कहना है कि हिंदीभाषी अपनी अपरिहार्यता साबित नहीं कर पा रहे हैं और इसका फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं.

निस्संदेह सत्तारूढ़ दल स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए हमेशा सबसे अधिक प्रयास करते हैं.

उत्तर प्रदेश

सत्ता के दावेदारों में घमासान

निर्मल रानी

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पूर्व ही राजनीतिक तापमान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सत्ता की दावेदारी करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतर कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है. सभी दल एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. इस वातावरण ने पूरे प्रदेश में अच्छा-ख़ासा तनाव पैदा कर दिया है. मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती किसी भी क़ीमत पर अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहतीं, परंतु ग़ैर बसपाई दल इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि किसी भी तरह इस बार मायावती को सत्ता से हटा कर ही दम लिया जाए. चूंकि सत्ता में बने रहना या सत्तासीन होना जनता के हाथों में है, इसलिए बसपा सहित सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. यदि सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी की बात छोड़ दें तो अन्य सभी विपक्षी दलों में इस बात की भी प्रतिस्पर्धा है कि प्रदेश में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में दरअसल असली दावेदार है कौन? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? और बसपा का विकल्प बनने की इसी दावेदारी को जताने के लिए प्रदेश में कई राजनीतिक दल इन दिनों धरना, प्रदर्शन और जुलूस आदि का आयोजन करने में जुट गए हैं.

निस्संदेह सत्तारूढ़ दल स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए हमेशा सबसे अधिक प्रयास करते हैं. विपक्ष के आरोपों और अपनी अकर्मण्यताओं एवं निष्क्रियताओं के चलते सत्तारूढ़ दल चूंकि चारों ओर से प्रहार झेल रहा होता है, इसलिए उसके समक्ष रक्षात्मक मुद्रा अपनाने की भी ज़बरदस्त चुनौती आ खड़ी होती है. इसके अतिरिक्त विपक्ष द्वारा बताई-गिनाई जाने वाली नाकामियों के जवाब में सत्ता पक्ष को अपनी उपलब्धियों को भी बढ़ा-चढ़ाकर जनता के समक्ष पेश करना होता है. सत्ता पक्ष अपने शासनकाल में जितनी भी लोक हितकारी एवं लोक लुभावनी योजनाएं कार्यान्वित करता है, उनका भी ब्योरा जनता को बढ़ा-चढ़ाकर दिया जाता है. इसके लिए सत्तारूढ़ दल सरकारी खज़ाने का भरपूर दुरुपयोग करके रेडियो, टेलीविज़न और स्थानीय-राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में भारी-भरकम विज्ञापन जारी करते हैं. लगभग सभी राज्यों की सरकारें यही करती हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार भी इस रणनीति का सहारा लेते हुए देखी जा सकती है. सरकारें भलीभांति यह जानती हैं कि चुनाव तिथि की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके बाद कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन जारी नहीं कर सकती, किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती, किसी नई योजना का उद्घाटन नहीं हो सकता और किसी अधिकारी का स्थानांतरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है. लिहाज़ा सत्तारूढ़ पार्टी आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही ये सारे काम कर डालती है. इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही नज़ारा देखा जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा आएदिन करोड़ों रुपये के विज्ञापन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई अन्य राज्यों के विभिन्न समाचारपत्रों को भी जारी किए जा रहे हैं. स्वर्गीय कांशीराम के जन्मदिन के बहाने भी राज्य सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है. इसके माध्यम से मायावती एक तीर से कई शिकार खेल रही हैं. सबसे पहले तो वह स्वयं को कांशीराम का उत्तराधिकारी साबित करना चाह रही हैं. दूसरे कांशीराम की स्मृति में निर्मित शहर, क़स्बे, पार्क और अन्य योजनाओं के बहाने वह अपने विकास कार्यों का भी ढिंढोरा पीट रही हैं. तीसरी बात वह यह भी प्रमाणित करना चाह रही हैं कि भीमराव अंबेडकर के दलित उत्थान के जिस मिशन को कांशीराम ने आगे बढ़ाया था, अब उसकी अगुवाई वह कर रही हैं. विज्ञापन भी उन्हीं समाचारपत्रों को जारी हो रहे हैं, जो निष्पक्ष मीडिया घराने के रूप में अपनी पहचान रखते हैं या सरकारी ढोल पीटने में माहिर हैं. जो समाचारपत्र किसी विपक्षी नेता से संबंध रखते हैं या ऐसी ख़बरें

प्रकाशित करते हैं, जो राज्य सरकार को नहीं भातीं, वे इन भारी-भरकम विज्ञापनों से वंचित हैं. पिछले दिनों रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश करते समय अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के लिए भी रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की. रेलवे संबंधी किसी भी योजना की घोषणा का श्रेय तो केंद्रीय रेल मंत्री को ही जाता है और यदि मान भी लिया जाए कि बसपा के सांसदों के प्रयासों से ही प्रदेश में रेलवे की कोई नई योजना आई है, तो भी अधिक से अधिक इसका श्रेय संयुक्त रूप से दोनों राजनीतिक दल या नेता ले सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार द्वारा मायावती का फोटो लगाकर नीले रंग का एक पूरे पेज का विज्ञापन इस प्रकार प्रकाशित किया गया, मानों मायावती स्वयं रेल मंत्री हों और उन्होंने ही उक्त योजनाएं प्रदेश के लिए घोषित की हों. पूरे विज्ञापन में कहीं भी न तो संप्रग सरकार को धन्यवाद दिया गया और न ममता बनर्जी या उनकी तृणमूल कांग्रेस को.

जहां मायावती इस समय अपनी पूरी ताकत नई-नई योजनाओं की घोषणा और उन्हें प्रचारित करने में लगा रही हैं, वहीं विपक्षी दलों में भी इस बात की होड़ लगी हुई है कि वे किस तरह स्वयं को मायावती के विकल्प के रूप में पेश करें. इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी प्रदेश में कभी पहले स्थान पर थी, जो मायावती के सत्ता में आने के बाद मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में चली गई, लेकिन गत संसदीय चुनावों में कांग्रेस ने राहुल गांधी द्वारा किए गए तूफ़ानी दौरों के परिणामस्वरूप 22 लोकसभा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की राज्य में नंबर दो होने की दावेदारी को सीधी चुनौती दे डाली. समाजवादी पार्टी के लिए सबसे चिंताजनक स्थिति उस समय उत्पन्न हुई, जब गत वर्ष फ़िरोज़ाबाद लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव की बहू एवं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर से चुनाव हार गईं. सपा को साफ़ तौर पर लगने लगा कि कांग्रेस प्रदेश में बढ़त लेने की मुद्रा में आ चुकी है. इन्हीं ताज़ा राजनीतिक हालात के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी पुन: स्वयं को उस स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है कि उसे ही बसपा का विकल्प समझा जाए और उसकी नंबर दो की पोजीशन बरक़रार रहे. पिछले दिनों समाजवादी पार्टी द्वारा राज्य में तीन दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता गिरफ़्तार हुए. कई स्थानों पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए ख़ूब लाठियां भांजी गईं. इस आंदोलन के माध्यम से सपा ने प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि मायावती सरकार अराजकता की प्रतीक है. उसने कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के प्रति अपनी बेचारगी का इज़हार भी किया. दूसरी ओर मायावती ने पुन: प्रदर्शन करने पर ऐसी ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. सपा जहां विरोध का बिगुल ऊंचे स्वर में बजाने की तैयारी कर रही है, वहीं बसपा ऐसे किन्हीं प्रयासों को कुचलने की मुद्रा में नज़र आ रही है.

जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरीक़े अपना रही है. कभी वरुण गांधी की शादी धार्मिक तौर-तरीक़े से शंकराचार्य के आश्रम में कराकर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि फ़ायर ब्रांड भाजपा सांसद वरुण पूर्णतया धार्मिक हैं और वैदिक रीति-रिवाजों को मानने वाले हैं. तो कभी वरुण मतदाताओं को विवाह भोज देकर लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं. भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है. भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर दिए गए बयान को भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है, लेकिन हक़ीक़त तो यही है कि भाजपा अपने तमाम प्रयासों एवं रणनीतियों के बावजूद अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वह राज्य में नंबर दो होने की पोजीशन तक स्वयं को पहुंचा सके. प्रदेश में छिड़े इस सत्ता संघर्ष में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए न जाने कितनी रणनीतियां अपनाई जाएंगी, कहा नहीं जा सकता. चुनाव घोषणा होने से पूर्व यदि कुछ नए राजनीतिक समीकरण सामने आएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

The Thandaiwalas Since 1924
SINCE 1924
मिश्राम्बु®
Mishrambu®
AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY

प्रीमियम
ठंडाई
www.mishrambu.com
9792445544 / 9839057755

तमिलनाडु की जनता मजबूर है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचारियों में से ही किसी एक को चुनना है, उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं.

विधानसभा चुनाव

सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार

फ़िरदौस ख़ान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का मिज़ाज अलग है. यहां सियासी दल जनता को वोट के बदले क़ीमती वस्तुएं देने का लालच दे रहे हैं. जहां सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख और मुख्यमंत्री एम करुणानिधि जनता को करुणानिधि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सस्ता अनाज, हर ग़रीब परिवार को मुफ़्त रंगीन टीवी, छात्रों को लैपटॉप, महिलाओं को मंगलसूत्र के लिए सोना देने और विकास के नाम पर समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं, वहीं एआईएमडीएमके की महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने जनता को राशन कार्ड पर 20 किलो चावल मुफ़्त, छात्रों को लैपटॉप, महिलाओं को पंखे, मिक्सर, ग्राइंडर एवं मिनरल वाटर आदि देने का ऐलान किया है. अगर यही सब चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खुलेआम वोट ख़रीदे जाएंगे. इसी देश में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं, जहां चुनाव मुद्दों और जातियों के नाम पर लड़े जाते हैं. बेशक ये राज्य तमिलनाडु से बेहतर हैं. तमिलनाडु की जनता मजबूर है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचारियों में से ही किसी एक को चुनना है, इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं. आख़िर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उसे तमिलनाडु में बह रही भ्रष्टाचार की गंगा क्यों दिखाई नहीं दे रही है.

एक तरफ़ तमिलनाडु के नेता भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लडने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ ख़ुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में जुटे हैं. एम करुणानिधि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं. उनके क़रीबी नेता ए राजा 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले की भेंट चढ़कर जेल पहुंच गए हैं. राजा की मेहरबानी हासिल करने वाले स्वान टेलीकॉम के मालिक एवं डीबी रिएलिटी के प्रबंध निदेशक शाहिद उस्मान बलवा को भी सीबीआई गिरफ़्तार कर चुकी है. बलवा की डीबी रिएलिटी कंपनी द्वारा तमिल चैनल कलैगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये जारी किए जाने के मामले की सीबीआई जांच कर रही है और इसी सिलसिले में कनिमोझी से पूछताछ की गई. बताया जाता है कि कलैगनार टीवी में करुणानिधि की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि कनिमोझी की हिस्सेदारी 20 फ़ीसदी है. उनके बेटे एम के स्टालिन और एम के अलागिरी आपस में लड़ रहे हैं. जयललिता द्रमुक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हुए मज़बूत सरकार देने का वादा कर रही हैं. जयललिता यह मानकर चल रही हैं कि वाममोर्चे से लेकर एमडीएमके और विजयकांत के मज़बूत गठबंधन को चुनाव में कामयाबी मिलेगी. ए राजा की गिरफ़्तारी से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को बल मिला है. हालांकि जयललिता पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के कलर टीवी स्कैम, तांसी ज़मीन घोटाला और आमदनी से ज़्यादा जायदाद के मामले शामिल हैं. तमिलनाडु में एम करुणानिधि के नेतृत्व में द्रमुक–कांग्रेस गठबंधन, जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक –एमडीएमके– डीएमडीके गठबंधन और डॉ. रामदौस की अगुवाई में पट्टाली मक्कल काचि और भारतीय जनता पार्टी आदि चुनाव मैदान में हैं. सियासी दल नाराज़ पार्टियों को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम से अलग हुए मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम को लुभाने की ख़ातिर एम करुणानिधि ने अपनी अगुवाई वाले गठबंधन को विजयी बनाने के लिए सभी द्रविड़ दलों से एक मंच पर आने की अपील की है. एमडीएमके नेता वाइको के अन्ना द्रमुक से अलग होने के ऐलान के बाद उनके लिट्टे के प्रति झुकाव की तरफ़ इशारा करते हुए करुणानिधि ने कहा कि हमें टाइगर्स का स्वागत करना चाहिए. एमडीएमके विधानसभा की 234 में से 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसे घटाकर 30 कर दिया गया. इसके बाद एआईएमडीएमके ने इसमें और कटौती करते हुए इसे छह सीटों तक समेट दिया. विरोध करने पर यह सीटें बढ़ाकर नौ कर दी गईं. एमडीएमके ने अब 35 के बजाय 21 सीटें मांगी, लेकिन जयललिता नहीं मानीं. आख़िरकार वाइको ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया. पिछले चुनाव में करुणानिधि ने दो वादे किए थे, पहला दो रुपये किलो चावल और ऐसे हर घर को एक मुफ्त रंगीन टेलीविज़न देना, जिसके पास नहीं है. इन वादों ने असर दिखाया और करुणानिधि को कामयाबी मिली. करुणानिधि ने 50 और 60 के दशक में तमिल आंदोलनों का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए. उन्हें सिद्धांतवादी नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन अपनी संतानों के मोह में पड़कर उन्होंने तमाम आदर्शों को ताख़ पर रख दिया. द्रमुक के मंत्रियों को मलाईदार महकमे दिलाने के लिए केंद्र को समर्थन वापसी की धमकी देने और दूरसंचार मंत्रालय अपनी पार्टी के पास रखने की उनकी ज़िद ने उनके लालच को जगज़ाहिर कर दिया. सीटों को लेकर द्रमुक और कांग्रेस भी आमने–सामने आ गई थीं. यहां तक कि द्रमुक ने यूपीए सरकार से अपने मंत्रियों को हटाने तक का फ़ैसला कर लिया था. द्रमुक कांग्रेस को 60 सीटें देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा सीटें चाहिए थीं. आख़िर द्रमुक को कांग्रेस को 63 सीटें देनी पड़ीं. दरअसल कांग्रेस तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है. पिछले दिनों राहुल गांधी ने राज्य में कई दौरे किए और पार्टीजनों से ताक़त बढ़ाने को कहा था. पिछले डेढ़ दशक में कांग्रेस ने कभी इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा. वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करके 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. चुनाव में इस गठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. हालांकि इसके बाद कांग्रेस राज्य में तीसरे दर्जे की पार्टी बन गई, लेकिन वह अपने दम पर चुनाव लड़ने की हालत में नहीं है. द्रमुक सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर यूपीए से ख़फ़ा थी. वह सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन बाज़ी पलट गई. सोनिया गांधी के सख्त रुख़ के सामने द्रमुक की एक न चली. उसकी समझ में आ गया कि कांग्रेस को उसकी उतनी ज़रूरत नहीं, जितनी उसे कांग्रेस की है. तमिलनाडु में द्रमुक का सब कुछ दांव पर लगा है, जबकि कांग्रेस के पास उसका विकल्प मौजूद है. द्रमुक की सियासी दुश्मन जयललिता कांग्रेस से कह चुकी हैं कि वह द्रमुक के 18 सांसदों की फ़िक्र न करे, क्योंकि सरकार बचाने के लिए सांसद जुटाने की ज़िम्मेदारी उनकी है. मगर कांग्रेस शायद ही जयललिता पर भरोसा करे. जयललिता 1991 में कांग्रेस के साथ थीं. वर्ष 1998 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चाय पार्टी दी और भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया. उन्होंने 2001 में सत्ता हासिल की और भाजपा से नज़दीकियां भी क़ायम रखीं. उन्होंने कांग्रेस और सोनिया पर शब्द बाण चलाने शुरू कर दिए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस दिन सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, वह दिन देश के लिए बहुत बुरा होगा. मगर सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए. तमिलनाडु की सियासत में एक बार द्रमुक तो दूसरी बार अन्ना द्रमुक का शासन रहा है. द्रमुक ने कांग्रेस के समर्थन से लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है.

केरल टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में बवाल

केरल में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की सिफ़ारिश पर 25 युवा कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बवाल मच गया है. टिकट की दावेदारी जता रहे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बग़ावत कर दी है. कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के कारण राज्य की मुख्य जातियों और समुदायों के साथ किए गए वादों को नज़रअंदाज़ किया गया है. पूर्व मंत्री एवं पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता एम एम हसन कोच्चि के समीपवर्ती अलुवा से दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह अनवर सादात को टिकट दिया गया है. इसी तरह कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी टिकट कट गए हैं. किसी भी सियासी दल की मुहिम में युवा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, वे पार्टी कार्यक्रमों में दरियां बिछाने से लेकर भीड़ जुटाने तक का काम करते हैं, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है तो उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. कभी पार्टी में वरिष्ठता के नाम पर उनकी अनदेखी की जाती है तो कभी टिकटें बेचकर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है. अब देखना यह है कि राहुल गांधी पार्टी की इस परिपाटी को कितना बदल पाते हैं, हालांकि उन्होंने पहल तो की है.

कांग्रेस केरल में इस बार 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ये सीटें पिछले विधानसभा चुनाव से सात ज़्यादा हैं. पार्टी ने विपक्ष के नेता ओमेन चांडी और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चेन्नीथला सहित सभी शीर्ष नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है. केरल में माकपा के प्रदेश प्रमुख पिनराई विजयन की अगुवाई वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस के ओमन चांडी के नेतृत्व में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) आदि चुनाव मैदान में है. कांग्रेस–संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा प्रदेश सरकार की नाकामी, घटती लोकप्रियता, वाममोर्चे के बिखराव और निकाय चुनाव से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव तक में यूडीएफ के शानदार प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है. इसके अलावा वह प्रदेश की 24 फ़ीसदी मुस्लिम और 19 फ़ीसदी ईसाई आबादी के समर्थन को अपनी ताक़त मान रही है. केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गठबंधन को भी उसकी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है. वाम लोकतांत्रिक मोर्चा अपने भ्रष्टाचार रहित पांच साल के शासन की उपलब्धियों, जनहितैषी कार्यों और भू–माफ़िया के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर जनता से समर्थन मांग रहा है. चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ़ से मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. पिछले लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली यूडीएफ को मज़बूत दावेदार माना जा रहा है. लेकिन अच्युतानंदन के लिए हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि राज्य में माकपा सचिव पी विजयन और अच्युतानंदन में छत्तीस का आंकड़ा है. इसके कारण माकपा की प्रदेश इकाई ने उन्हें टिकट देने तक से मना कर दिया था. फ़िलहाल उन्हें पलक्कड़ ज़िले के मलमपुझा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है.

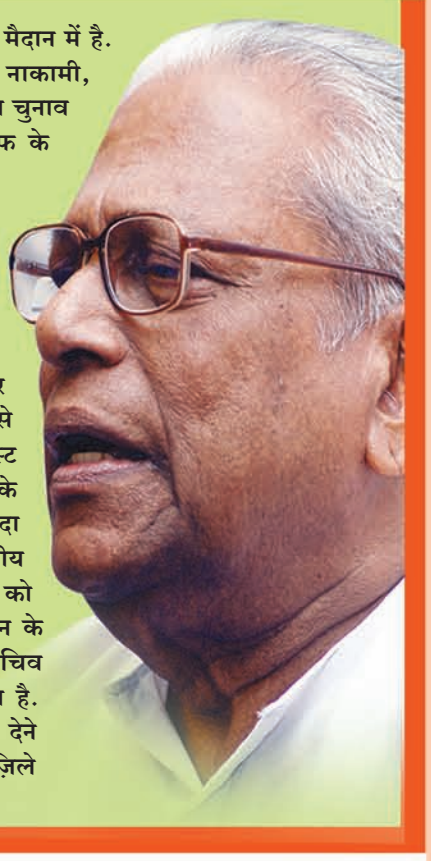

असम कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताक़त झोंकी

असम में जहां कांग्रेस सत्ता बरक़रार रखने के लिए चुनाव मुहिम में पूरी ताक़त झोंक देना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की रणनीति बनाने में जुटी है. यहां मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की अगुवाई वाला कांग्रेस–बोडो पीपुल्स फ्रंट गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी–असम गण परिषद का अनौपचारिक गठबंधन और बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाला ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि चुनाव मैदान में हैं. भाजपा के अगप नेताओं से मतभेद के कारण औपचारिक गठबंधन नहीं हो सका, लेकिन दोनों को ही एक–दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए दोनों ने ही आपसी तालमेल बनाए रखना बेहतर समझा. क़रीब तीन दर्जन सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. चुनावी रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उतारने का फ़ैसला किया है. चुनाव प्रचार अभियान की कमान राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली संभाल रहे हैं. राज्य में मुसलमानों की आबादी को देखते हुए पार्टी के मुस्लिम मुखौटे शाहनवाज़ हुसैन को भी चुनाव प्रचार की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. मारवाड़ी समाज के वोट हासिल करने के लिए पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष किरण माहेश्वरी और महासचिव धर्मेंद्र प्रधान भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी असम विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं. भाजपा का दावा है कि वह दो दर्जन सीटें तो जीत ही लेगी. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा उम्मीद असम से है, क्योंकि यहां उसके पास सांसद और विधायक दोनों हैं. पिछली बार भाजपा ने दस सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में उसके चार विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे.

कांग्रेस उल्फ़ा से शांति वार्ता, विकास और मज़बूत सरकार देने का वादा कर रही है. भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ से निबटने में सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बना रही है. असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और हिंसा एक संवेदनशील मुद्दा है. कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद इसे लेकर अपनी सियासी रोटियां सेंकती रही हैं. असम में बांग्लादेशियों को कांग्रेस के वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है. असम में जनता बाढ़, औद्योगिक विकास का अभाव और बेरोज़गारी आदि समस्याओं का सामना कर रही है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... देश और कांग्रेसी! ...धीर

भारत भूकंप के लिहाज़ से लगातार ज़्यादा संवेदनशील इसलिए भी होता जा रहा है, क्योंकि इसकी सब-कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया के अंदर घुसती जा रही है.

भारत में जापान से ज़्यादा

ख़तरनाक भूकंप आ सकते हैं

राजेश एस. कुमार

जापान में सुनामी से हुई तबाही पूरी दुनिया ने देखी. कुछ लोगों ने टेलीविज़न पर तो कुछ लोगों ने अपनी आंखों से. भारत में इस तरह के भयंकर मंज़र अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में इस तरह की तबाही नहीं आ सकती है. दरअसल हम लोग गफ़लत में जी रहे हैं. बिना किसी तैयारी के इस बात से बेफ़िक्र हैं कि भारत में इस तरह के प्रलंयकारी भूकंप और सुनामी आ ही नहीं सकते. सच्चाई तो यह है कि भारत में जापान से भयानक तबाही आ सकती है. जापान तो ख़ैर इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में माहिर हो चुका है, लेकिन भारत में तो इस तरह की आपातकाल स्थितियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतज़ाम भी नहीं हैं. जिस तरह से भारत में भूकंप जोन के इलाक़े बढ़ते जा रहे हैं, उससे तो साफ़ हो जाता है कि भारत किसी भी वक़्त जापान जैसी हालात से रूबरू हो सकता है. भारत के भूकंपीय जोन नक़्शे में भी देखे जा सकते हैं. इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मसले पर पिछले साल शिमला में हुई बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम एक टाइम बम पर बैठे हैं. हम बार-बार भले ही इस बात की दलील दें कि हमारी जापान से तुलना सही नहीं है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ और भूमंडलीय प्लेटों की स्थितियां यही बताती हैं कि हमारा देश कभी भी किसी बड़े भूकंप की चपेट में आ सकता है.

भारत भूकंप के लिहाज़ से लगातार ज़्यादा संवेदनशील इसलिए भी होता जा रहा है, क्योंकि इसकी सब-कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया के अंदर घुसती चली जा रही है. इससे जब भी सब-कॉन्टिनेंटल प्लेट का दबाव ऐशियन प्लेट पर बढ़ेगा तो नतीजा एक बड़े सैलाब के तौर पर दिखाई देगा. धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां-जहां मिलती हैं वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का ख़तरा ज़्यादा होता है.

भूकंप की आशंका के आधार पर देश को पांच जोन में बांटा गया है. नार्थ-ईस्ट के सभी राज्य, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन-5 में आते हैं. यह हिस्सा सबसे ज़्यादा संवेदनशील कहा जा सकता है. उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से और दिल्ली जोन-4 में आते हैं. इन्हें भी कम संवेदनशील नहीं कहा जा सकता है.

मध्य भारत अपेक्षाकृत कम ख़तरे वाले हिस्से जोन-3 में आता है, जबकि दक्षिण के ज़्यादातर हिस्से सीमित ख़तरे वाले जोन-2 में आते हैं, लेकिन यह एक मोटा वर्गीकरण है. दिल्ली में कुछ इलाक़े हैं, जो जोन-5 की तरह ख़तरे वाले हो सकते हैं. इस प्रकार दक्षिण राज्यों में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जो ज़ोन-4 या ज़ोन-5 जैसे ख़तरे वाले हो सकते हैं. दूसरे ज़ोन-5 में भी कुछ इलाक़े हो सकते हैं, जहां भूकंप का ख़तरा बहुत कम हो और वे ज़ोन-2 की तरह कम ख़तरे वाले हों. इस मामले में बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां लगभग सभी भूकंपीय ज़ोन आते हैं. इसकी जांच के लिए भूकंपीय माइक्रोजोनेशन की ज़रूरत होती है. माइक्रोजोनेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें भवनों के पास की मिट्टी को लेकर परीक्षण किया जाता है और इसका पता लगाया जाता है कि वहां भूकंप का ख़तरा कितना है.

हालांकि, भारत में तबाही लाने के लिए सिर्फ़ सब-कॉन्टिनेंटल प्लेट ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि भारत की परमाणु इकाइयां भी भारत को राख के ढेर में तब्दील करने के लिए काफ़ी हैं. अब ज़रा भारत की 20 परमाणु इकाइयों के बारे में भी सोचें. अगर भारत में तबाही का कारण ये परमाणु इकाइयां होती हैं तो इससे होने वाली तबाही दुनिया में किसी भी दूसरी जगह आई आपदा से ज़्यादा विनाशकारी होगी. भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदूकश क्षेत्र में भूकंप का सबसे ज़्यादा ख़तरा कश्मीर को होता है. हिंदूकश क्षेत्र में आए भूकंप का ख़तरा भले ही गुज़र गया हो, लेकिन इस महीने में एक के बाद एक आ रहे भूकंप चिंता का विषय हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मार्च महीने के 21 दिनों में अब तक भूकंप के 55 झटके लग चुके हैं, जबकि प्रतिमाह 25-30 भूकंप ही आते हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के भूकंप वैज्ञानिक डॉ. ए. के. शुक्ला के अनुसार इसकी वजह जापान में आया बड़ा भूकंप है. जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद छोटे भूकंप आते हैं. भूकंप विज्ञान केंद्र में पूरी दुनिया में आने वाले भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं. इस महीने आए 55 भूकंपों में सबसे ज़्यादा 11 मार्च को 22 झटके लगे हैं. इसी दिन जापान में 8.9 तीव्रता का भूकंप भी आया था. जहां तक भारत का प्रश्न है 19 मार्च को अंडमान निकोबार क्षेत्र में 4.8 तीव्रता का तथा इससे पहले 14 मार्च को चमोली में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था. डॉ. शुक्ला के अनुसार भारत के लिए अंडमान, कच्छ, पूर्वोत्तर, उत्तराखंड तथा कुछ हद तक हिंदूकश क्षेत्रों में आने वाले भूकंप संवेदनशील होते हैं. वैसे अगर हम भूकंप के कारणों की बात करें तो वैज्ञानिकों बताते हैं कि धरती या समुद्र के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण ये भूकंप आते हैं. अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर अंदर होती है. सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण कमज़ोर होती है. ऐसी स्थिति में जब अचानक चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है. एक अन्य प्रकार के भूकंप सतह से 100 से 650 किलोमीटर नीचे आते हैं. इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से द्रव रूप में होती हैं. हालांकि वहां किसी झटके या टक्कर की संभावना नहीं होती, लेकिन ये चट्टानें भारी दबाव में होती हैं. यदि इतनी गहराई में भूकंप आता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है. धरती की सतह से काफ़ी गहराई में उत्पन्न अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलीविया में रिकॉर्ड किया गया था. सतह से 600 किलोमीटर भीतर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप का ख़तरा बढ़ रहा है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत और तिब्बत एक-दूसरे की तरफ़ प्रति वर्ष दो सेंटीमीटर की गति से सरक रहे हैं. इस प्रक्रिया से हिमालय क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है. यही वजह है कि पिछले 200 वर्षों में हिमालय क्षेत्र में छह बड़े भूकंप आ चुके हैं. इनके मुताबिक़ इस दबाव को कम करने का प्रकृति के पास सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है और वह है भूकंप. इसलिए भूकंपों को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है, हां इतना ज़रूर है कि इनसे सावधान होकर जानमाल के नुक़सान को कम ज़रूर किया जा सकता है. हालांकि इस मामले में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली भारत में है. उपरोक्त हालात से इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि हम भी जापान की तरह भूकंप के बारूदी ढेर में बैठे हैं. लेकिन जापान और हममें सिर्फ़ इतना ही अंतर है कि जापान इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए लिए तैयार है और हम नहीं. समय चेतने का है, नहीं तो हम भी प्रकृति की इस विनाशलीला का शिकार कभी हो सकते हैं.

rajeshsy@chauthiduniya.com

भारत के भूकंपीय जोन

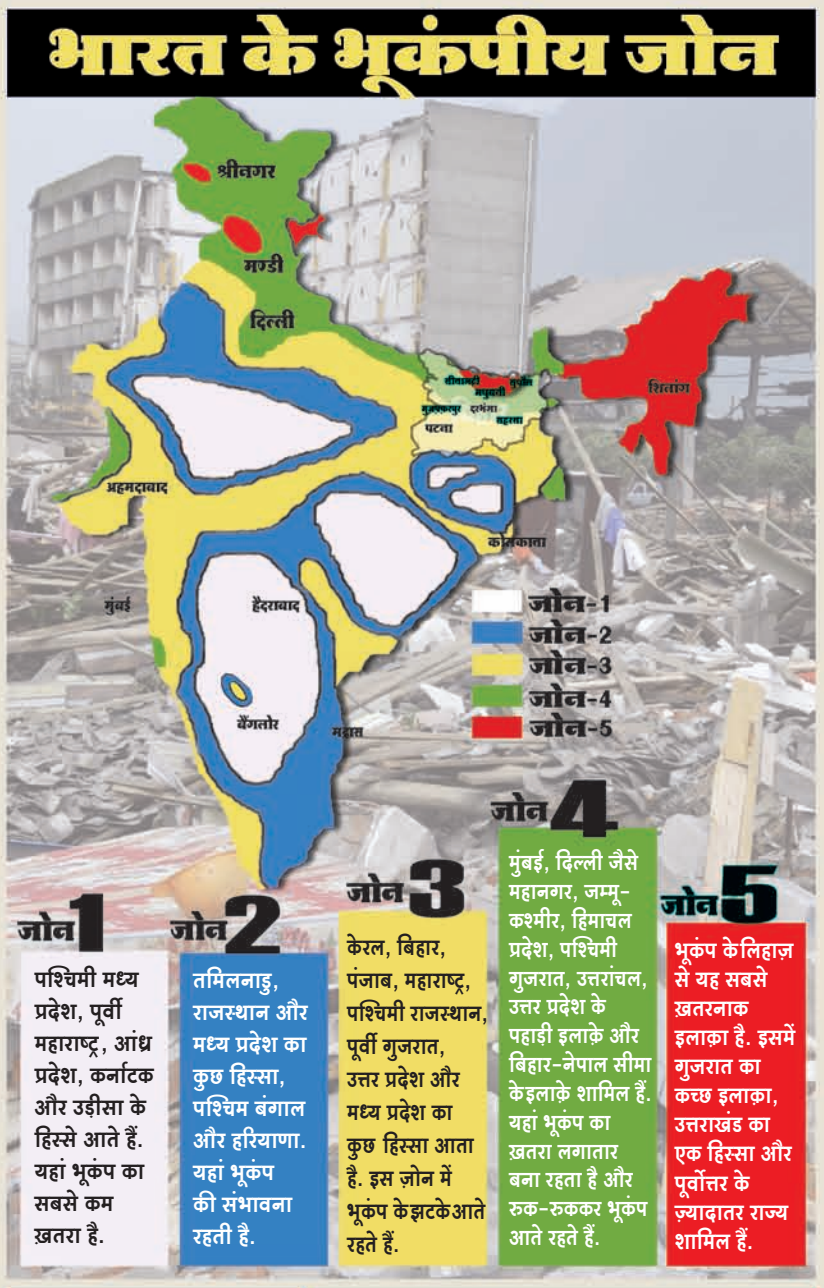

जोन 1
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के हिस्से आते हैं. यहां भूकंप का सबसे कम ख़तरा है.

जोन 2
तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा. यहां भूकंप की संभावना रहती है.

जोन 3
केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है. इस ज़ोन में भूकंप के झटके आते रहते हैं.

जोन 4
मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाक़े और बिहार-नेपाल सीमा के इलाक़े शामिल हैं. यहां भूकंप का ख़तरा लगातार बना रहता है और रुक-रुककर भूकंप आते रहते हैं.

जोन 5
भूकंप के लिहाज़ से यह सबसे ख़तरनाक इलाक़ा है. इसमें गुजरात का कच्छ इलाक़ा, उत्तराखंड का एक हिस्सा और पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्य शामिल हैं.

भारत के 10 बड़े भूकंप

1. शिलॉन्ग (1897)
2. कांगड़ा (1905)
3. बिहार-नेपाल सीमा (1934)
4. पूर्वोत्तर असम (1950)
5. सतपुड़ा (1938)
6. अंजार (1956)
7. कोयना (1967)
8. किल्लारी (1993)
9. जबलपुर (1997)
10. कच्छ (2001)

सुनामी
जापान बनाम भारत

मार्च में जापान में आए भूकंप और सुनामी में मरने वालों की आधिकारिक संख्या अब 10 हज़ार से ऊपर हो गई है. पुलिस के रिकॉर्ड में अब भी 17,440 लोग लापता और 2,775 घायल हैं. 2004 में आए सुनामी के बाद तटीय इलाक़ों में काफ़ी कम तादाद में लोग बचे हैं. ज्यादातर लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर बसा दिया गया है. 2004 में भारत में भी सुनामी ने अपना क़हर बरसाया था. 2004 में आए भूकंप के बाद सुनामी आई थी. उस समय भूकंप की तीव्रता 9.15 थी. उस सुनामी में तेरह देशों के क़रीब सवा दो लाख लोग मारे गए थे. इस लिहाज़ से भारत में सुनामी जापान से कम प्रलंयकारी नहीं थी.

दुनिया के अब तक के ख़तरनाक भूकंप

1. 11 मार्च 2011, जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर 9.0 की तीव्रता के भूकंप से सुनामी, 10,000 से अधिक लोगों की मौत.
2. 9 मई 2010, इंडोनेशिया में 7.2 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों की मौत.
3. 13 अप्रैल 2010, चीन में 6.9 की तीव्रता का भूकंप, 2500 की मौत.
4. 12 जनवरी 2010, हैती में 7.0 की तीव्रता का भूकंप, 2 लाख लोगों की मौत.
5. 30 सितंबर, 2009, इंडोनेशिया, सुमात्रा में 7.6 की तीव्रता का भूकंप, 1100 की मौत.
6. 29 सितंबर 2009, सैमोन द्वीप में 8.3 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों की मौत.
7. 10 अगस्त 2009, अंडमान निकोबार में 7.6 की तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत नहीं.
8. 6 अप्रैल, 2009, इटली के लैकिला शहर में 6.3 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों की मौत.
9. छह मार्च, 2007, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 70 लोगों की मौत.
10. 27 मई, 2006, इंडोनेशिया के जकार्ता में भूकंप, छह हज़ार लोग मारे गए.
11. आठ अक्टूबर, 2005, पाकिस्तान में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप, क़रीब 75 हज़ार लोग मारे गए.
12. 28 मार्च, 2005, इंडोनेशिया में 8.7 तीव्रता वाला भूकंप, लगभग 1300 लोग मारे गए.
13. 22 फ़रवरी, 2005, ईरान के केरमान प्रांत में लगभग 6.4 तीव्रता के आए भूकंप में लगभग 100 लोग मारे गए थे.
14. 26 दिसंबर,2004, 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न सूनामी ने एशिया में हज़ारों लोगों की जान गई.
15. 24 फ़रवरी, 2004, मोरक्को के तटीय इलाक़े में आए भूकंप ने 500 लोगों की जान ले ली थी.
16. 26 दिसंबर, 2003, दक्षिणी ईरान में आए भूकंप में 26 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
17. 21 मई 2003, अल्जीरिया में भूकंप आया, दो हज़ार लोगों की मौत
18. 24 फरवरी 2003, पश्चिमी चीन में भूकंप, 260 लोग मारे गए और 10 हज़ार से अधिक लोग बेघर.
19. 21 नवंबर 2002, पाकिस्तान के उत्तरी दियामीर ज़िले में भूकंप में 20 लोगों की मौत.
20. 25 मार्च 2002, अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी इलाक़े में 6 की तीव्रता का भूकंप, 800 से ज़्यादा लोग मरे.
21. 26 जनवरी 2001, गुजरात में 7.9 तीव्रता का भूकंप, तीस हज़ार लोग मारे गए.
22. 13 जनवरी 2001, अल साल्वाडोर में 7.6 तीव्रता का भूकंप, 700 से भी अधिक लोग मारे गए.
23. 6 अक्टूबर 2000, जापान में 7.1 तीव्रता का एक भूकंप, 30 लोग घायल हुए और कई लापता.
24. 21 सितंबर 1999, ताईवान में 7.6 तीव्रता का भूकंप, ढाई हज़ार लोग मारे गए.
25. 17 अगस्त 1999, तुर्की के इज़मिट और इस्तांबूल शहरों में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 17000 लोग मारे गए.
26. 29 मार्च 1999, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरकाशी और चमोली में दो भूकंप. 100 से अधिक लोग मारे गए.
27. 25 जनवरी 1999, कोलंबिया के आर्मेनिया शहर में 6.0 तीव्रता का भूकंप. क़रीब एक हज़ार लोग मारे गए.
28. 17 जुलाई 1998, न्यू पापुआ गिनी के उत्तरी-पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर आया भूकंप, एक हज़ार से अधिक मरे.
29. 26 जून 1998, तुर्की के दक्षिण-पश्चिम में अदना में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 144 लोग मारे गए.
30. 30 मई 1998, उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में एक बड़ा भूकंप, चार हज़ार लोग मारे गए.
31. फ़रवरी 1997, उत्तर-पश्चिमी ईरान में 5.5 तीव्रता का एक भूकंप, एक हज़ार लोग मारे गए.
32. 27 मई 1995, रूस के पूर्वी द्वीप सखालीन में 7.5 तीव्रता का भूकंप, दो हज़ार लोग मरे.
33. 17 जनवरी 1995, जापान के कोबे शहर में भूकंप, छह हज़ार चार सौ तीस लोग मारे गए.
34. 6 जून 1994, कोलंबिया में आया भूकंप, क़रीब एक हज़ार लोग मारे गए.
35. 30 सितंबर 1993, भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में आए भूकंप से क़रीब दस हज़ार लोगों की मौत.
36. 21 जून 1990, ईरान के उत्तरी राज्य गिलान में भूकंप, चालीस हज़ार से भी अधिक लोगों की मौत.
37. 17 अक्टूबर 1989, कैलिफ़ोर्निया में भूकंप, 68 लोग मारे गए.
38. 7 दिसंबर 1988, उत्तर-पश्चिमी आर्मेनिया में 6.9 तीव्रता का भूकंप, पच्चीस हज़ार लोगों की मौत.
39. 19 सितंबर 1985, मैक्सिको में भूकंप, दस हज़ार से अधिक लोग मारे गए.
40. 28 जुलाई 1976, चीन का तांगशान शहर में भूकंप, पांच लाख से अधिक लोग मारे गए.
41. 22 मार्च 1960, दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप चिली में आया. इसकी तीव्रता 9.5 दर्ज की गई.
42. 28 जून 1948, पश्चिमी जापान में पूर्वी चीनी समुद्र को केंद्र बनाकर भूकंप आया, तीन हज़ार से ज़्यादा लोग मरे.
43. 31 मई, 1935, क्वेटा और उसके आसपास के इलाक़ों में भूकंप, लगभग 35 हज़ार लोगों की जानें गईं.
44. 1 सितंबर 1923, जापान की राजधानी टोक्यो में आया ग्रेट कांटो भूकंप, 142,800 लोगों की मौत
45. 18 अप्रैल 1906, सैन फ्रांसिस्को में कई मिनट तक भूकंप के झटके आते रहे. तीन हज़ार लोग मारे गए.
46. 1 नवंबर 1755 पुर्तगाल में 8.7 की तीव्रता का भूकंप, 70,000 की मौत
47. 17 अगस्त 1668 टर्की में 8.0 की तीव्रता का भूकंप, 8000 की मौत
48. 23 जनवरी 1556 में चीन में 8.0 की तीव्रता का भूकंप, 830,000 की मौत
49. 9 अगस्त 1138, सीरिया में 230,000 की मौत
50. 22 दिसंबर 0856 में, ईरान के दमगान में 200,000 की मौत.

साधारण बीज में एक ख़ास जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक से प्रवेश कराकर बीटी बीज तैयार किए जाते हैं.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, उस भारत, जिसके निर्माण के लिए मैं जीवन भर काम करता रहा हूं, में प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो.

काले धन पर टिका भारतीय प्रजातंत्र

मेघनाद देसाई

पी वी नरसिम्हाराव के समय की एक बात मुझे हमेशा याद आती है. मैंने दो पत्रकारों को बात करते सुना था. एक ने दूसरे से कहा कि उसने शेयर बाज़ार घोटाले के एक आरोपी को प्रधानमंत्री के पास चार करोड़ रुपये ले जाते देखा था. दूसरे ने तपाक से कहा कि उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी छोटी रकम पर तो छींक भी नहीं मारेंगे. मुझे याद है कि इस बातचीत पर मुझे गुस्सा नहीं, बल्कि हंसी आई थी. आज हम उस समय से बहुत आगे आ गए हैं. हम सभी को याद है कि किस तरह राव सरकार के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों को भारी-भरकम रकम देकर ख़रीदा गया था.

अब आज के विकीलीक्स को देखें. आज एक सांसद की क़ीमत कुछ करोड़ से बढ़कर दस और बीस करोड़ रुपये हो गई है. अमर सिंह, जो कि इस पूरे मामले में भीतर के आदमी थे, ने कहा है कि इसमें एक सांसद की क़ीमत दस नहीं, बल्कि बीस करोड़ रुपये थी. मुझे उनकी इस बात पर पूरा विश्वास है. आज क्या क़ीमत है, यह सोचने का विषय है. क्या बिकने की क़ीमतों ने महंगाई के साथ अपने क़दम बढ़ाए हैं या फिर बढ़े हुए एम पी फंड के साथ, जिसे वित्त मंत्री ने बहुत ही उदारता के साथ बढ़ाया है? वैसे अगली अर्थव्यवस्था के सर्वे में इस बात का भी ख़ुलासा होना चाहिए कि घूसखोरी की वजह से राजनीतिक जीवन कितना फ़ायदेमंद हो गया है. मुझे लगता है कि इसमें अर्जित होने वाला फ़ायदा अर्थव्यवस्था के बाक़ी किसी भी क्षेत्र से अधिक ही निकलेगा. जिस तरह से राजनीतिक दलों के पास पैसा आता है, वह काले धन की खुली कहानी है. लेकिन इसे कुछ अर्थशास्त्रीय तर्कों से देखा जा सकता है कि आख़िर मामला है क्या? राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां प्रतिस्पर्धा साफ़-पाक होती है. अल्पाधिकार यहां का नियम है. बड़ी पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे धन और बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है. कांग्रेस ने तो बहुत ही कम शुल्क पर सदस्यता देने का चलन शुरू किया था, लेकिन इस धन से पार्टी नहीं चल सकती. बहुत ही कम राजनीतिक कंपनियों (पार्टियों) में ही स्पर्धा होती है. उनमें एंट्री बहुत ही कठिन और महंगी होती है. आप क्षेत्रीय जातीय पार्टियां भी बना सकते हैं, जैसे कि आरएलडी या आरजेडी. आपको बस चाहिए एक सधा हुआ

वोट बैंक. जैसे ही आपके पास दो या तीन एमपी आए नहीं कि आपका धंधा चल निकलता है.

एक एमपी होने का फ़ायदा आपके निकट संबंधियों और आपके परिवार को मिलता है, जो कि तमिलनाडु के एम करुणानिधि के मामले में कई पत्नियों के बहुत से बच्चों को भी मिलता है. लेकिन अगर आपने बाहरी लोगों को शामिल किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं. शायद ए राजा का उदाहरण फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा. कभीकभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा पूंजीपति पार्टी को बहुत सारा पैसा दे दे, ताकि उसे राज्यसभा का टिकट मिल जाए. ऐसा अभी भाजपा के एक मुख्यमंत्री को सरेआम कहते देखा गया, लेकिन हर बार की तरह उनकी बात को दूसरे अर्थों में लिया गया. बड़ी पार्टियों को बार-बार केंद्र या राज्यों में सत्ता जीतनी पड़ती है, ताकि पार्टी चलती रहे. लेकिन जब वे सत्तासीन हो जाती हैं तो उन्हें लूट का पैसा गठबंधन के उन सदस्यों के साथ बांटना पड़ता है, जो एटीएम मंत्रालयों की मांग करते हैं. लेकिन इतना कुछ होता है कि छोटी पार्टियों के एमपी, जो गठबंधन से बाहर होते हैं, को भी पटाया जा सकता है. इस तरह से एक पूरा राजनीतिक तंत्र ही काले धन को पैदा करता है और वितरित भी. यह सारा नगद पैसा होता है, जिस पर मुस्कराते हुए राष्ट्रपिता की तस्वीर होती है. आख़िर उन्हें याद करने का इससे बेहतर तरीक़ा तो हो ही नहीं सकता.

वैसे यह धन आता कहां से है? बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लाइसेंस और परमिट की एवज़ में पैसा लेने की प्रथा तब शुरू हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था की कमान पूरी तरह से राज्य के अंतर्गत कर ली थी. समाजवाद तो भारत की राजनीति का जीवन था, लेकिन देश में एक ही पार्टी का एकाधिकार था. कांग्रेस की हार के बाद दूसरी पार्टियों ने भी इस प्रथा को बिना वक़्त गंवाए सीख लिया. भाजपा गठबंधन की तहलका मामले में हुई किरकिरी कौन भुला सकता है. तब तक आर्थिक उदारवाद ने लाइसेंस और परमिट की क़ीमतें तो और बढ़ा दी थीं. यहां काम कर रहा था वह समाजवाद, जो भारतीयता से ओतप्रोत था. भारत को मास्को के सोने या अमेरिका के डॉलरों की ज़रूरत नहीं है. भारत के पास अपना अलग और बहुत बड़ा धन का ख़ज़ाना है, जिस पर देश का अद्वितीय राजतंत्र चल रहा है. अमर सिंह ने सही कहा.

feedback@chauthiduniya.com

बीटी बीज यानी किसानों की बर्बादी

संप्रग सरकार की जो प्रतिबद्धता किसान और खेती से जुड़े स्थानीय संसाधनों के प्रति होनी चाहिए, वह विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति दिखाई दे रही है. इस मानसिकता से उपजे हालात कालांतर में देश की बहुसंख्यक आबादी की आत्मनिर्भरता को परावलंबी बना देने के उपाय हैं. बीते साल फरवरी में जब पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीटी बैगन की खेती के ज़मीनी प्रयोगों को बंद करते हुए भरोसा जताया था कि जब तक इनके मानव स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षात्मक पहलुओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो जाती, उत्पादन को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी. इस भरोसे से यह उम्मीद जगी थी कि बीटी बीजों के सिलसिले में अब एकतरफा फ़ैसले नहीं लिए जाएंगे. इसके बावजूद गोपनीय ढंग से मक्का के संकर बीजों का प्रयोग बिहार में किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब इस वादाखिलाफी की ख़बर लगी तो उन्होंने सख्त आपत्ति जताते हुए केंद्रीय समिति में राज्य के प्रतिनिधि को शामिल करने की पैरवी भी की. नतीजतन पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार में बीटी मक्का के परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन यहां एक आशंका ज़रूर उठती है कि यह परीक्षण उन प्रदेशों में जारी रहेंगे, जहां कांग्रेस और संप्रग के सहयोगी दलों की सरकारें हैं. गुपचुप जारी इन प्रयोगों से पता चलता है कि मनमोहन सरकार की हालत विदेशी कंपनियों के आगे इतनी दयनीय है कि उसे जनता से किए वादे से मुकरना पड़ रहा है. नीतीश कुमार ने पर्यावरण मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर न केवल ऐतराज जताया, बल्कि एक व्यवहारिक पहलू सामने लाते हुए सलाह दी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की मंज़ूरी समिति में राज्य के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए. बिहार में बीटी मक्का और धारवाड़ में बीटी बैगन के प्रयोगों से पहले राज्य के किसी प्रतिनिधि को समिति में लेना ज़रूरी नहीं समझा गया. राज्य सरकार को प्रयोग की न सूचना दी गई और न ही ज़रूरी सावधानियां बरती गईं. भारत के कृषि और डेयरी उद्योग पर नियंत्रण करना अमेरिका की प्राथमिकताओं में प्रमुख है. इन बीजों की नाकामी साबित हो जाने के बावजूद इनके प्रयोगों का मक़सद है मोंसेंटो, माहिको बालमार्ट और सिंजेटा जैसी कंपनियों के कृषि बीज और कीटनाशकों के व्यापार को भारत में ज़बरन स्थापित करना. बिहार में मक्का बीजों की पृष्ठभूमि में मोंसेंटो ही थी. इसके पहले धारवाड़ में बीटी बैगन के बीजों के प्रयोग के साथ इसकी व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करने में माहिको का हाथ था. यहां तो ये प्रयोग

> साधारण बीज में एक ख़ास जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक से प्रवेश कराकर बीटी बीज तैयार किए जाते हैं. बीज निर्माता कंपनियों की ऐसी दलील है कि कीटाणु इन्हें भोजन नहीं बनाते और इनसे पैदावार अधिक होती है. देश की खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने की दृष्टि से जीएम खेती की बड़ी आबादी के चलते भारत को सख्त ज़रूरत है.

कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को लालच देकर कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर में चल रहे थे. जीएम बैगन पहली ऐसी सब्जी थी, जो भारत में ही नहीं, दुनिया में पहली मर्तबा प्रयोग में लाई जाती. इसके बाद एक-एक करके कुल 56 फ़सलें वर्ण संकर बीजों से उगाई जानी थीं. लेकिन बीटी बैगन खेती के देश भर में ज़बरदस्त विरोध के कारण पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसके प्रयोग एवं खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन राजनेताओं के चेहरे कितने दोमुंहे हैं, यह गुपचुप मक्का बीज प्रयोगों से पता चलता है.

दरअसल आनुवांशिक बीजों से खेती को बढ़ावा देने के लिए देश के शासन-प्रशासन को मजबूर होना पड़ रहा है. 2008 में जब परमाणु क़रार का हो-हल्ला संसद और संसद से बाहर चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कृषि मंत्री शरद पवार और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की तिगड़ी ने अमेरिका से एक ऐसा समझौता गुपचुप कर लिया था, जिस पर कतई बहस-चर्चा नहीं हुई. इसी समझौते के मद्देनज़र बीटी बैगन को बाज़ार का हिस्सा बनाने के लिए शरद पवार और जयराम रमेश ने देश के कई नगरों में जन सुनवाई के ज़रिए एक मुहिम तक चलाई थी, लेकिन जनता और स्वयंसेवी संगठनों के ज़बरदस्त विरोध के चलते राजनेताओं को इस जिद से तत्काल पीछे हटना पड़ा था.

साधारण बीज में एक ख़ास जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक से प्रवेश कराकर बीटी बीज तैयार किए जाते हैं. बीज निर्माता कंपनियों की ऐसी दलील है कि कीटाणु इन्हें भोजन नहीं बनाते और इनसे पैदावार अधिक होती है. देश की खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने की दृष्टि से जीएम खेती की बड़ी आबादी के चलते भारत को सख्त ज़रूरत है. लेकिन कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बीज आहार की दृष्टि से तो उत्तम हैं ही नहीं, स्थानीय और पारंपरिक फ़सलों के लिए भी ख़तरनाक हैं. राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रमेश भट्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर बीटी बैगन की खेती शुरू होती है तो इसके प्रभाव से बैगन की स्थानीय किस्म मट्टूगुल्ला से प्रभावित होकर लगभग समाप्त हो जाएगी.

इसके बावजूद हमारे देश की सरकार विदेशी कंपनियों के व्यापारिक हित साधने में लगी है. जबकि हम अपने ही देश में बीटी कपास के दुष्परिणाम आज तक भुगत रहे हैं. बीटी कपास के उत्पादन का सिलसिला 2002 में शुरू हुआ था. इस बीज की अब तक खपत लगभग दस हज़ार करोड़ रुपये की हो चुकी है. यदि यही धन किसानों के हाथों में होता तो देश के ढाई लाख किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती. ज़ाहिर है, यह धन विदेशी कंपनियों की तिजोरियों में गया और देश का अन्नदाता कंगाल हो गया. जीन रूपांतरित बीजों के इस्तेमाल में शर्त होती है कि यदि बीज ख़राब निकलते हैं तो प्रयोग करने वाली कंपनी को पर्याप्त मुआवज़ा देना होगा, लेकिन बिहार में इन बीजों से उत्पादित फ़सल जब कमज़ोर निकली तो कंपनी के प्रयोगकर्ताओं ने मुआवज़ा देने की जबावदेही से पल्ला झाड़ लिया. आख़िर में इस नुक़सान की भरपाई नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के खजाने से कराई. यानी बीटी बैगन से होने वाली कमाई पर तो विदेशी कंपनियों का पूरा अधिकार है, लेकिन हानि में कोई भागीदारी नहीं. क्या कंपनियों की इसी चालाकी से किसानों और देश के हित सधेंगे?

प्रमोद भार्गव
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

...तो कभी क्रांति हुई है और न कभी होने दी जाएगी.

कुमार, *ई मेल से*

संपादकीय अच्छा लगा

तोप मुकाबिल हो-बड़े संपादकों के छोटे सवाल बहुत अच्छा लगा. इसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ संपादकीय कहा जा सकता है. आपने ठीक कहा है कि बड़े-बड़े संपादकों ने भी यह पूछने की हिमाक़त नहीं की कि सरकार देश के ग़रीबों के साथ है या फिर उनके, जो अपना नाम दुनिया के खरबपतियों की लिस्ट में दर्ज कराना चाहते हैं. दूसरा यह कि क्या सरकार सिर्फ विकास दर ही देखेगी या महंगाई पर भी लगाम लगाने का प्रयास करेगी. प्रधानमंत्री को काला धन वापस लाने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, केवल खोखले वादों से काम नहीं चलने वाला. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस ग़लतफ़हमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए कि सरकार चाहे जो भी करे, जनता कुछ नहीं करेगी. जनता के पास केवल वोट की शक्ति ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह सड़कों पर भी उतर सकती है.

अरुण सरोहा, *दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली*

संत समाज और रामदेव

यह भारत है, यहां पैसे और राजनीति से सब कुछ संभव है. रामदेव के प्रभाव से संत समाज में जलन हो रही है. सही है कि हर व्यक्ति नाम कमाने के लिए लालायित रहता है. ख़ुद अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर पाए तो आरोप लगा दो, नाम हो जाएगा. अगर साथ में राजनीति का सहारा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या. अगर सरकार और उसके समर्थक संतों को लगता है तो वे क्यों नहीं रामदेव पर मुक़दमा करते. क्यों जांच नहीं कराते आरोपों की. वे सभी जानते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है.

प्रमोद जैन, *ई मेल से*

बेवजह का शोर

रामदेव आज जिस मुक़ाम पर जनमत को लाने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं इसमें सफल होंगे या नहीं, लेकिन सत्ता और उसके दलालों ने उनके विरुद्ध एक गोपनीय षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है. अखिल भारतीय संत समाज के शीर्ष संत भी इस षड्यंत्र में भागीदार हैं. आप शीघ्र ही रामदेव के विरुद्ध विभिन्न अदालतों से वारंट जारी होते हुए और शीर्ष अदालतों में जनहित याचिकाएं दाखिल होते पाएंगे. चोरों के इस समूह विलाप में बाबा का क्रांति आह्वान नाद दब जाएगा, क्योंकि भारत में न तो कभी क्रांति हुई है और न कभी होने दी जाएगी.

सर्वश्रेष्ठ पत्र

जनता का पहरेदार

बड़े संपादकों के छोटे सवाल शीर्षक से संतोष भारतीय का आलेख पढ़ा. उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े यानी भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ मीडिया के गिरते स्तर और दिशाहीनता को भारतीय जनमानस के समक्ष उजागर करके स्वयं और चौथी दुनिया की जवाबदेही एवं विश्वसनीयता को बहाल रखने का सराहनीय प्रयास किया है. आशा है, आपका अख़बार आगे भी जनहित की कसौटी पर खरा उतरेगा और जनता के पहरेदार की भूमिका का एहसास कराता रहेगा. आज मीडिया जनता के बजाय सरकार का पहरेदार और उससे भी ज़्यादा दावेदार बन गया है.

संजय पाठक, *ग्राम अहपुरा, ज़िला भोजपुर, बिहार.*

चौथी दुनिया

चौ चौके-छक्के समाचार के
थी थीम अलग है इसकी
दु दुरुह आरटीआई पर
नि नित्य ख़बर है मिलती
या याद दिलाता अधिकारों की
खरा मार्गदर्शन है मिलता
लाभ उठाते बहुतेरे इससे
इसीलिए सबको भाता है
चौथी दुनिया भीड़भाड़ से
अलग पहचान बनाता है.

कृष्ण कुमार उपाध्याय, *गांधी नगर, बस्ती, उत्तर प्रदेश*

सकारात्मक दृष्टिकोण

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चकाचौंध के सामने चौथी दुनिया का सकारात्मक दृष्टिकोण, संतुलित संपादन, सजीले पृष्ठ, सुंदर फोटोग्राफ और पाठकों की नब्ज़ को छूते विषय, वाह क्या संयोजन है! हिंदी साप्ताहिक अख़बारों के डूबते युग को ज़िंदगी प्रदान करना चौथी दुनिया का प्रयास है. इसमें कभी गिरावट न आने दीजिएगा.

मो. अकबर, *निर्माण नगर, अकोला, महाराष्ट्र*

सूचना

राजकमल प्रकाशन
नयी दिल्ली पटना इलाहाबाद

अब चौथी दुनिया में सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की तरफ़ से 700 रुपये की किताबें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी. पाठक पत्र में अपना पूरा नाम, पता एवं फ़ोन नंबर अवश्य लिखें.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

युवाओं को सड़क पर उतरना होगा

संतोष भारतीय

23 मार्च, 1931 की सुबह सात बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई. ये जांबाज़ स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे. इनकी आंखों में आज़ाद भारत का सपना था. एक ऐसा भारत, जो दुनिया भर में लोकतंत्र की एक मिसाल बनेगा. जनता को नेतृत्व देने वाले नेता सच्चे और ईमानदार होंगे. अस्सी साल के बाद यानी 23 मार्च, 2011 को आज़ाद भारत की संसद में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि सरकार को बचाने के लिए सांसदों की ख़रीद-बिक्री हुई या नहीं. सांसदों को पैसा किसने दिया. स्टिंग आपरेशन किसने किया. संसद की यह बहस हमें बताती है कि हम किस हद तक गिर चुके हैं.

भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से क्या हासिल हुआ. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वही कहा, जो पहले से कहते आ रहे थे कि न तो सरकार और न ही कांग्रेस की ओर से 2008 में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों के वोट ख़रीदे गए. संसद में नोट फॉर वोट का मामला फिर से इसलिए गरमाया, क्योंकि विकीलीक्स ने अमेरिकी राजनयिक के एक संदेश को सार्वजनिक कर दिया. संसद में न्यूक्लियर डील को लेकर विवाद चल रहा था. अमेरिकी सरकार चिंतित थी कि डील का क्या होगा. इस संदेश से पता चला कि कांग्रेस के एक नेता ने एक अमेरिकी राजनयिक को नोटों से भरा बैग दिखाया था और यह कहा कि इन पैसों से हम सांसदों का समर्थन ख़रीदने जा रहे हैं, सरकार नहीं गिरेगी. विकीलीक्स की प्रमाणिकता पर सवाल उठाना ग़लत होगा, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट द्वारा भेजे जा रहे संदेशों को हैक करके सार्वजनिक की गई है. दुनिया के किसी भी नेता या देश ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है.

क्या संसद सिर्फ़ तर्क देकर बहस जीतने का अड्डा बन गई है. क्या संसद में टेक्निकल और लीगल बिंदुओं पर बहस होगी या फिर देश के भविष्य के ख़तरे और चिंताओं पर विचार होगा. किसने स्टिंग किया, कौन मास्टर माइंड है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अमर सिंह की भूमिका क्या रही आदि सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं. देश की राजनीति को जो भी समझते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में सांसदों और विधायकों की ख़रीद-फरोख्त होती है. समयानुसार इसके रेट भी तय होते हैं. नरसिम्हाराव की सरकार के दौरान भी पैसे देकर सांसदों के वोट ख़रीदे गए थे. यह कोई नई बात नहीं है और देश की बदक़िस्मती यह है कि सांसदों की ख़रीद-फरोख्त की यह आख़िरी घटना भी नहीं है. यही सबसे गंभीर और ख़तरनाक मुद्दा है. क्या हमारे सांसदों का समर्थन ख़रीदने और बेचने की चीज बन गया है.

एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दूबे. भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है. बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर चौंका दिया कि पूरा स्टिंग आपरेशन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर किया गया. इस आरोप का भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिया, वह लोगों में विश्वास नहीं जगा सका. टीवी चैनलों पर पार्टी के नेता कमज़ोर दलील देते नज़र आए. एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी नोट पर वोट के मामले में ख़ुद ही फंस गई. संसद के अंदर कपिल सिब्बल और चिदंबरम ने जहां विपक्ष की दलीलों का करारा जवाब दिया, वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर दी. लालकृष्ण आडवाणी को लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का जन्मसिद्ध अधिकार सिर्फ़ उन्हीं का है, ऐसा कहकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष का मखौल बना दिया. प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर महंगा पड़ा. वैसे सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने तीखे प्रश्नों और आरोपों की झड़ी लगाने में कोई कमी नहीं की थी. संसद में बहस तो रोचक हुई, लेकिन मुद्दा शर्मसार करने वाला था.

इस कहानी का एक पहलू यह है कि दोनों ही तरफ़ से सांसदों ने अपनी-अपनी पार्टी के आदेश के ख़िलाफ़ जाकर वोट किए. कुल 51 सांसद ऐसे थे, जिन्होंने पार्टी के व्हिप को नहीं माना. ऐसा क्यों हुआ. क्या यह हमारी संसदीय प्रणाली के लिए चिंता का विषय नहीं है. अगर चर्चा ही करनी थी तो इस विषय पर चर्चा होती कि ऐसे सांसदों के साथ क्या किया जाए. झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने क्या किया. राजनीति में यह नैतिक पतन का सबूत है. लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चिंता होनी चाहिए थी. पार्टी के आलाकमानों और पार्टी के स्वार्थ से बंधे हमारे प्रतिनिधियों का क़द बौना हो गया है. यही वजह है कि ये सिर्फ़ निजी या पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करते हैं. नज़र उठाकर देखिए तो पता चलता है कि देश की परेशान जनता की सुध लेने वाला कोई नेता या पार्टी मौजूद ही नहीं है. इस मामले में मीडिया को भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा. मीडिया का काम राजनेताओं पर नज़र रखना है. हमारी जमात के लोगों ने राजनीतिज्ञों से इतना ज़्यादा मेलजोल बढ़ा लिया है कि पत्रकार भी उनके जैसे हो गए हैं. पत्रकारों ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं का प्रवक्ता बनने का काम शुरू कर दिया है. यही वजह है कि राजनेता बेलगाम हो गए हैं. अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस अंग्रेजी चैनल ने स्टिंग आपरेशन का वह टेप जनता से क्यों छुपाकर रखा. किसी पत्रिका ने बहस के दिन इस पूरे मामले को ट्विस्ट करने की क्यों कोशिश की.

> प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वही कहा, जो पहले से कहते आ रहे थे कि न तो सरकार और न ही कांग्रेस की ओर से 2008 में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों के वोट ख़रीदे गए. संसद में नोट फॉर वोट का मामला फिर से इसलिए गरमाया, क्योंकि विकीलीक्स ने अमेरिकी राजनयिक के एक संदेश को सार्वजनिक कर दिया. संसद में न्यूक्लियर डील को लेकर विवाद चल रहा था. अमेरिकी सरकार चिंतित थी कि डील का क्या होगा. इस संदेश से पता चला कि कांग्रेस के एक नेता ने एक अमेरिकी राजनयिक को नोटों से भरा बैग दिखाया था और यह कहा कि इन पैसों से हम सांसदों का समर्थन ख़रीदने जा रहे हैं, सरकार नहीं गिरेगी.

जब भगत सिंह को फांसी दी गई, तब वह 23 साल के थे. राजगुरु की उम्र 22 साल थी, सुखदेव 24 और अशफाक उल्लाह 27 साल के थे. वे नौजवान थे. उनकी आंखों में आज़ाद भारत का सपना था. वे देश की चिंता करते थे. यही वजह है कि हंसते-हंसते वे सूली पर चढ़ गए. आज के युवा शायद अफीम खाकर सो रहे हैं. कहां हैं देश के युवा संगठन और छात्र संगठन. चाहे वह विद्यार्थी परिषद हो, एनएसयूआई हो या फिर एसएफआई. इन संगठनों को अपनी-अपनी पार्टियों से अलग अपना एजेंडा तय करना होगा. बेहतर भविष्य के लिए सड़कों पर उतरना होगा. जब तक ये छात्र और युवा संगठन अपने राजनीतिक आकाओं के आदेशों का पालन करते रहेंगे, तब तक ये देश की मुख्यधारा में कोई सार्थक योगदान नहीं दे पाएंगे. राजनीतिक दलों ने अपनी साख खो दी है. जनता का भरोसा इतना कमज़ोर हो चुका है कि जो इन पार्टियों के समर्थन में बात करता है, वह भी नज़रों से गिर जाता है. भारत का भविष्य आज के युवाओं के हाथ में है. अच्छा होता कि जिस दिन संसद में सांसदों की ख़रीद-फरोख्त की चर्चा हो रही थी, उस दिन हमारे नौजवान काली पट्टी बांधकर पूरे देश में घूमते, आंदोलन करते. महाभारत की लड़ाई से हमें सीख लेनी चाहिए. महाभारत की लड़ाई की मुख्य वजह धृतराष्ट्र का मोह और अनैतिक नेतृत्व था. महाभारत की लड़ाई में कौरवों और पांडवों के वंश तो ख़त्म हुए ही, साथ ही हस्तिनापुर का भी पतन हो गया. कर्ण, भीष्म द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य जैसे विद्वान और ईमानदार लोग भी मूकदर्शक बनकर अधर्म का साथ देते रहे. यही वजह है कि महाभारत से हुए महाविनाश के लिए भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को भी ज़िम्मेदार माना जाता है. देश की स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है. कार्यपालिका और संसद से जनता की उम्मीद ख़त्म हो गई है, आख़िरी उम्मीद सिर्फ़ न्यायपालिका से बची है. युवाओं को समझना होगा कि अगर वे चुपचाप बैठे रह गए तो देश के विनाश में उनका योगदान भी इतिहास दर्ज करेगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

सरकारी भूमि पूजन का औचित्य

राम पुनियानी

पुलिस स्टेशनों, बैंकों एवं अन्य शासकीय-अर्द्ध शासकीय कार्यालयों एवं भवनों में हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें-मूर्तियां आदि लगी होना आम बात है. सरकारी बसों एवं अन्य वाहनों में भी देवी-देवताओं की तस्वीरें अथवा हिंदू धार्मिक प्रतीक लगे रहते हैं. सरकारी इमारतों, बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के अवसर पर हिंदू कर्मकांड किए जाते हैं. यह सब इतना आम हो गया है कि इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस मुद्दे पर कुछ प्रबुद्धजनों ने अपना विरोध दर्ज किया था और सरकार की धर्मनिरपेक्षता की नीति पर प्रश्नचिन्ह लगाए थे. पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्रीय कैबिनेट ने न केवल सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी ख़र्च पर कराए जाने के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया था, वरन् तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को यह सलाह भी दी थी कि वह राष्ट्रपति की हैसियत से मंदिर का उद्घाटन न करें. उस समय सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की तीर्थ स्थानों, मंदिरों आदि की यात्राएं नितांत निजी हुआ करती थीं और इन यात्राओं के दौरान वह मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे.

धीरे-धीरे समय बदला. आज राजनेताओं के बीच भगवान का आशीर्वाद पाने की प्रतियोगिता चल रही है. राजनेताओं की मंदिरों एवं बाबाओं के आश्रमों की यात्राओं का जमकर प्रचार होता है. सरकारी इमारतों के उद्घाटन के मौक़े पर ब्राह्मण उपस्थित रहते हैं. सरकारी परियोजनाओं के शिलान्यास के पहले भूमि पूजन किया जाता है और मंत्रोच्चारण कर ईश्वर से परियोजना का कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न कराने की प्रार्थना की जाती है. अभी हाल में राजेश सोलंकी नामक एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास समारोह के दौरान भूमि पूजन और मंत्रोच्चारण किए जाने को चुनौती दी. इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे. सोलंकी का तर्क था कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अतः राजकीय कार्यक्रमों में किसी धर्म विशेष के कर्मकांड नहीं किए जा सकते. ऐसा करना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचता है. सोलंकी ने यह तर्क भी दिया कि अदालत के भवन के शिलान्यास के अवसर पर भूमि पूजन और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण से न्याय पालिका की धर्मनिरपेक्ष छवि को आघात पहुंचा है.

सोलंकी की इस तार्किक और संवैधानिक याचिका को स्वीकार करने की बजाय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया. और तो और, याचिकाकर्ता पर बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने कहा कि

> अभी हाल में राजेश सोलंकी नामक एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास समारोह के दौरान भूमि पूजन और मंत्रोच्चारण किए जाने को चुनौती दी. इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे. सोलंकी का तर्क था कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अतः राजकीय कार्यक्रमों में किसी धर्म विशेष के कर्मकांड नहीं किए जा सकते. ऐसा करना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचता है.

धरती को इमारत के निर्माण के दौरान कष्ट होता है. भूमि पूजन के माध्यम से धरती से इस कष्ट के लिए क्षमा मांगी जाती है. भूमि पूजन के ज़रिए धरती से यह प्रार्थना भी की जाती है कि वह इमारत का भार सहर्ष वहन करे. भूमि पूजन करने से निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है. निर्णय में यह भी कहा गया है कि भूमि पूजन वसुधैव कुटुंबकम (पूरी धरती हमारा परिवार है) एवं सर्वे भवंतु सुखिन: (सब सुखी हों) जैसे हिंदू धर्म के मूल्यों के अनुरूप है. न्यायालय के ये सारे तर्क हास्यास्पद और बेबुनियाद हैं. निर्माण कार्य शुरू करने के पहले धरती की पूजा करना शुद्ध हिंदू अवधारणा है. दूसरे धर्मों के लोग यह नहीं करते. जैसे कि ईसाई धर्म में निर्माण शुरू करने के पहले पादरी द्वारा धरती पर पवित्र जल छिड़का जाता है. जहां तक नास्तिकों का सवाल है, निर्माण के संदर्भ में उनकी मुख्य चिंता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना होती है. शासकीय कार्यक्रमों में किसी धर्म विशेष के कर्मकांडों को किए जाने को उचित ठहराना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है. भारतीय संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह सभी धर्मों से दूरी बनाए रखेगा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा. एस आर बोम्मई के मामले में उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला भी यही कहता है. इस फ़ैसले के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखेगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और न ही राज्य की कोई धार्मिक पहचान होगी. यह सही है कि विभिन्न धर्मों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों को पूरा समाज एवं देश स्वीकार कर सकता है, परंतु यह बात धार्मिक कर्मकांडों पर लागू नहीं होती. यद्यपि धर्मों की मूल आत्मा उनके नैतिक मूल्य हैं, परंतु आमजनों की दृष्टि में कर्मकांड ही विभिन्न धर्मों के प्रतीक बन गए हैं. कर्मकांडों के मामले में तो धर्मों के भीतर भी अलग-अलग मत और विचार रहते हैं. कबीर, निजामुद्दीन औलिया एवं महात्मा गांधी जैसे संतों ने धर्मों के नैतिक पहलू पर जोर दिया. जहां तक धार्मिक कर्मकांडों, परंपराओं आदि का संबंध है, उनमें बहुत भिन्नताएं हैं. एक ही धर्म के अलग-अलग पंथों के कर्मकांडों, पूजा पद्धति आदि में भी अंतर रहता है. उच्च न्यायालय का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के भी विरुद्ध है. यह अनुच्छेद राज्य पर वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी डालता है. राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म के कर्मकांडों, परंपराओं, रीतियों आदि को बढ़ावा देना संविधान के विरुद्ध है. वैसे भी श्रद्धा और अंध श्रद्धा के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म होती है. श्रद्धा को अंध श्रद्धा का रूप लेते देर नहीं लगती और अंध श्रद्धा समाज को पिछड़ेपन एवं दकियानूसी सोच की ओर धकेलती है. जहां तक किसी इमारत के निर्माण का प्रश्न है, अगर संबंधित तकनीकी एवं भूगर्भीय मानकों का पालन नहीं किया जाएगा तो दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी. यही कारण है कि इमारतों के निर्माण के पूर्व कई अलग-अलग एजेंसियों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. अगर इन प्रावधानों का पालन किए बग़ैर इमारतें बनाई जाएंगी तो भूमि पूजन करने के बावजूद दुर्घटनाएं होंगी. हमारे न्यायालयों को इन संवैधानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए. अजीबोग़रीब तर्क देकर यह साबित करने की कोशिश करना हमारे न्यायालयों को शोभा नहीं देता कि किसी धर्म के कर्मकांडों और रूढ़ियों को राज्य द्वारा अपनाना उचित है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, उस भारत, जिसके निर्माण के लिए मैं जीवन भर काम करता रहा हूं, में प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो. राज्य को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होना ही होगा (हरिजन, 31 अगस्त, 1947) और धर्म किसी व्यक्ति की देशभक्ति का मानक नहीं हो सकता. वह तो व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच का व्यक्तिगत मसला है और उसका राजनीति या राज्य के मसलों से घालमेल नहीं होना चाहिए. पिछले कुछ दशकों से हिंदू धार्मिक परंपराएं एवं रीतियां राजकीय परंपराएं एवं रीतियां बनती जा रही हैं. इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की ज़रूरत है.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

कुछ जानकार इस तरह से समलैंगिकों के लिए अलग ब्रांड की शराब को मुनाफ़े की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानते.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई : कुछ ख़ास बातें

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक़ है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह क्या, कहां और कैसे कर रही है. इसके साथ ही हर नागरिक सरकार को चलाने के लिए टैक्स देता है, इसलिए भी उसे यह जानने का हक़ है कि उसका पैसा कहां ख़र्च किया जा रहा है. जनता द्वारा यह सब जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है. 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया. अनुच्छेद 19 के अनुसार, हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं, तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती. 2005 में देश की संसद ने एक क़ानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी.

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह

- सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके.
- किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके.
- किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जांच कर सके.
- किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके.
- किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके.

सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं ग़ैर सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाएं आदि इसमें शामिल हैं. पूर्णत: निजी संस्थाएं इस क़ानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी क़ानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है. (धारा–2(क) और (ज)

लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है, अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण या भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक शुल्क मांगने के ख़िलाफ़ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत की जा सकती है.

हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं. ये वे अधिकारी हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं. (धारा–5) लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह 30 दिनों के अंदर (कुछ मामलों में 45 दिनों तक) सूचना उपलब्ध कराए. (धारा–7(1)

अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा ग़लत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है. साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी.

लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे. धारा 6 (2)

सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क देना होगा (केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क तय किया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है, बीपीएल कार्डधारकों से सूचना मांगने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता. धारा 7(5)

दस्तावेज़ों की प्रति लेने के लिए भी शुल्क देना होगा. (केंद्र सरकार ने यह शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखा है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जाएगी. धारा 7(6)

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो ऐसे में उसका कर्तव्य है कि वह उस आवेदन को पांच दिनों के अंदर संबंधित विभाग को भेज दे और आवेदक को भी सूचित करे. ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी. धारा 6 (3)

लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है, अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण या भ्रम में डालने वाली या ग़लत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक शुल्क मांगने के ख़िलाफ़ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत की जा सकती है. लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है. जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, उनका विवरण सूचना के अधिकार क़ानून की धारा 8 में दिया गया है. लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो वह धारा 8 में मनाही के बावजूद दी जा सकती है. जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता.

यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है या धारा 8 का ग़लत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है. धारा 19 (1)

यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे संबंधित हो) के पास करनी होती है. धारा 19 (3)

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

रहस्य से पर्दा उठा

एक कहावत है कि कुत्ता आदमी से भी ज़्यादा वफादार होता है. ऐसे ही एक वफादार कुत्ते की मौत पर काफी समय से प्रश्नचिन्ह लगा हुआ था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जापान के सबसे मशहूर कुत्ते की दशकों पहले हुई मौत के कारणों का पता लगा लिया है. 1930 के दशक में हचिको नामक यह कुत्ता स्वामिभक्ति की मिसाल बन गया था, क्योंकि अपने मालिक की मौत के सालों बाद तक यह एक स्टेशन पर उनका इंतज़ार करता रहा था. पहले माना जा रहा था कि हचिको की मौत पेट में कबाब वाली सींक लग जाने से हुई थी, लेकिन अब उसकी मौत के रहस्य से पर्दा उठ गया है. बीबीसी के अनुसार, पिछले 75 सालों से हचिको जापान में स्वामिभक्ति की मिसाल बना हुआ है. बच्चों की किताबों में उसे एक आदर्श के रूप में पेश किया जाता रहा है. हचिको की बेमिसाल ज़िंदगी पर दो फिल्में भी बनाई गई हैं. टोक्यो के शिबूया स्टेशन के बाहर लगी उसकी मूर्ति बेहद लोकप्रिय है और दशकों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. वह शिबूया स्टेशन के बाहर उसी जगह पर हचिको हर शाम अपने मालिक का इंतज़ार करता था. उसकी यह दिनचर्या सालों से जारी थी, लेकिन एक दिन दफ्तर में हचिको के मालिक की मौत हो गई और वह लौटकर नहीं आए. हचिको कई सालों

तक इसी शिबूया स्टेशन के बाहर ठीक उसी तरह अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा, जैसे पहले किया करता था. अपने मालिक के इंतज़ार का उसका सिलसिला तभी थमा, जब 1935 में उसकी मौत हो गई. हचिको के मरने के बाद उसके पार्थिव शरीर को एक संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया.

माना जाता है कि खाने-पीने का सामान बेचने वाले कुछ स्थानीय फेरीवालों ने हचिको की हालत पर तरस खाकर दयाभाव से उसकी हत्या कर दी होगी. हचिको के पेट में कबाब सेंकने वाली सींक मिली थी. इस आधार पर एक अनुमान यह भी लगाया गया था कि उसने जल्दी-जल्दी मांस खाते वक़्त सींक भी निगल ली होगी और उसी से लगी अंदरूनी चोट की वजह से उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन अब पशु चिकित्सकों ने हचिको के पार्थिव अवशेष की कई बार जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हचिको ने कबाब सेंकने वाली चार सींकें तो वाक़ई निगल ली थीं, लेकिन उनसे उसे कोई नुक़सान नहीं पहुंचा था. यानी हचिको की मौत लोहे की सींक़ों की वजह से नहीं हुई थी. डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस स्वामिभक्त कुत्ते की मौत कैंसर या पेट में कीड़े पड़ने से हुई थी. ख़ैर कुछ भी हो, हचिको की कहानी से सबक तो लिया ही जा सकता है.

बाज़ार में अब गे बियर

ख़ूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार...यह पंच अब सिर्फ़ आप ही नहीं, बल्कि समलैंगिक भी मार सकते हैं. आस्ट्रेलिया की एक प्रमुख शराब निर्माता कंपनी मेक्सिकन ब्रेबरी ने दुनिया में पहली बार समलैंगिकों के लिए ख़ास बियर बाज़ार में उतारी है. समलैंगिकों के लिए एक ख़ास ब्रांड की बियर उतारे जाने को लेकर जानकारों ने अलग–अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ जानकार इस तरह से समलैंगिकों के लिए अलग ब्रांड की शराब को मुनाफ़े की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानते. समलैंगिकों के लिए बार संचालित करने वाले ब्रिस्बेन के एलजीबीटी समुदाय के सदस्य नील मैक्लुकास ने कहा, समलैंगिकों के लिए ख़ास शराब! कभी नहीं. इसका मतलब है कि आप समलैंगिकों को हुक्म दें कि वे क्या पिएं और क्या न पिएं. उन्होंने कहा, मैं यह नहीं मान सकता कि समलैंगिकों के लिए बनी इस ख़ास बियर को पीने से कोई मर्द मारा जाएगा. बात थोड़ी सी हास्यास्पद ज़रूर है, लेकिन इससे समलैंगिकता अभियान से जुड़े कुछ लोगों को एक नया मुद्दा मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

किसी संदेश या संपर्क सूत्र के ज़रिए आपको अपना आर्थिक निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा. अपने कामकाज में कुछ दूरगामी और लाभकारी प्रोजेक्ट शामिल करने का उतावलापन रहेगा.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

व्यापारिक मामलों में कार्यदक्षता, उच्चस्तरीय क्षमता और रचनात्मक सोच अपनाने की ज़रूरत है. भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल करने की ज़रूरत है. व्यवसायिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में स्थिरता के कुछ नए संकेत मिल रहे हैं.

मिथुन 21 मई से 20 जून

कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको तरकीब का सहारा देकर सक्रिय बना देगा और कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिल जाएंगे. इस हफ्ते की शुरुआत कुछ धीमी गति से हो रही है. जिस योजना को आप अमल में लाने की कोशिश करेंगे.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

इस हफ्ते आप अपने किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल होंगे. अगर आपके काम की यही रफ्तार रही तो जल्द ही आपके सारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं. इसका लाभ भी आपको जल्द ही मिल जाएगा.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

संपत्तियों को दूसरों की नज़र से बचाकर रखें, अन्यथा आप पर बढ़ते ख़र्च का बोझ पड़ेगा. यदि आपकी उम्र ज्यादा है और परिवारजनों से मनमुटाव चल रहा है तो इस सप्ताह आपको अपने भविष्य के लिए कोई ठोस रणनीति बनानी होगी.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

परिवार या दोस्तों के ज़रिए अपने मामले सुलझाने में कामयाब रहेंगे. हालांकि इसके बदले में आपके परिवारीजन आपसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास है कि आपके कष्ट से उनके कष्ट बढ़ जाएंगे.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस हफ्ते किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में आप कुछ पाने की भी अपेक्षा रखेंगे. कभी–कभी ऐसा भी अवसर आता है, जब दूसरे लोग आपके एहसान को जल्दी ही भूल जाते हैं. ऐसा ही एक मामला आपकी परेशानी बढ़ा सकता है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस हफ्ते किसी काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर भ्रम और संदेह की स्थिति बनी रहेगी. हो सकता है, आप कोई गंभीर और भारी–भरकम तरीक़ा अपनाएं, जिसकी वजह से आपके सहयोगी आपका विरोध कर सकते हैं.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस हफ्ते आपके कामकाज में कुछ प्रगति नज़र आएगी. बाहरी तौर पर उत्साहित और ख़ुश दिखाई देंगे, क्योंकि अचानक ही किसी भारी सफलता से आपके कारोबार और व्यवसाय में सुख–समृद्धि का आगमन होने जा रहा है.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस हफ्ते आपको अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों की रणनीति का आभास हो जाएगा. कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जो आपको बार–बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. इन सबसे निपटने के लिए आपको अपनी संगठन शक्ति और शुभचिंतकों का सहारा लेना पड़ेगा.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस हफ्ते अपने बाहरी दिखावे को छोड़कर किसी वास्तविक रूप में लोगों को प्रभावित करेंगे. किसी पुराने मित्र और परिचित से भी मुलाकात हो सकती है. आप पुरानी याद को तरोताजा कर सकते हैं.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

इस हफ्ते अपनी कार्य कुशलता और अनुभव आदि के बल पर आप अपनी व्यवसायिक समस्याएं सुलझा लेंगे. आप किसी सामाजिक आयोजन या मंगल कार्य संचालन समिति के प्रधान भी हो सकते हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अमेरिका के प्रति लोगों में गुस्सा उस वक़्त दिखा, जब बीती 18 मार्च को जुमे की नमाज़ के बाद रेमंड की रिहाई के विरुद्ध पूरे देश में विरोध दिवस मना.

पाकिस्तान

रेमंड को माफ़ी अवाम को मंज़ूर नहीं

राजीव रंजन तिवारी

अमेरिकी दूतावास कर्मी रेमंड डेविस की गोली से जब दो पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे तो कट्टरपंथियों ने यह कहते हुए चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया था कि यदि अमेरिका के दबाव में रेमंड की रिहाई हुई तो मुल्क में हुकूमत के विरुद्ध आग भड़क उठेगी, लेकिन रेमंड इस्लामी शरीयत के मुताबिक़ ब्लड मनी देकर रिहा हो गया. अब इस पर कट्टरपंथियों की बोलती बंद है. चूंकि पाकिस्तानी अमेरिकी नीतियों को पसंद नहीं करते, इसलिए संभव है कि देर-सबेर बवाल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कट्टरपंथियों की नरमी रहस्य के घेरे में है. यह कहा जा सकता है कि इस रिहाई से कट्टरपंथियों, आतंकवादियों एवं तालिबानियों को पाकिस्तान सरकार और अमेरिका के विरुद्ध ईंट से ईंट बजाने का मौक़ा मिल गया है. रेमंड प्रकरण अमेरिका के लिए भी अशांति का पैगाम लाया है. पाकिस्तानी चरमपंथी उस आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहेंगे, जिसे अमेरिकी अदालत ने 86 वर्ष की कैद की सज़ा सुना रखी है. इससे अलग पाकिस्तान में ईश निंदा क़ानून का अलग बवाल है. पाकिस्तान की स्थितियां निरंतर बिगड़ रही हैं, जिसमें सुधार की गुंजाइश कम ही दिख रही है.

ग़ौरतलब है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कर्मी रेमंड डेविस पर दो पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या का इल्ज़ाम है. रेमंड के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कर 27 जनवरी को उसे गिरफ़्तार किया गया था. यह ख़बर मिलते ही इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से लेकर वाशिंगटन तक हलचल मच गई. नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की ओर से कहा गया कि रेमंड की हिरासत ग़ैर क़ानूनी है, इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए. अदालत में रेमंड ने जज के सामने अपना जुर्म यह कहते हुए कबूला कि उसने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई थीं, जिसमें उक्त दोनों लोग मारे गए. उधर अमेरिका ने भी स्पष्ट किया कि यदि रेमंड रिहा नहीं होता है तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे, जिसका नुक़सान पाकिस्तान को होगा. ज्ञातव्य है कि ख़राब आर्थिक स्थिति वाले पाकिस्तान को प्रति वर्ष अमेरिका एक अरब डॉलर से अधिक की मदद करता है. इसी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत रेमंड के प्रति नरम रुख़ अख्तियार कर रही थी, लेकिन मामला अदालत में होने की वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती. रेमंड के प्रति सरकार की नरमी से सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के भीतर भी तूफ़ान खड़ा हुआ. सरकार कहती रही कि यदि अदालत रेमंड को रिहा करती है तो उसे मंजूर है. यानी पाकिस्तान सरकार को उसकी रिहाई पर ऐतराज नहीं था.

इस बीच जनता के रुख को भांपते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सरकार की मंशा के विरुद्ध यह कह दिया कि रेमंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो कि वह अमेरिकी राजनयिक है. पाकिस्तान की जनता की भावना रेमंड के ख़िलाफ़ है, इसलिए उसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए. नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान सरकार की अमेरिकापरस्ती के कारण उन्हें रेमंड के विरुद्ध वक्तव्य देने का ख़ामियाज़ा अपनी कुर्सी गंवा कर चुकाना पड़ा. कुरैशी के कुर्सी छोड़ते ही सरकार पर चौतरफा दबाव भी बनने लगा. मामले में नया मोड़ तब आया, जब रेमंड की गोली से मरे एक नागरिक फ़हीम की विधवा शमायला ने बीती 14 फरवरी को आत्महत्या कर ली. मरने से पहले शमायला ने कहा था कि उसे डर है कि सरकार अमेरिका के दबाव में उसके पति के हत्यारे को रिहा न कर दे. शमायला के उस बयान और आत्महत्या ने पाकिस्तान सरकार, अमेरिका और रेमंड के विरुद्ध आग भड़का दी. नतीजतन, चरमपंथी, जेहादी और तालिबानी एकजुट होकर रेमंड को फांसी देने की मांग करने लगे. जगह-जगह सरकार और अमेरिका के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ. तहरीक-ए-तालिबान और जमात-ए-इस्लामी ने रेमंड को फांसी देने या फिर उन्हें सौंपने की बात कही.

उधर देश के वकीलों ने भी चार याचिकाएं दायर कर दीं कि पाकिस्तान सरकार कहीं अमेरिकी दबाव में रेमंड को रिहा न कर दे. इस पर जज एजाज़ अहमद चौधरी ने रेमंड का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, ताकि वह देश न छोड़ सके. हालांकि रेमंड की रिहाई के लिए अमेरिका ने कहा कि वह दूतावास कर्मी है, इसलिए उस पर मुक़दमा नहीं चल सकता. यह मसला इतना गंभीर हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ा कि रेमंड की वजह से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए वियना समझौते के तहत रेमंड को रिहा कर देना चाहिए. इस मसले पर दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी चल ही रही थी कि पाकिस्तान के क़ानून मंत्री बाबर अवान ने रेमंड की रिहाई के बदले अमेरिका की जेल में बंद आफ़िया सिद्दीकी को सौंपने की मांग कर डाली. विदित हो कि अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफ़िया को 86 साल की कैद की सज़ा

सुना रखी है. तीन बच्चों की मां आफ़िया ने जुलाई 2008 में अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया था. अब इन दोनों मसलों पर पाकिस्तान के लोग सड़क पर उतर आए हैं. जहां रेमंड की रिहाई का विरोध हो रहा है, वहीं आफ़िया की रिहाई की मांग तेज होने लगी है.

बराक ओबामा की अफ-पाक नीतियों के सलाहकार रहे ब्रूस रिडल ने अपनी पुस्तक डेडली एंबरेस: पाकिस्तान, अमेरिका एंड फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जेहाद में लिखा है कि पाकिस्तान में एक जनरल, जो 1980 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति एवं तानाशाह स्वर्गीय जनरल जिया-उल-हक का काफी नज़दीकी था, सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह का नेतृत्व कर सकता है. दरअसल, पाकिस्तान एवं अमेरिका दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है. पाकिस्तान को हर वर्ष अमेरिकी डॉलर चाहिए तो अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध जंग में पाकिस्तान की मदद. ख़ैर, रेमंड की रिहाई के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने ब्लड मनी का सहारा लिया. पंजाब के क़ानून मंत्री सनाउल्लाह ने कहा कि रेमंड को इस्लामी क़ानून के तहत ब्लड मनी के भुगतान के बाद छोड़ा गया है. मारे गए दोनों लोगों के परिवारीजनों को इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ बतौर ब्लड मनी बीस लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए.

जमात-उद-दावा के प्रमुख मोहम्मद सईद ने कहा कि अमेरिका से मुक्ति पाने का यह मौक़ा हमें बड़े भाग्य से मिला. अमेरिका के प्रति लोगों में गुस्सा उस वक़्त दिखा, जब बीती 18 मार्च को जुम्मे की नमाज़ के बाद रेमंड की रिहाई के विरुद्ध पूरे देश में विरोध दिवस मना. जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख सईद मुनव्वर हसन ने डेविस को रिहा करने के मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. मुनव्वर ने कहा कि सरकार ने रेमंड को रिहा करके देश की इज़्ज़त से खिलवाड़ किया है. अमेरिकी सरकार ने आफ़िया को सिर्फ़ बंदूक़ दिखाने के आरोप में 86 साल की सज़ा दे दी, लेकिन हत्यारे रेमंड को रिहा कर दिया गया. वकील इक़बाल जाफरी ने रेमंड की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि रेमंड को माफी और रिहाई क़ानून के विरुद्ध है. उधर रेमंड द्वारा मारे गए लोगों के परिवारीजनों ने अदालत के निर्णय के बाद चुपचाप देश छोड़ दिया है. माना जा रहा है कि उन्हें अमेरिका में ग्रीन कार्ड और आवास दिया गया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रेमंड की रिहाई के बदले कोई ब्लड मनी नहीं दिया गया. पाकिस्तान में लगातार पिछले तीन दशकों से जेहाद चल रहा है. अफ़ग़ानिस्तान के साथ सोवियत संघ के युद्ध के समय से लेकर कश्मीर में घुसपैठ और तालिबान के बढ़ते क़दमों तक मुल्क लगातार संघर्ष से सामना कर रहा है. पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र वहां की विदेश नीति पर हावी है.

feedback@chauthiduniya.com

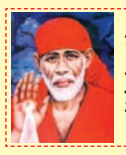

साई बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक विशेष शकुन हुआ, जो उनके महासमाधि लेने की पूर्व सूचना थी. साई बाबा के पास एक ईंट थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे.

मुक्ति का महामंत्र

ऑसिम खेत्रपाल

शिरडी के साई बाबा आज असंख्य लोगों के आराध्यदेव बन चुके हैं. उनकी कीर्ति दिन दोगुनी-रात चौगुनी बढ़ती जा रही है. यद्यपि बाबा के द्वारा नश्वर शरीर को त्यागे हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए आज भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं. शिरडी में बाबा की समाधि से भक्तों को अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान मिलता है. बाबा की दिव्य शक्ति के प्रताप से शिरडी अब महातीर्थ बन गई है. साई बाबा ने अनगिनत लोगों के कष्टों का निवारण किया. जो भी उनके पास आया, वह कभी निराश होकर नहीं लौटा. वह सबके प्रति समभाव रखते थे. उनके यहां अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, जातिपात, धर्म-मजहब का कोई भेदभाव नहीं था. समाज के सभी वर्ग के लोग उनके पास आते थे. बाबा ने एक हिंदू द्वारा बनवाई गई पुरानी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया और उसको नाम दिया द्वारकामाई. बाबा नित्य भिक्षा लेने जाते थे और बड़ी सादगी के साथ रहते थे. भक्तों को उनमें सब देवताओं के दर्शन होते थे. कुछ दुष्ट लोग बाबा की ख्याति के कारण उनसे ईर्ष्या-द्वेष रखते थे और उन्होंने कई षड्यंत्र भी रचे. बाबा सत्य, प्रेम, दया, करुणा की प्रतिमूर्ति थे. साई बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र से मिलती है. मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है. साई नाथ के भक्त इस ग्रंथ का पाठ अनुष्ठान के रूप में करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं.

साई बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक विशेष शकुन हुआ, जो उनके महासमाधि लेने की पूर्व सूचना थी. साई बाबा के पास एक ईंट थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे. बाबा उस पर हाथ टिकाकर बैठते थे और रात में सोते समय उस ईंट को तकिए की तरह अपने सिर के नीचे रखते थे. 1918 के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय एक भक्त के हाथ से गिरकर वह ईंट टूट गई. द्वारकामाई में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए. साई बाबा ने लौटकर जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वह मुस्करा कर बोले कि यह ईंट मेरी जीवनसंगिनी थी. अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया. बाबा तबसे अपनी महासमाधि की तैयारी करने लगे.

नागपुर के प्रसिद्ध धनी बाबू साहिब बूटी साई बाबा के बड़े भक्त थे. उनके मन में बाबा के आराम से निवास करने हेतु शिरडी में एक अच्छा भवन बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई. बाबा ने बूटी साहिब को स्वप्न में एक मंदिर सहित वाड़ा बनाने का आदेश दिया तो उन्होंने तत्काल उसे बनवाना शुरू कर दिया. मंदिर में द्वारकाधीश श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी. महासमाधि लेने से पूर्व साई बाबा ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया था कि पंचतत्वों से निर्मित उनका शरीर जब इस धरती पर नहीं रहेगा, तब उनकी समाधि भक्तों को संरक्षण प्रदान करेगी. आज तक सभी भक्तजन बाबा के इस कथन की सत्यता का निरंतर अनुभव करते चले आ रहे हैं. साई बाबा ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सदा अपनी उपस्थिति का बोध कराया है. उनकी समाधि अत्यंत जागृत शक्ति स्थल है. साई बाबा सदा यह कहते थे कि सबका मालिक एक. उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देकर सबको प्रेम के साथ मिलजुल कर रहने को कहा. बाबा ने अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी (संयम) का पाठ सिखाया. जो भी उनकी शरण में गया, उसको उन्होंने अवश्य अपनाया. विजयादशमी उनकी पुण्यतिथि बनकर हमें अपनी बुराइयों (दुर्गुणों) पर विजय पाने के लिए प्रेरित करती है. नित्य लीलालीन साई बाबा आज भी सद्गुरु के रूप में भक्तों को सही राह दिखाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं. साई नाथ के उपदेशों में संसार के सभी धर्मों का सार है. ऐसी महान विभूति के बारे में जितना भी लिखा जाए, कम ही होगा. उनकी यश पताका आज चारों तरफ़ फहरा रही है. बाबा का साई नाम मुक्ति का महामंत्र बन गया है और शिरडी महातीर्थ.

feedback@chauthiduniya.com

पहेली का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साई सच्चरित्र का पाठ करें. सात दिन के अंदर इसका संपूर्ण पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी.

साई बाबा ने अपने किस भक्त को कोढ़ से मुक्ति दिलाई?

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें.
011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाजा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

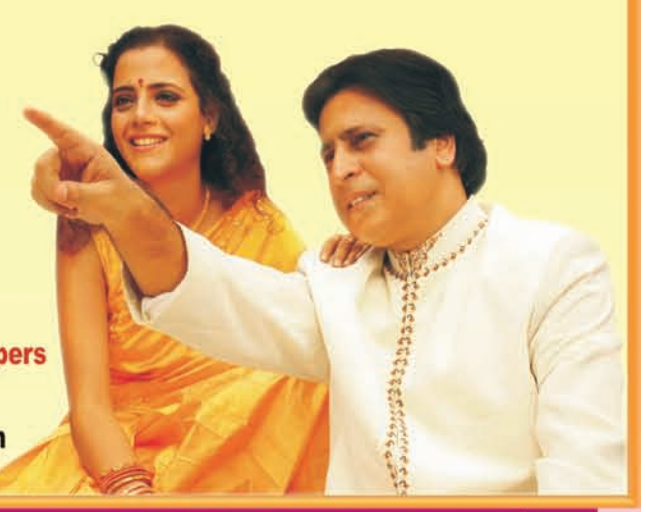

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार बार नमस्कार.

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए. *स्व. मालती कपूर*

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है. *प्रेमचंद*

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं. *स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा*

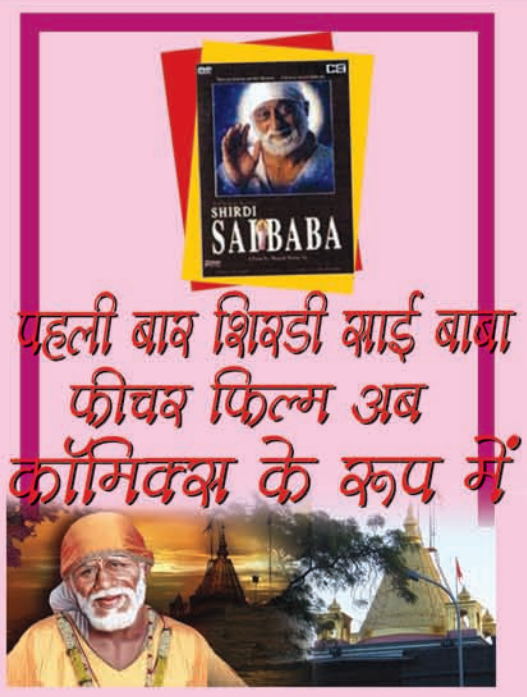

तोमर जी के लेख अक्सर जनादेश सहित विभिन्न पोर्टलों पर पढ़ने को मिल जाते थे, जिन्हें पढ़कर प्रेरणा मिलती थी. अरुण को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आलोक तोमर अब हमारे बीच नहीं हैं.

अनंत विजय

निराशा से भरा संपादकीय

पिछले पच्चीस साल से राजेंद्र यादव के संपादन में प्रकाशित हंस का संपादकीय होता है–मेरी तेरी उसकी बात. मैं पिछले पच्चीस सालों से तो नहीं, लेकिन सत्तरह–अट्ठारह सालों से नियमित राजेंद्र जी का संपादकीय पढ़ता रहा हूं. मुझे यह कहने या मानने में कोई संकोच नहीं है कि हंस के संपादकीय ने मुझे चीज़ों को देखने–समझने की एक अलग दृष्टि दी. राजेंद्र यादव का संपादकीय बहुधा ऊर्जा से लबरेज और व्यवस्था से लड़ने–भिड़ने पर उतारू या सामाजिक रूढ़ियों पर चोट करता हुआ रहता था. यादव जी की तीखी भाषा और तर्क गढ़ने की शक्ति का कायल हो गया था. कई बार हंस के संपादक से उनके संपादकीय में प्रकट किए गए विचारों को लेकर असहमतियां भी रहीं, जो लिखकर या फिर मौखिक दर्ज कराईं. लोग संपादकीय के बारे में बेशक अनाप–शनाप बोलते रहे हों, कई नामवर लोग तो मेरी तेरी उसकी बात को कूड़े की बात कहकर मज़ाक भी उड़ाते रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे उनका संपादकीय हमेशा से विचारोत्तेजक लगता रहा है. अभी पिछले दो–तीन अंकों का संपादकीय बेहद अच्छा था, पसंद इसलिए आ रहा था, क्योंकि कम डिप्लोमैटिक था. साफ़ बातें हमेशा से लोगों को पसंद आती हैं, मुझे भी. लेकिन फरवरी अंक का संपादकीय पढ़कर मुझे जाने क्यों बेहद कोफ्त हुई. मैं उनको पत्र लिखना चाह रहा था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से लिख नहीं पाया. लेकिन अगले ही अंक में संपादकीय की भूल–ग़लतियों पर साधना अग्रवाल का एक लंबा पत्र और राजेंद्र यादव का खेद भी प्रकाशित है. ख़ैर, वे तो तथ्यात्मक भूल की बातें थीं, लेकिन फरवरी अंक के संपादकीय से जो निराशा का भाव सामने आता है, वह न केवल चिंताजनक है, बल्कि उस निराशा के अंधकार में यादव जी इतना डूब जाते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया, समाज का हर तबका (लेखक को छोड़कर) भ्रष्ट और टुच्चा नज़र आता है.

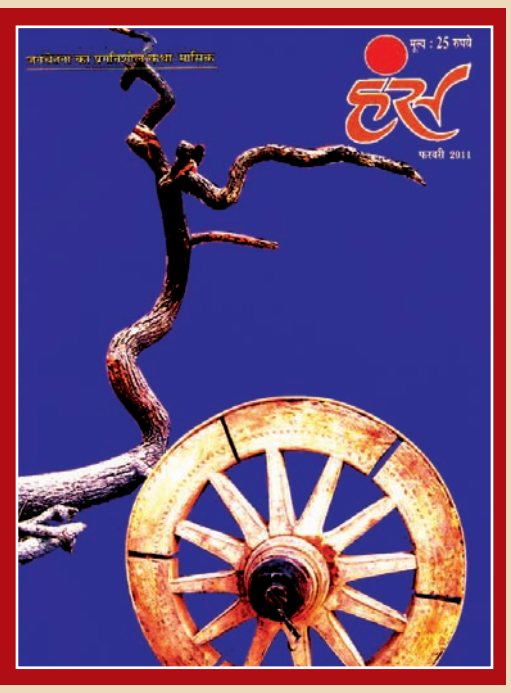

उनके संपादकीय को देखिए–घूस, घोटालों और घपलों का एक साल (2010) बीत गया, शायद यह साल स्वतंत्र भारत के सबसे काले दिनों के रूप में याद किया जाएगा, जहां निरंकुश सत्ता भारतीय संविधान से कारपोरेट हाउसों ने छीन ली और देश के सारे शक्ति स्तंभ चरमरा कर ढह गए हैं. पांचवां स्तंभ यानी मीडिया या तो पेड न्यूज़ के हाथों बिक गया है या नीरा राडिया जैसों के माध्यम से दोनों हाथों से दलाली खा रहा है. यादव जी के इस संपादकीय ने मीडिया को लोकतंत्र में एक पायदान नीचे ठेल दिया. यह अब तक चौथा स्तंभ माना जाता था, लेकिन राजेंद्र जी ने इसे पांचवां स्तंभ क़रार दिया. निराशा के घोर आलम में राजेंद्र यादव जी ने पूरे मीडिया को बिका हुआ या दलाल क़रार दे दिया. यादव जी जैसे ज़िम्मेदार और बुज़ुर्ग लेखक से इस तरह की फ़तवेबाज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है. अगर किन्हीं एक–दो अख़बारों में पेड न्यूज़ छप रही हैं या फिर कुल जमा चार पत्रकारों के नीरा राडिया से संबंध सामने आए हैं, वैसे में पूरे मीडिया को दलाल कहना ग़ैर ज़रूरी ही नहीं, ग़ैर ज़िम्मेदाराना भी है. यादव जी जैसे सम्मानित लोगों को इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क से बचना चाहिए. उन्हें शायद इस बात का एहसास होगा कि लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके कहे का समाज पर असर पड़ता है. इसलिए अगर वह कोई बात कहते हैं तो उसमें सब्सटैंस होना चाहिए. लेकिन वह तो एक डंडा लेकर निकल पड़े हैं और उससे ही सभी को हांकने पर आमादा हैं.

मीडिया पर वह यहीं नहीं रुकते, उसी में आगे कहते हैं–देश की राजधानी में हर रोज दर्जनों हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी हैं. ग़रीबी–अमीरी के बीच की खाई अपराधों और हत्याओं से पाटी जा रही है. ग़रीब और वंचित आदमी आख़िर कब तक ऊपर वालों की हज़ारों–लाखों करोड़ की हेर–फेर को चुपचाप बैठा देखता रहे? टीवी चैनलों और अख़बारों के पास इन सनसनीख़ेज़ ख़बरों के सिवा परोसने को कुछ नहीं बचा है. वे इन्हें ही कूट–पीस रहे हैं. गांव और ग़रीबी का वहां कोई नामोनिशान नहीं रह गया है. यहां भी यादव जी का संपादकीय सामान्यीकरण के दोष का शिकार हो गया है. यादव जी जिन घपलों–घोटालों की बात कर रहे हैं, उन्हें किसने उजागर किया? जिस एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ के टेलीकॉम घोटाले में पूर्व मंत्री ए राजा जेल में हैं, उसका पर्दाफाश किसने किया? क्या एक अख़बार के रिपोर्टर ने आज़ाद भारत के इस सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया? क्या कमज़ोरों के हक़ की लड़ाई मीडिया नहीं लड़ता है? क्या यादव जी जेसिका के इंसाफ़ की लड़ाई भूल गए या फिर उन्होंने प्रियदर्शिनी मट्टू कांड में मीडिया की सामाजिक भूमिका को भुला दिया या फिर अभी–अभी दिल्ली के एक कॉलेज की लड़की राधिका की सरेआम हत्या पर मीडिया ने सरकार और पुलिस पर दबाव नहीं बनाया? यह फ़ेहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन यादव जी देखना चाहें तब तो! उन्होंने तो पहले से ही तय कर लिया है कि सबका नाश करना है और फिर उस पर पिल पड़े. लेकिन जब आप सामान्यीकरण की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो आप सिर्फ़ वही देख सकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं.

मीडिया पर वह यहीं नहीं रुकते, उसी में आगे कहते हैं-देश की राजधानी में हर रोज दर्जनों हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी हैं. ग़रीबी-अमीरी के बीच की खाई अपराधों और हत्याओं से पाटी जा रही है. ग़रीब और वंचित आदमी आख़िर कब तक ऊपर वालों की हज़ारों-लाखों करोड़ की हेर-फेर को चुपचाप बैठा देखता रहे? टीवी चैनलों और अख़बारों के पास इन सनसनीख़ेज़ ख़बरों के सिवा परोसने को कुछ नहीं बचा है.

आगे अपने संपादकीय में यादव जी अपने पसंदीदा विषय नक्सली और उनके हमदर्द विनायक सेन पर पहुंचते हैं और टिप्पणी करते हैं–उधर कश्मीर, असम और महाराष्ट्र में रोज बंद होते हैं. घर, बसें और सार्वजनिक संपत्तियां फूंकी जाती हैं. गोली–लाठी–पत्थर चलाए जाते हैं, ऐसे में आदिवासियों, किसानों के हितों के लिए लड़ने वाले माओवादी, नक्सली देश के दुश्मन नंबर वन घोषित ही नहीं किए जाते, फ़ौजों और हवाई जहाजों से वहां शांति स्थापित की जाती है. भगवान जाने किसने माओवादियों को देश का दुश्मन नंबर वन घोषित किया है. लेकिन यादव जी इतना तो तय मानिए कि जिन्हें आप आदिवासियों और किसानों के हितों के लिए लड़ने वाला नक्सली और माओवादी बता रहे हैं, वे अब सिर्फ़ अपने हित की सोचते हैं, अब वे अपराधी बन चुके हैं, अब वे फ़िरौती के लिए अपहरण करते हैं और धन न मिलने पर मासूमों को जान से मार डालते हैं. किसानों के हितों की आड़ में अपराध का नंगा खेल खेला जा रहा है. उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उनका संपर्क आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों से होने लगा है. लेकिन यादव जी, आप जिस लाल चश्मे से नक्सलियों को देखते हैं, उससे तो वे किसानों और ग़रीबों के हितों के रक्षक ही नज़र आएंगे. ज़रा आंखों से लाल चश्मा हटाकर देखिए, आपको अपराध की काली दुनिया नज़र आएगी. जिस विनायक सेन को आप ग़रीबों का चिकित्सक बता रहे हैं, वह देशद्रोह की सज़ा काट रहे हैं. देश के तमाम नामी–गिरामी वकीलों का प्रयास और ग़ैर सरकारी संस्थाओं का पैसा भी विनायक सेन को हाईकोर्ट से जमानत नहीं दिला सका. आप लोगों का तर्क होगा कि अदालत भी तो राज्य सत्ता का ही एक अंग होती है. देश की न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा नहीं रहा. आपने लिखा– न्यायपालिका खुलेआम अपने फ़ैसले अपराधी के पक्ष में बेच रही है. यहां भी जनरलाइज़ेशन. अगर हमारी न्यायपालिका अपने फ़ैसले बेच रही होती तो विदेशों से आर्थिक मदद पाने वाले देशी एनजीओ विनायक सेन के लिए फ़ैसला ख़रीद चुके होते. लेकिन यक़ीन मानिए यादव जी, हमारे देश की न्यायपालिका आपको अवश्य बिकी हुई नज़र आ रही हो, लेकिन एक–दो अपवादों को छोड़कर, कमोबेश ईमानदार है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

आलोक तोमर

कलम का सच्चा सिपाही

आलोक तोमर के निधन की ख़बर समूचे मीडिया जगत में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई. एक पत्रकार साथी ने जैसे ही मुझे बताया कि कलम के सिपाही आलोक तोमर सदा के लिए सो गए तो मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ. तोमर ने हमेशा जनता की आवाज़ बनने के लिए कलम चलाई. मानवता के प्रबल पक्षधर तोमर ने जिस तरह सिख दंगा पीड़ितों का दर्द जनता तक पूरे साहस के साथ पहुंचाया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. लोगों ने इस सच्चाई को बहुत क़रीब से महसूस किया कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे. हिमालय के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें हिम भूमि की ओर इतना खींचा कि रामगढ़ में एक टुकड़ा ज़मीन ख़रीद कर वह हिमपुत्र भी बन गए. सोनभद्र प्रेस क्लब के अध्यक्ष विजय चतुर्वेदी ने तोमर के व्यक्तित्व की चर्चा करते उन्हें एक महान कलमकार बताया. मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पत्रकार अरुण जायसवाल ने कहा कि तोमर जी के लेख अक्सर जनादेश सहित विभिन्न पोर्टलों पर पढ़ने को मिल जाते थे, जिन्हें पढ़कर प्रेरणा मिलती थी. अरुण को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आलोक तोमर अब हमारे बीच नहीं हैं. इस पर हमने दिल्ली में रहने वाले पत्रकार साथी विजय शुक्ला से फोन पर बात की. शुक्ला ने रुंधे कंठ से बीमारी से लेकर उनके सदा के लिए सो जाने तक की सूचना दे डाली. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक शोक सभा हुई. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय पार्षद आर के शर्मा ने आलोक जी को सच्चा कलमकार बताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. प्रयाग के वरिष्ठ पत्रकार एवं भट्ट सत्ता के संपादक प्रभाकर भट्ट ने कहा कि आलोक जी नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए प्रेरणास्रोत थे. उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने आलोक तोमर को राष्ट्रीय पहचान वाला सच्चा कलमकार बताया.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

भारतीय कंपनी लावा ने एक नया ड्यूल सिम फोन पेश किया है, जिसमें कई ख़ूबियां हैं. यह नया फोन है लावा क्वर्टी-35 और इसकी ख़ासियत है कि यह कलर मैचर है.

इलेक्ट्रिक स्कूटर का सफर

क़रीब 10 साल पहले बीएमडब्ल्यू ने ऐलान किया था कि वह एक ऐसा स्कूटर तैयार करना चाहती है, जिसे चलाने के लिए बेहद मामूली ख़र्च करना पड़े. आख़िरकार अब यह स्कूटर तैयार हो गया है.

महंगे होते पेट्रोल के इस दौर में लग्जरी कारों से अपनी पहचान बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू की सहयोगी कंपनी मिनी ने अब एक ख़ास स्कूटर लांच किया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक मील तक चलाने का ख़र्च मात्र एक पेंस यानी क़रीब 70 पैसे आएगा. क़रीब 10 साल पहले बीएमडब्ल्यू ने ऐलान किया था कि वह एक ऐसा स्कूटर तैयार करना चाहती है, जिसे चलाने के लिए बेहद मामूली ख़र्च करना पड़े. आख़िरकार अब यह स्कूटर तैयार हो गया है. इसे पेरिस मोटर शो में लांच किया जाएगा, जिसके बाद पूरे विश्व में उपलब्ध कराया जाएगा. इस ख़ास स्कूटर में चार्जेबल बैट्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसे घर में लगे इलेक्ट्रिक सॉकेट के ज़रिए आसानी से चार्ज किया जा सकता है. इसे पूरी तरह चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगेगा. इस स्कूटर की अधिकतम रफ्तार 50 मील प्रति घंटे है. कंपनी की तरफ़ से फ़िलहाल इसकी क़ीमत का ख़ुलासा नहीं किया गया है.

बीएमडब्ल्यू की साइकिल

दुनिया की मशहूर लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्लू ने अब साइकिल बनाना शुरू कर दिया है. साइकिलिंग का लुत्फ़ सिर्फ़ निचले वर्ग के लोग ही नहीं उठाएंगे, साइकिल पर चलना अब कार न होने की निशानी नहीं माना जाएगा, यह अमीरों द्वारा भी शौक से चलाई जा सकेगी. ख़ास बात यह है कि इस साइकिल का वज़न सिर्फ़ सवा सात किलो है, जिसे बनाने में बीएमडब्लू के इंजीनियरों ने दिन-रात एक कर दिया. कंपनी ने यह साइकिल कार्बन फाइबर से तैयार कराई है और इसलिए यह अल्ट्रा स्लिम है और देखने में बिल्कुल अनूठी. इसके हलकेपन का मतलब यह नहीं है कि यह वज़न नहीं ढो सकती. यह 80 किलो तक वज़न आसानी से ढो सकती है. कार्बन फाइबर से बनने से फ़ायदा यह है कि इस साइकिल में आम साइकिलों की तरह जंग नहीं लगेगी. बीएमडब्लू के स्टाइल स्टेटमेंट के मुताबिक़ इस साइकिल को काफी रंग-बिरंगा बनाया गया है. इसके रिम कलरफुल हैं और ब्रेक ज़बरदस्त पावरफुल. इसमें गियर भी हैं, जिनसे साइकिल सवार स्पीड बढ़ा-घटा सकते हैं. आम साइकिलों की तरह राइडर की एनर्जी से चलने वाली इस साइकिल से पर्यावरण प्रदूषण की भी जांच बनी रहेगी और स्टाइल और स्टैंडर्ड साथ-साथ रहेगा. यह साइकिल आगामी जून माह से बीएमडब्लू के चुनिंदा डीलरों के यहां मिलने लगेगी, लेकिन कंपनी ने इसकी क़ीमत का खुलासा नहीं किया है. फिर भी इसकी क़ीमत लाखों में होगी, इसका अंदाज़ा तो आसानी से लगाया जा सकता है.

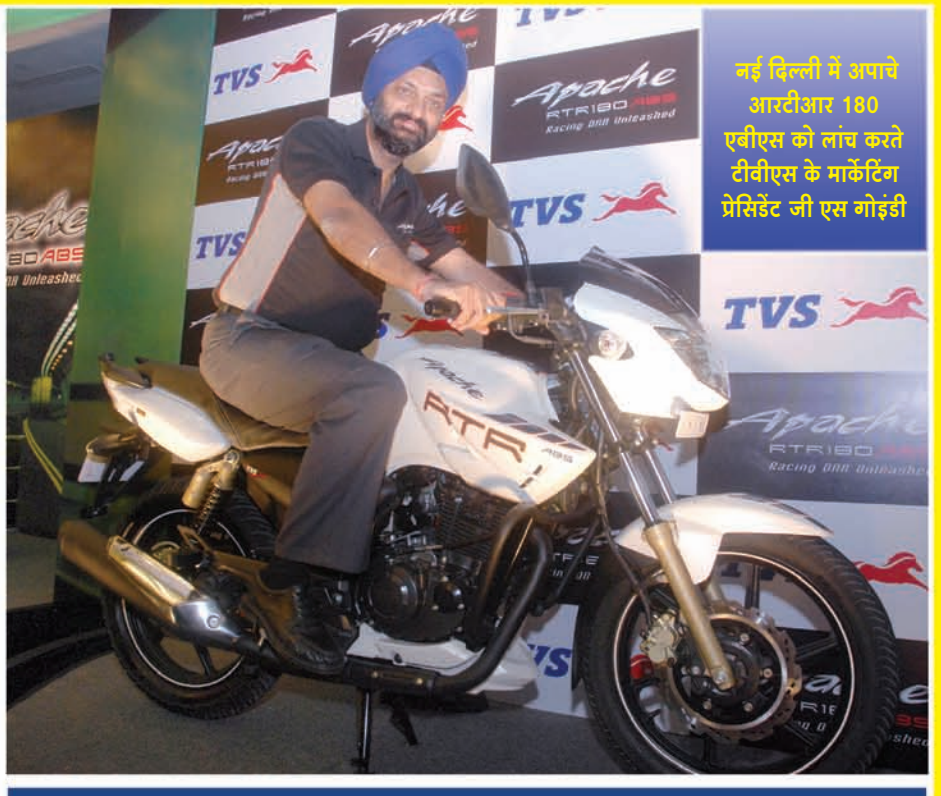

नई दिल्ली में अपाचे आरटीआर 180 एबीएस को लांच करते टीवीएस के मार्केटिंग प्रेसिडेंट जी एस गोइंडी

होम थिएटर वाला लैपटॉप

जो लैपटॉप में 3-डी और एचडी मूवीज़ रखना चाहते हैं यानी यह फिल्मों के शौक़ीन लोगों के लिए एक वरदान है.

अगर मोबाइल फोन की दुनिया में ढेरों बदलाव हो रहे हैं तो लैपटॉप भला पीछे कैसे रह सकते हैं. लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां एक से बढ़कर एक लैपटॉप पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में अब एचपी ने एक बेहद शक्तिशाली लैपटॉप बाज़ार में उतारा है. यह उन लोगों के लिए बेहद काम का है, जो लैपटॉप में 3-डी और एचडी मूवीज़ रखना चाहते हैं यानी यह फिल्मों के शौक़ीन लोगों के लिए एक वरदान है. एचपी एनवी-17 एक मल्टी मीडिया लैपटॉप है, जो इस मामले में एक शानदार पेशकश है. इसकी ख़ासियत यह है कि तमाम 3-डी टेक्नोलॉजी इसी में ही है और इसके लिए किसी तरह के ड्राइवर और डोंगल की ज़रूरत नहीं है. 3-डी मूवीज़ के लिए इसमें एक्टिव शटर ग्लास हैं. इस लैपटॉप का एचडी स्क्रीन 17.3 इंच का है. इससे फिल्में काफी अच्छी तरह से देखी जा सकती हैं. अच्छे म्यूज़िक के लिए इसमें ब्लू रे और बीट्स ऑडियो हैं. इससे यह लैपटॉप एक परफेक्ट होम थिएटर का काम करता है. इसकी मेमोरी अधिकतम 8 जीबी हो सकती है. इसकी क़ीमत लगभग 75 हज़ार रुपये है. शायद यह क़ीमत लोगों को थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन चीज़ भी उम्दा है.

नई दिल्ली में एक वॉच स्टोर के शुभारंभ के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान

अनोखा मोबाइल फोन

ग्राहकों को लुभाने के लिए भारतीय मोबाइल कंपनियां एक से बढ़कर एक हैंडसेट बाज़ार में उतार रही हैं. इसी क्रम में भारतीय कंपनी लावा ने एक नया ड्यूल सिम फोन पेश किया है, जिसमें कई ख़ूबियां हैं. यह नया फोन है लावा क्वर्टी-35 और इसकी ख़ासियत है कि यह कलर मैचर है. यह एक नया फीचर है, जिसके ज़रिए आप इस फोन के कैमरे को जिस चीज़ या सतह की ओर निर्देशित करेंगे, वह उस रंग को कैच कर लेगा और उसे आपके फोन का वाल पेपर बना देगा. यानी आप किसी भी रंग का वाल पेपर बना सकते हैं. इसके अलावा इसमें 2.4 इंच का एलसीडी स्क्रीन है. इसमें एक मल्टी फॉर्मेट वीडियो प्लेयर है, जिससे आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें मोबाइल ट्रैकर, बातचीत रिकॉर्डर और जवाब देने वाली मशीन भी है. इसकी क़ीमत भी ज़्यादा नहीं है यानी सिर्फ़ 3950 रुपये.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत का मुक़ाबला आस्ट्रेलिया से हुआ और इस मैच को जीतकर भारत ने शानदार वापसी करते हुए किसी हद तक अपनी दावेदारी जता दी है.

जो जीता वही सिकंदर

पिछली बार प्रायोजकों को भारी नुक़सान उठाना पड़ा था, क्योंकि क्रिकेट के बड़े प्रायोजक भारतीय बाज़ार को निशाना बनाते हैं. अब ऐसे में सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता को भी भुनाने का उन्हें मौक़ा मिलता है. इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि विश्वकप में भारत या पाकिस्तान फ़ाइनल तक ज़रूर पहुंचेंगे.

ICC Cricket World Cup 2011

जब तक यह आलेख पाठकों तक पहुंचेगा तब तक विश्व कप 2011 का विजेता सामने आ चुका होगा, लेकिन अपने आख़िरी पड़ाव की ओर पहुंच चुके इस महाकुंभ में अब तक जितने भी मैच हुए हैं उनमें किसी भी तरह का रोमांच देखने को नहीं मिला. जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी कि आयरलैंड और कनाडा जैसी दूसरी टीमें शुरुआती राउंड से ही बाहर हो जाएंगी, ठीक वैसा ही हुआ. विश्व कप का पहला हफ़्ता बहुत रोमांचक नहीं रहा, जहां क्रिकेट जगत की शीर्ष टीमों और बाक़ी टीमों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि मुक़ाबला एकतरफ़ा होना ही था. सभी टीमें अपना-अपना खाता निपटाकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. अब बची वही कुछ चुनिंदा टीमें, जो ज़्यादातर हर विश्वकप में सेमीफाइनल में भिड़ती हैं, मसलन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान. अगर क्रिकेट के जानकारों की मानें तो उपमहाद्वीप से बाहर की किसी भी टीम के लिए विश्व कप जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि यहां की परिस्थितियां ही ऐसी हैं. नीची रहने वाली और धीमी घूमने वाली विकेट में बाहर की किसी भी टीम की गेंदबाज़ी में ऐसा संतुलन नहीं है जिससे कि वह नियमित रूप से मैच जिता सके, लेकिन इसी आधार पर अन्य टीमों की दावेदारी को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता है. दरअसल मुश्किल उनको होगी, जिनकी बल्लेबाज़ी में इतना दम नहीं है कि वे शीर्षक्रम के लड़खड़ाने पर संभल सकें.

बात अगर मेज़बान देश भारत की बात की जाए तो अब तक मैच देखने के बाद यही अनुमान निकाला जा सकता है कि इसका टॉप ऑर्डर बुरी तरफ़ फ्लॉप रहा है. इक्का-दुक्का खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मैचों में बल्लेबाज़ तू चल मैं आया की तर्ज़ पर ही खेले हैं. इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ भारत का 19 साल बाद वनडे सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया. इसकी सबसे बड़ी वजह टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना रही. इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत नागपुर में खेले गए विश्व कप क्रिकेट के एक मैच में दक्षिण अफ्रीका से तीन विकेट से हार गया. दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 297 रनों की आवश्यकता थी, जो उसने दो गेंद रहते ही हासिल कर ली. इस विश्व कप में यह भारत की पहली हार थी. इसके बाद भारत का मुक़ाबला वेस्टइंडीज से हुआ. मैच की शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था यह मैच भी भारत की झोली से चला जाएगा, लेकिन क़िस्मत से टीम इंडिया जीत गई. इसके बाद भारत का मुक़ाबला आस्ट्रेलिया से हुआ और इस मैच को जीतकर भारत ने शानदार वापसी करते हुए किसी हद तक अपनी दावेदारी जता दी है. अब बचता है श्रीलंका. यह एक ऐसी टीम है जिसकी गेंदबाज़ी संतुलित है, मैदान पर खिलाड़ी चुस्त हैं और बल्लेबाज़ी ठोस है. वे किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं. फ़ाइनल में भारत और श्रीलंका की टक्कर की संभावना पूरी बनती है, बशर्ते दोनों टीमें नॉक आउट दौर में न टकरा जाएं.

लेकिन खेल प्रेमियों समेत कई लोगों की इच्छा भारत-पाक के मैच में दिखती है. ऐसे में अब अगर सेमीफ़ाइनल में इन दोनों टीमों के भिड़ने की संभावना हो जाए तब? इस रोचक संभावना से क्रिकेट प्रेमी तो उत्साहित हैं ही, लगता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी उत्साहित है, क्योंकि हारून लोर्गाट अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन में आए और उन्होंने क्वार्टर फ़ाइनल मैचों का ज़िक्र शुरू किया तो पहले बोले कि भारत और पाकिस्तान के मैच का विजेता मोहाली में खेलेगा. इससे पहले कि वह आगे बढ़ते उनके साथियों और मीडिया वालों ने उन्हें याद दिलाया कि अभी क्वार्टर फ़ाइनल में ये दोनों टीमें अलग-अलग खेल रही हैं. भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट से आईसीसी को काफ़ी मुनाफ़ा होता है और वहां भारत-पाकिस्तान के मैच की तो बात ही क्या होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नज़र उस मुनाफ़े पर रखे हुए लोर्गाट साहब दिल की बात बोल गए. ख़ैर जो भी हो हालात भारत पाक के साथ ही हैं. वैसे भारत और पाकिस्तान जैसे देश इस टूर्नामेंट से पिछली बार की तरह जल्दी ही रुख्सत न हो जाएं, इसलिए इस बार ऐसा फ़ॉर्मेट बनाया गया, जहां दोनों टीमें कम से कम क्वार्टर फ़ाइनल तक तो पहुंचे ही जाएं.

पिछली बार प्रायोजकों को भारी नुक़सान उठाना पड़ा था, क्योंकि क्रिकेट के बड़े प्रायोजक भारतीय बाज़ार को निशाना बनाते हैं. अब ऐसे में सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता को भी भुनाने का उन्हें मौक़ा मिलता है. इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि विश्वकप में भारत या पाक फ़ाइनल तक ज़रूर पहुंचेंगे. पाकिस्तान की गेंदबाज़ी उन तमाम झटकों के बाद जिन्होंने उसकी धार को कुंद किया है, मज़बूत लगती है, लेकिन तब क्या उसकी टीम नियमित तौर पर बड़े स्कोर कर सकेगी? इस पर संदेह है. ऐसे में बचते हैं केवल दो मुख्य दावेदार और उनके दावे को पहले हफ़्ते के उनके प्रदर्शन से और बल मिलता है.

भारत की बल्लेबाज़ी, ऐसी परिस्थितियों में जिससे वह भली-भांति परिचित है, वह देखने में ही डरानेवाली और ठोस लगती है. अगर उसका ऊपरी और मध्य क्रम नहीं बैठा, जिसकी संभावना ऐसे विकेटों पर कम ही है तो खिलाड़ी निर्दयी होकर खेलेंगे. और उनके पास ऐसे धीमी गति के गेंदबाज़ हैं जो किसी भी टीम की बल्लेबाज़ी का कचूमर निकाल सकते हैं. फिर भी, उनका कमज़ोर-तेज़ आक्रमण, मैदान पर सुस्त हाव-भाव और अपेक्षाओं के दबाव का सामना करने की टीम की क्षमता चिंता की वजह होनी चाहिए.इसके अलावा एक और बात यह कि यह विश्वकप सचिन और पॉन्टिंग का आख़िरी विश्वकप माना जा रहा है. हालांकि रिकी इस बात से इंकार करते हैं कि वह विश्वकप के बाद संन्यास ले लेंगे. रिकी से संवाददाताओं ने पूछा कि विश्व कप जैसे मुक़ाबले में सचिन और पॉन्टिंग आख़िरी बार आमने-सामने होंगे तो वह बातों ही बातों में सचिन की तारीफ़ कर गए. बोले, जहां तक हमारे अंतिम विश्व कप की बात है तो सचिन जिस फ़ॉर्म में हैं वह तो अभी एक और विश्व कप खेल सकते हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले मैच से मैं भी फ़ॉर्म में लौटूंगा और अगले विश्व कप तक खेल सकूंगा.

वैसे सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 99 शतक हो चुके हैं और किसी भी मैच में वह शतकों का शतक जड़ सकते हैं. उनके प्रशंसकों को भी हर मैच से पहले बेसब्री से सचिन के उस 100वें शतक का इंतज़ार रहता है. उपरोक्त विश्लेषण और आंकड़े बताते हैं कि विश्कप के असली मुक़ाबले अभी बाकी हैं और टीमों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी. एक ओर जहां जानकार मेज़बानों की दावेदारी मज़बूत बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बाक़ी टीमों का प्रदर्शन बोल रहा है कि वे किसी भी वक्त तख्ता पलट सकते हैं. ख़ैर 2 अप्रैल का फाइनल मैच इन सब कवायदों का जवाब दे देगा.

राजेश एस कुमार
rajeshsy@chauthiduniya.com

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida - an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India. Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144, E-mail: grazia@fortunehotels.in, Website: www.fortunehotels.in

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 04 अप्रैल–10 अप्रैल 2011

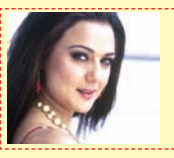

कैमरे पर वापसी के लिए मैंने तक़रीबन आठ किलो वज़न कम किया है. क्रिकेट और एक्टिंग में से क्या ज्यादा पसंद है? प्रीति कहती हैं कि दोनों की अपनी जगह है.

बॉलीवुड की ट्रेंड सेटिंग फिल्में

हिंदी फिल्मों में ढेर सारी चीजें बदल कर भी नहीं बदलतीं. भले ही नई तकनीक, नई लोकेशंस और बढ़े हुए बजट से सिनेमा के प्रदर्शन में भारी बदलाव आया हो. लेकिन कुछ चीजें एक ट्रेंड की तरह तबसे चली आ रही हैं, जबसे इनका प्रयोग हुआ है और ये बार-बार पर्दे पर आकर नई फिल्मों के ज़रिए अपने प्रयोग की याद दिलाती हैं. जैसे बॉलीवुड में आम आदमी का चित्रण. हाल में आई फिल्म पीपली लाइव के नत्था और खट्टा-मीठा में आम आदमी के किरदार ने रुपहले पर्दे के पहले आम आदमी राजू की याद दिला दी. फिर समाज के बदलते स्वरूप के साथ बदले हुए आम आदमी के रूप में विजय को हमने देखा. उसी तरह कुछ ख़ास चीजें हैं, जिन्होंने बदलते वक्त के सिनेमा में भी इतिहास को जीवंत बनाए रखा है. डालते हैं एक नज़र.

सेक्सी डिज़ाइनर वियर ट्रेंड

आपको याद होगा, फिल्म रंगीला में आमिर-उर्मिला की रंग बिरंगी ड्रेसेस, उसके बाद उसी तरह की ड्रेस का बाज़ार में छा जाना. दरअसल फिल्म रंगीला ने ही बॉलीवुड में स्टाइलिश और डिज़ाइनर कपड़ों का ट्रेंड बना दिया. इससे पहले बॉलीवुड की ड्रेसिंग ज़्यादा लाउड, भड़कीली और टोटल मिस मैच हुआ करती थी. 90 के दशक में उर्मिला अपने कपड़ों की वजह से ही बॉलीवुड की सेक्स सिंबल बन गई थीं. बॉलीवुड में सेक्सी का मतलब स्लिम और ड्रेस कोड में लेस इज मोर का प्रचलन हो गया. इस फिल्म के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने वाले मनीष मल्होत्रा आज लगभग सभी बड़े बजट वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं.

आर्ट और कमर्शियल फिल्मों का सिंगल डोज

फिल्म सत्या ने न केवल अंडरवर्ल्ड फिल्में बनाने का ट्रेंड सेट किया, बल्कि कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच की दीवार भी गिरा दी. वास्तविकता से जुड़ी कहानी होने के बावजूद इसकी गहराई में आर्ट सिनेमा की झलक थी. इसके सनसनी फैलाने वाले डायलॉग और कहानी में मजेदार ट्विस्ट होने की वजह से इसे कमर्शियल भी माना गया. इसके बाद ही बॉलीवुड में समानांतर सिनेमा का ट्रेंड बन गया, जिसका उदाहरण हैं इक़बाल, डोर, ए वेडनेस डे, देव डी और अंडरवर्ल्ड सिनेमा में गैंगस्टर, वास्तव, शूटआउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, कंपनी.

स्लैपस्टिक कॉमेडी

डेविड धवन की फिल्म आंखें से बॉलीवुड में हंसी-मज़ाक का नया ट्रेंड शुरू हो गया. पूर्ववर्ती हास्य फिल्मों से अलग इस फिल्म से सिचुएशन और दोहरे मतलब वाली कॉमेडी की शुरुआत हुई. इसके बाद ऐसी फिल्मों की बहार आ गई, जिन्हें दर्शकों ने ख़ूब पसंद किया. इसी तर्ज पर कुली नंबर-1, हीरो नंबर-1, जुड़वा, इश्क एवं राजा जैसी फिल्में आईं. इसके बाद डेविड के इस स्टाइल को कॉपी किया प्रियदर्शन ने और फिर बनी हेराफेरी, हंगामा एवं खट्टा-मीठा जैसी फिल्में.

विलेन के रोल में हीरो

शाहरुख़ ख़ान ने बॉलीवुड को न केवल एक लवरब्वॉय दिया, बल्कि एंटी हीरो भी दिया. वह पहले अभिनेता थे, जिसने बहुत बहादुरी से एंटी हीरो का निगेटिव किरदार निभाया. सबसे पहले अवार्ड विनिंग फिल्म बाजीगर, डर और फिर अंजाम में उन्होंने अपने इस किरदार को बड़ी आसानी से दर्शकों की सहानुभूति लेते हुए अदा किया. उसके बाद बॉलीवुड के लगभग सभी अभिनेताओं ने एंटी हीरो का किरदार निभाया, अपवाद केवल सलमान ख़ान हैं.

पर्दे पर आम आदमी

सिनेमा समाज का आईना है, इसे राजकपूर ने साबित कर दिया आम आदमी का किरदार निभाकर. वह हिंदी सिनेमा के पहले आम आदमी हैं. मेन स्ट्रीम सिनेमा में राजकपूर ने आम आदमी के प्रतिनिधि चरित्र के तौर पर राजू को गढ़ा. फिल्म दर फिल्म, विभिन्न पृष्ठभूमियों और परिस्थितियों में उन्होंने राजू की दुविधाओं, कमियों और सपनों को दिखाया. उसके बाद वही राजू समाज में अपनी जगह और अधिकारों के लिए विजय के रूप में सामने आया. सलीम-जावेद की मार्फत वंचितों की पूरी पीढ़ी का असंतोष, आक्रोश और आक्रामक स्वभाव व्यक्त हुआ. कालांतर में आम आदमी धीरे-धीरे वर्ग में बंट गया. फिर बाज़ारवाद के बाद शहर और देहात में बंट गया. फिर कभी रॉकेट सिंह तो कभी सुरेंद्र सूरी के नाम से सामने आया. हाल में आई फिल्म खट्टा-मीठा में मिडिल क्लास आम आदमी के रूप में अक्षय कुमार हैं तो ग्रामीण आम आदमी की भूमिका में पीपली लाइव का नत्था और उसका परिवार.

एनआरआई से गुलज़ार हुआ बॉलीवुड

देश में आए आर्थिक उदारीकरण ने नया सपना दिया, अमीर बनने का सपना. देश-विदेश को समान पटल पर लाकर रखने का जिम्मा उठाया करण जौहर ने. अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में करण ने एनआरआई को इंट्रोड्यूस किया और उसे देशभक्त दिखाते हुए लोकप्रिय भी बनाया.

सौम्य क्लासिक फिल्मों का ट्रेंड

फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है ने बॉलीवुड को एक ख़ास फ्लेवर का सिनेमा दिया. इसने लड़कों के लिए अलग तरह का स्टाइल, दोस्ती का नया तरीक़ा-नई परिभाषा और महिलाओं के प्रति प्रेम का नया नज़रिया पेश किया. यह फिल्म ऐसी है कि एक दशक बाद भी इसे देखना उतना ही रोमांचकारी लगता है.

आइटम नंबर का प्रचलन

पहली बार ममता कुलकर्णी ने अपने ठुमकों से बॉलीवुड को नाच-गाने का नया कॉम्बिनेशन दिया. 1996 में आई फिल्म घातक के गीत-कोई आए तो ले जाए में आइटम नंबर करने के बाद बॉलीवुड में आइटम नंबर का ट्रेंड बन गया. उसके बाद शिल्पा शेट्टी के यूपी-बिहार लूटने से लेकर मुन्नी की बदनामी तक सभी आइटम नंबरों के लिए फिल्मों में ख़ास जगह बनी रही.

हीरो बन गया मैचो मैन

बॉलीवुड के पहले मस्कुलर यानी बलवान हीरो बने सुनील शेट्टी ने दर्शकों को ख़ूब लुभाया. मसल पावर से लैस इस तगड़ी बॉडी वाले अभिनेता को दर्शकों ने ख़ूब सराहा. यही नहीं, वह बच्चों और युवाओं के बीच भी लोकप्रिय हो गए. यह सिनेमा का सबसे वफादार दर्शक वर्ग है, यहां जो चल जाता है, वह सुपर हिट हो जाता है. इसके बाद सलमान ख़ान, रितिक रोशन और शाहरुख़ ख़ान ने भी अपनी मस्कुलर हीरो वाली छवि बना ली.

पर्दे पर लव मेकिंग

चांदनी रात में नौका विहार, छुपना-छिपाना, अठखेलियां करना आदि से हटकर रुपहले पर्दे पर प्यार के बंधन को खोला आमिर ख़ान और करिश्मा कपूर ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी से. उसके बाद तो सिल्वर स्क्रीन पर प्यार करने का तरीक़ा ही बदल गया. लिप लॉक से लेकर ओपन और एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव का ट्रेंड बन गया, जो मर्डर जैसी फिल्म में लव मेकिंग तक पहुंच गया है.

आइपीएल में इंटरेस्ट कम

फिल्मों और क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराने के बाद बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस प्रीति जिंटा बतौर होस्ट टीवी पर डेब्यू कर रही हैं. हालांकि फिल्मों की बात को वह अफवाहें बताकर आसानी से टाल जाती हैं तो आईपीएल में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने के मूड में नहीं हैं, लेकिन वह काफी अर्से बाद कैमरे के सामने आ रही हैं, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? इस सवाल पर वह कहती हैं कि आईपीएल के वक़्त मैं अपने लुक्स को लेकर कॉन्शस नहीं थी. बस जींस-टीशर्ट पहनी और चली गई टीम का हौसला बढ़ाने. इस वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था. कैमरे पर वापसी के लिए मैंने तक़रीबन आठ किलो वज़न कम किया है. क्रिकेट और एक्टिंग में से क्या ज़्यादा पसंद है? प्रीति कहती हैं कि दोनों की अपनी जगह है. जब हम एक्टर होते हैं तो सिर्फ़ अपने रोल के बारे में सोचते हैं. हमें यह चिंता नहीं होती कि फिल्म ओवर बजट हो रही है या अंडर बजट. हमें सिर्फ़ एक्टिंग, अपनी बॉडी और लुक्स की चिंता करनी होती है. जबकि क्रिकेट में होते हुए मेरे दिमाग़ में हज़ार चीजें एक साथ चलती थीं. लोकेशन, प्लेयर्स की परेशानियां और न जाने क्या-क्या. इसलिए जबसे कैमरे के सामने आई हूं, काफी रिलैक्स फील कर रही हूं. प्रीति क्रिकेट को अपने बच्चे की तरह मानती हैं. वह कहती हैं कि इसे मैंने अपनी ज़िंदगी दी है और इसे कभी नहीं छोड़ सकती. जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है और उस पर बहुत फोकस करना होता है, लेकिन जैसे-जैसे चीजें कंट्रोल में आती जाती हैं, उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है. वैसे आईपीएल में इस बार मैं उतना इन्वॉल्व नहीं रहूंगी, जितना पहले रहती थी.

दीपिका के तोहफ़े

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

फिल्म दम मारो दम में दीपिका पादुकोण द्वारा किया गया आइटम नंबर इन दिनों बेहद चर्चा में है. दीपिका इस गाने में बेहद सेक्सी लुक में नज़र आई हैं और उन्होंने इस गाने में अब तक की सबसे शॉर्ट स्कर्ट पहनी है. आज तक किसी अभिनेत्री ने इतनी छोटी स्कर्ट पहन कर डांस नहीं किया होगा. अब जब गाना ऑन एयर हो चुका है तो प्रशंसक दीपिका को इस पर रेस्पांस भी दे रहे हैं. वे इन दिनों दीपिका को ग्रीटिंग कार्ड्स, चॉकलेट, सॉफ्ट टॉयज नहीं, बल्कि स्कर्ट्स तोहफ़े में भेज रहे हैं. हाल में जब दीपिका भोपाल में फिल्म आरक्षण की शूटिंग ख़त्म करके अपने घर पहुंचीं तो वहां उन्हें तोहफ़े के रूप में नौ स्कर्ट्स मिले. इनमें से कुछ स्कर्ट्स लंबे हैं तो कुछ बहुत छोटे. इन्हें देखकर दीपिका को समझ में आ गया कि यह आइटम नंबर का ही प्रभाव है, इसलिए लोग उन्हें तोहफ़े में स्कर्ट्स भेज रहे हैं. लगता है, कुछ लोगों को दीपिका का सेक्सी लुक बेहद रास आया है तो कुछ चाहते हैं कि वह इतनी छोटी स्कर्ट न पहनें. बहुत जल्दी उन्हें इंडस्ट्री में काफी लोग पहचान चुके हैं और सराहना भी करते हैं. मशहूर फिल्म निर्माता फ़राह ख़ान का कहना है कि पहली मुलाक़ात में ही उसकी आंखों में एक चमक देखकर मुझे यक़ीन हो गया था कि यह लड़की कुछ अलग करके दिखाएगी. दीपिका की हंसी में भी एक निश्छलता थी. हालांकि ओम शांति ओम की कामयाबी ने जब उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, तब उनमें एक अजीब सा बदलाव भी मैंने महसूस किया. मुझे लगता है कि दीपिका को इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए था. कम से कम मेरे लिए तो हरगिज़ नहीं. वैसे मेरी नाराज़गी के मद्देनज़र दीपिका ने मुझसे मुलाक़ात की. मैंने उन्हें याद भी कराया था कि आईपीएल का क्रिकेट मैच देखने के लिए तो वक़्त है, पर फ़राह से मिलने के लिए नहीं. मैं तो अब फालतू हो गई हूं न. संभवत: मेरी इस शिकायत का ही असर है कि अब मेरे बर्थ डे पर मुझे विश करने का पहला एसएमएस दीपिका का ही आता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

थैंक्यू

यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी थैंक्यू रोमांस से भरी कॉमेडी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार, सोनम कपूर, बॉबी देओल, इरफ़ान ख़ान, सुनील शेट्टी, सेलिना जेटली और रिमी सेन ने अभिनय किया है. फिल्म की प्रोड्यूसर हैं ट्विंकल खन्ना और रोनी स्क्रूवाला. बॉलीवुड में कॉमेडी के लिए मशहूर निर्देशक अनीस बज़्मी की इस मल्टी स्टारर फिल्म में बॉलीवुड की दिग्गज एवं सदाबहार अभिनेत्री रेखा का मशहूर गीत-प्यार दो प्यार लो को नए रूप में डाला गया है, जो अभी से ही काफी लोकप्रिय हो चुका है. यह रोम-कॉम फिल्म विवाहेत्तर संबंधों पर आधारित है. इसमें रेखा की फिल्म जांबाज़ के गाने का रीमिक्स वर्जन सभी पुरुष नायकों के विवाहेत्तर संबंधों को प्रदर्शित करते हुए फिल्माया गया है. इसके अलावा फिल्म का एक और पंच है यानी आइटम नंबर. मुन्नी और शीला के बाद मल्लिका शेरावत अपने आइटम नंबर का तड़का लगाने के लिए इस फिल्म में रज़िया बनकर आ रही हैं. मल्लिका शेरावत आइटम गीत-रज़िया फंसी गुंडों में...में थिरकती हुई नज़र आएंगी. थैंक्यू का कुछ हिस्सा वेंकूवर में फिल्मा चुके अनीस बज़्मी फिल्म की शुरुआत से ही इसे नई जगहों पर फिल्माना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कनाडा में शूटिंग पर जोर दिया, लेकिन वहां कुछ परेशानियां थीं. दरअसल, शूटिंग के लिए इजाज़त मिलने में दिक्कत थी, लेकिन अक्षय के पास कनाडा की नागरिकता होने की वजह से आसानी से फिल्म की शूटिंग हो गई. फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा कनाडा में ही फिल्माया गया है. संगीत प्रीतम ने दिया है और गीत लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य, आशीष पंडित और कुमार ने.

राज, योगी और विक्रम नामक तीन शादीशुदा दोस्त बिजनेस पार्टनर हैं और महिलाओं में काफी रुचि रखते हैं. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफी ख़ुश है, क्योंकि उनकी बीवियों को उनके शौक के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उनके हंसते-खेलते जीवन में तब खलल पड़ जाता है, जब राज की पत्नी संजना को उस पर शक होता है और वह अपने पति की पड़ताल के लिए उसके पीछे किशन नामक जासूस लगा देती है. किशन अब तक जासूसी के ज़रिए भटके हुए पतियों को रास्ते पर लाकर शादियां बचाने का काम करता था, लेकिन वह अचानक अपनी क्लाइंट संजना से प्यार करने लगता है. किशन अपने प्यार को पाने के लिए उसके पति की सच्चाई बताकर शादी तुड़वाता है या राज को सही रास्ते पर लाता है, इसी स्थिति पर सिचुएशनल कॉमेडी का बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है. यह फिल्म आगामी आठ अप्रैल को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 04 अप्रैल–10 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

मणि ने दी

नीतीश को चुनौती

फोटो– प्रभात पाण्डेय

चौथी दुनिया के पिछले अंक में प्रेम कुमार मणि ने नीतीश को लेकर अपनी राय क्या व्यक्त की, उन्हें पार्टी से ही बर्ख़ास्त कर दिया गया. अब इसके जवाब में मणि ने तय किया है कि वह पूरे बिहार का दौरा कर लोगों को नीतीश व उनके विकास का सच बताएंगे. उन्होंने नीतीश को चुनौती दी है कि वह उनसे आमने-सामने आकर बहस करें.

सरोज सिंह

जदयू से निलंबित किए गए विधान पार्षद प्रेमकुमार मणि ने नीतीश कुमार की तानाशाही के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है. कभी नीतीश कुमार के दोस्त रहे मणि को इस बात का अफ़सोस है कि इतिहास ने नीतीश को एक मौक़ा दिया, पर दलाल व चापलूसों में घिर कर उन्होंने ख़ुद को इतिहास के कूड़ेदान के हवाले कर दिया. मणि का दावा है कि जदयू का विनाश तय है और इसकी बुनियाद स्वयं नीतीश कुमार ने रख दी है. पूरे बिहार का दौरा कर मणि बिहार के लोगों को नीतीश और उनके विकास का सच बताने वाले हैं, जबकि जदयू प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि पिछले चुनाव में प्रेम कुमार मणि की लालू प्रसाद से मिलीभगत थी. रात के अंधेरे में मणि किन-किन नेताओं के साथ बैठते थे, पार्टी को सब मालूम है. जनता ने नीतीश कुमार को दिल से स्वीकार कर पार्टी के ख़िलाफ़ काम करने वाले नेताओं को ख़ारिज कर दिया है. दरअसल मणि मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं और बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं. बिहार का विकास देश व दुनिया देख रही है. मुसलमानों के दिलों में नीतीश कुमार के लिए जो प्यार व सम्मान उभरा है, उसे देखकर कुछ नेता परेशान हैं. उनकी परेशानी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मुसलमानों ने केवल बातें बनाने वाले और काम करने वाले नेताओं की पहचान कर ली है.

पिछले दिनों अनुशासन समिति ने जिस तरह से काम किया, उसको लेकर मणि का गुस्सा सातवें आसमान पर है. वह कहते हैं कि मैं घबराने वाले लोगों में से नहीं हूं. अन्याय व भेदभाव के ख़िलाफ़ संघर्ष तो मेरी आदतों में शुमार है. नीतीश जी ने चुनौती दी है वह स्वीकार है. पूरे बिहार का दौरा कर लोगों को नीतीश व उनके विकास का असली सच बताऊंगा. जहां तक अनुशासन समिति की निष्पक्षता का सवाल है तो कोई यह बताए कि मुझे किस अपराध की सज़ा दी गई और मंत्री नरेंद्र सिंह को किस काम का ईनाम दिया गया. उनके पुत्र ने चकाई से जेएमएम से चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान नरेंद्र जी का आशीर्वाद उसे मिला. इस समिति ने उन्हें तो कोई नोटिस नहीं दिया. सांसद एन के सिंह का नाम नीरा राडिया के साथ जुड़ा, पर क्या हुआ. ऐसे कई मामले हैं जो बतलाते हैं कि कुछ ख़ास कारणों से अनुशासन समिति के निशाने पर कुछ चुने हुए नेता ही थे. मणि ने साफ़ किया कि नीतीश जी को वैसे लोग पसंद नहीं हैं जो उन्हें सच का चेहरा दिखाएं. इस मुद्दे पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि अनुशासन समिति ने पूरी निष्पक्षता से काम किया है. अगर समिति ने मणि को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

मुसलमानों के दिलों में नीतीश कुमार के लिए जो प्यार व सम्मान उभरा है, उसे देखकर कुछ नेता परेशान हैं. उनकी परेशानी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मुसलमानों ने केवल बातें बनाने वाले और काम करने वाले नेताओं की पहचान कर ली है.

नीतीश कुमार के विकास के दावे को भी मणि हवा-हवाई मानते हैं. उनकी राय में सड़क व अमन चैन के मामले में बिहार का चेहरा ज़रूर बदला, लेकिन मैं यहां लोगों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश का सबसे ज़्यादा विकास अंग्रेज़ों के राज में हुआ. रेल से लेकर तमाम विकास की बुनियाद उसी दौरान रखी गई थी. सभी महानगर व हिल स्टेशन अंग्रेज़ों ने बनवाए व विश्वविद्यालय भी बनवाए, तो क्या इस देश के लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत को स्वीकार कर लिया. नारा लगा, अंग्रेज़ों वापस जाओ. जहां तक विकास की सच्चाई की बात है तो जो ताज़ा आकंड़ें बताते हैं कि बिहार के 58 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. पिछले पांच वर्षों में ग़रीबों की संख्या सोलह प्रतिशत बढ़ गई. अब आप ही बताइए कि यह कैसा विकास है. जिस प्रदेश की आधी से अधिक आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे जी रही है तो क्या यह माना जा सकता है कि उस प्रदेश का तेज़ी से विकास हो रहा है. यह तो वही बात हुई की तबियत सुधर रही है, पर बुख़ार चढ़ रहा है. विकास का सच यह है कि मुट्ठी भर लोगों का बेतहाशा विकास हुआ और उसने ग़ैर बराबरी की खाई चौड़ी व गहरी कर दी. इस मामले में संजय सिंह कहते हैं कि जनादेश इस बात का गवाह है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के विकास को देखा और महसूस किया. दूसरे राज्य बिहार के विकास से प्रभावित होकर अपने यहां प्रदेश के कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं. मणि मानते हैं कि नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को दफ़न कर दिया. नीतीश सरकार तो रणवीर सेना के ऐजेंडे पर काम कर रही है. ग़रीबों व अमीरों की बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है. कर्पूरी ठाकुर व वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय के जिस झंडे को आसमान तक पहुंचाया, उसे नीतीश कुमार ने झुका दिया. हद तो तब हो गई जब वीपी सिंह के निधन पर बिहार में पार्टी की तरफ़ से एक शोक सभा तक नहीं हुई. मणि बिहार में भूमि सुधार को लेकर हुई राजनीति से भी काफ़ी दुखी हैं. वह कहते हैं कि भूमि सुधार इस प्रदेश की ज़रूरत है, यह बात सब लोगों को समझनी ही होगी. नीतीश कुमार ने ख़ुद मुझसे कहा था कि जो काम कम्युनिस्ट नहीं कर पाए, उसे मैं करने जा रहा हूं, मैं भूमि सुधार को लागू करने जा रहा हूं. नीतीश कुमार की इन बातों से मैं इतना रोमांचित हो गया कि इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुझसे कहा कि भूमि सुधार लागू करना संभव नहीं है. तभी मुझे लगा कि नीतीश को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का एक मौक़ा मिला जिसे उन्होंने गंवा दिया और अपना नाम इतिहास के कूड़ेदान में दर्ज करा लिया. मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार के प्रेम को भी मणि अलग नज़रिये से देखते हैं. उनकी राय में यह सब दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है. अल्पसंख्यकों की जो ज़मीनी परेशानियां हैं, वह जस की तस हैं. मैंने अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए दस सूत्री कार्यक्रम दिया था, पर उस पर अमल नहीं हुआ. मैं तो नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो नगरनौसा कांड की जांच कराएं और जिन लोगों ने मुसलमानों की ज़मीन हड़पी है, उसे उन्हें वापस दिलाएं.

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भाषण देना और सही मायनों में उनके लिए काम करना दोनों अलग-अलग बातें हैं. नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं. कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की आलीशान कोठियों में स्कूल खुलेंगे. मैं भी चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का ख़ात्मा हो. भ्रष्टाचार ऐसा वायरस है जो विकास को नष्ट कर देता है, लेकिन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का केवल नाटक किया जा रहा है. भ्रष्टाचारियों के घरों में स्कूल खोलने के वादों पर अगर नीतीश कुमार अमल करते हैं तो जिस मकान में वह ख़ुद दस साल से रह रहे हैं, उसमें स्कूल खोलें. उसमें तो यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है. इंटरनेट पर संपत्ति का ब्योरा दिया जा रहा है, अरे कोई अपनी नाजायज़ संपत्ति का ब्योरा इंटरनेट पर देगा क्या. दूसरे दलों के नेताओं को जदयू में शामिल करने के नीतीश के फ़ैसले पर भी मणि ने उंगली उठाई है. वह कहते हैं कि आप आने वाले लोगों पर ग़ौर कीजिए. राजद से कौन लोग आए. तस्लीमुद्दीन, श्याम रजक और रमई राम जैसे लोग. रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह या फिर अब्दुल बारी सिद्दीक़ी जैसे लोग नीतीश के साथ नहीं आए. दरअसल उनके साथ वे लोग ही आ रहे हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दलालों व चापलूसों की बड़ी फ़ौज से वह घिर गए हैं. नीतीश के नाम पर ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर मुझसे आमने सामने बहस करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि न्याय के साथ विकास का जो सपना हम लोगों ने देखा था वह किस तरह चूर-चूर हो रहा है. देखें तो मणि के अपने तर्क हैं और जदयू के अपने दावे. दोनों ने अपना अपना फ़ैसला कर लिया है. लगता है पंचायत चुनाव के बाद बिहार एक ज़बरदस्त राजनीतिक संग्राम का गवाह बनने वाला है.

feedback@chauthiduniya.com

मणि का दर्द

प्रेम कुमार मणि

- नरेंद्र सिंह व एन के सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं
- नीतीश ने दफ़न कर दिया सामाजिक न्याय के आंदोलन को
- हिम्मत है तो नगरनौसा कांड की जांच कराएं
- रणवीर सेना के एजेंडे पर काम कर रही सरकार
- नीतीश के पूर्व मकान में खुल सकती है यूनिवर्सिटी
- दलालों व चापलूसों से घिर चुके हैं नीतीश कुमार
- भूमि सुधार पर अपनी बात से पलट गए मुख्यमंत्री

जदयू के तीर

संजय सिंह

- प्रेमकुमार मणि चुनाव में लालू से मिले हुए थे
- किन-किन नेताओं के साथ बैठते थे, सब पता है
- मानसिक तौर पर पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं
- बिहार का विकास देश और दुनिया देख रही है
- मुसलमानों के दिलों में नीतीश के लिए प्यार व सम्मान
- मणि को अनुशासन समिति के सामने पेश होना चाहिए
- पूरा बिहार नीतीश कुमार के विकास के साथ

एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट में इसका ख़ुलासा हो चुका है. इनका मुख्य उद्देश्य अब आतंक फैलाकर धन इकट्ठा करना बन चुका है. अफ़ीम व कोयला तस्कर माओवादियों के भामाशाह बन चुके हैं.

प्राकृतिक संपदा में देश-विदेश के पक्षियों और जंगली जानवरों ने अपना रैन बसेरा बना रखा है. सत्तर के दशक के बाद दस्यु सरगनाओं ने भी अपने छिपने का ठिकाना बना रखा था.

एक नज़र

बाबा के भक्तों को महाप्रसाद मिलेगा

द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम में अब आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर प्रबंधन बोर्ड की ओर से महाप्रसाद मिलेगा. बोर्ड की ओर से फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रसाद वितरण सेवा (लंगर) का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर बोर्ड के सचिव सह उपायुक्त मस्तराम मीणा, बोर्ड के सदस्य व पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा, मेयर राजनारायण खवाड़े, उप मेयर संजयानंद झा, तारानंद जैन, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष विनोद दत्त द्वारी सहित कई गणमान्य नागरिक एवं ज़िले के पदाधिकारी उपस्थित थे. समारोह में उपस्थित पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने कहा कि वैष्णो देवी एवं तिरुपति की तरह बाबाधाम में कभी दिनों से लंगर प्रारंभ करने का सपना आज पूरा हो रहा है. लंगर सेवा का लाभ बाबाधाम में आने वाले सभी श्रद्धालु ले सकेंगे. लंगर सेवा शिवगंगा के निकट मानसरोवर तट पर प्रारंभ की गई है. *-रंजीत झा*

दरभंगा के हीरालाल सहनी सम्मानित

हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्रदान करने के अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास की ओर से दरभंगा के स्थानीय साहित्यसेवी डॉ. हीरालाल सहनी को सम्मानित किया गया. राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉ. सहनी की भूमिका इस क्षेत्र में सराहनीय है. स्थानीय स्तर पर साहित्यिक गतिविधियों को जीवंत बनाए रखने में उनका सक्रिय योगदान है और वह बाहर भी विभिन्न साहित्यिक समारोहों में शिरकत करते रहे हैं.

लेहरियासराय-दरभंगा रोड ख़तरनाक

लेहरियासराय से दरभंगा को जोड़ने वाली शहर की मुख्य पथ अब हादसे को न्योता दे रही है. वीआईपी रोड में म्यूज़ियम गुमटी के मुख्य पथ से सटे रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे के नीचे डालने वाला स्लीपर विगत कई माह से गिराकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमेशा कोई न कोई दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. स्लीपर का आधा भाग मुख्य पथ की तरफ़ निकला हुआ है, जो गंभीर दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है. किंतु इस ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है.

डॉ. प्रकाश नायक का शोध रंग लाएगा

आर. के. कॉलेज मधुबनी के भौतिक विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश नायक के प्रस्तावित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट-स्टडी आफ फोटोनिक बैंड गैप मेटेरियल्स फार द यूज ब्राडबैंड माइक्रोवेब एंटीना का चयन किया गया. इस पर शोध के लिए चार लाख इकसठ हज़ार रुपये की राशि आवंटित की गई है. साथ ही आठ हज़ार रुपए प्रति माह के मानदेय पर तीन वर्षों के लिए प्रोजेक्ट फेलो रखने की अनुमति प्रदान की है. डॉ. नायक ने बताया कि उनका यह शोध दूरसंचार के आज के इस युग की बढ़ती मांग को पूरा करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन ब्रॉडबैंड के ज़रिए होता है, जिसमें एंटीना का डिज़ाइन एक महत्वपूर्ण कड़ी है. फोटोनिक बैंड गैप स्ट्रक्चर के अध्ययन द्वारा एंटीना की दक्षता को बढ़ाना शोध का मुख्य लक्ष्य होगा.

लावारिस बच्ची को अपनाया

किसी ने फेंका, किसी ने अपनाया. मधुबनी में नवजात बच्ची को तलाब में फेंकने से यह चर्चा पूरे प्रखंड में फैली हुई है. बच्ची पर मोहनपुर गांववासी शोभाचंद्र की पत्नी दुर्मिला देवी ने अपनी ममता दिखाते हुए उसे गोद लिया. शोभाचंद्र ने पोखर जाने के दौरान देखा कि कौए की कांव-कांव के बीच एक बच्ची रो रही है. नज़र पड़ते ही वह बच्ची को उठाकर अपनी पत्नी दुर्मिला को सौंपते डॉक्टर से जांच करवाई. डॉ. आरपी ने कहा कि बच्ची स्वस्थ है. दुर्मिला को पहले से दो पुत्र हैं. बच्ची को पाकर वह फूले नहीं समा रही है. मज़दूरी कर जीवन चलाने वाली दुर्मिला ने कहा कि इस बच्ची को पढ़ाकर एक नेक इंसान बनाएंगी.

किसान मालामाल होंगे

मुंगेर के नगरवासियों की स्वास्थ्य-रक्षा के साथ-साथ अब रामपुर, इंद्ररूख, वलीपुर और फ़रीदपुर के आसपास के किसान मालामाल होंगे. लगभग 1500 हेक्टेयर खेतों में जैविक खाद उपलब्ध कराने से यह विधि उनकी आय का ज़रिया बन जाएगा. मुख्य कारख़ाना प्रबंधक अशोक कुमार मंडल के प्रयास से आमजन को पौष्टिक दूध भी मिल सकेगा. खेतों में रबी की फ़सल होने पर बंजर भूमि उर्वरक हो जाएगी. कारख़ाने के मुख्य चिकित्सक डॉ. एके चौरसिया के नेतृत्व में रामपुर टंकी मैदान व रेलवे कॉलोनी के नाले की सफ़ाई से नगरवासियों की स्वास्थ्य-रक्षा होगी. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

Estd 2000

- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

माओवादियों के नए-नए धंधे

नवल किशोर सिंह

माओवादी संगठन के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं. जानकारी के मुताबिक़ माओवादियों ने अगले वित्तीय वर्ष का अपना बजट बनाया है. इसमें संगठन के अंदर विभिन्न विभागों के लिए राशि का आवंटन किया गया है. सबसे ज़्यादा राशि रक्षा विभाग को आवंटित की गई है. पूरा बजट समानांतर सरकार चलाने का संकेत देता है. यह बजट 5 हज़ार करोड़ का है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे किस स्तर पर लेवी वसूल रहे हैं. सवाल है कि यह राशि सिर्फ़ समर्थकों के चंदे से एकत्र नहीं होती है या हो सकती है. वे समाज के जिस वर्ग को न्याय और न्यायोचित अधिकार दिलाने के संघर्ष के नाम पर गोला-बारूद की खेती कर रहे हैं, आतंक का राज क़ायम कर रहे हैं, उसके लिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करना भी कठिन है. ज़ाहिर है कि कोष संग्रह के लिए इससे इतर स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि वे जिस वर्ग का फ़ौजदार होने का स्वांग रचते हैं, उसके बुनियादी सवालों को लेकर कभी आवाज़ तक नहीं उठाते. उल्टे उसे अपना कोपभाजन बनाते हैं. नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले लोगों का यदि वर्गीय विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि अधिकांश लोग इसी आर्थिक वर्ग से आते थे, जिनकी नुमाइंदगी का वे दावा करते हैं. इनकी सहानुभूति आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की अपेक्षा ठेकेदारों, बिचौलियों भ्रष्ट नौकरशाहों, दो नंबरी व्यवसायियों के प्रति कुछ ज्यादा है. हाल में लातेहार में नरेगा में होने वाली गड़बड़ियों पर नज़र रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता लियाक़त अंसारी को माओवादियों ने घर से खींचकर पीट-पीटकर मार डाला. वह कौन सा जनविरोधी काम कर रहा था. ग़रीब वर्ग को मनरेगा का पूरा लाभ मिले, इसके लिए वह जनता को जागरूक कर रहा था. इससे नक्सलियों को क्या परेशानी हो सकती थी. परेशानी तो ठेकेदारों, बिचौलियों और भ्रष्ट अफ़सरों को थी. उनकी परेशानी दूर करने में माओवादियों की दिलचस्पी का कारण ढूंढा जाए तो नक्सली आंदोलन के मौजूदा भटकाव को रेखांकित किया जा सकता है.

माओवादियों को लेवी के रूप में बड़ी रक़म देने वाले आर्थिक लुटेरे ही हो सकते हैं, मेहनत-मज़दूरी कर जीवन-यापन करने वाले नहीं. आर्थिक लुटेरों के वित्त-पोषण के ज़रिये, उनके लठैत की भूमिका में आकर ये इस देश में कौन-सी क्रांति लाना चाहते हैं. प्राय: ग़रीब वर्ग के लोगों की हत्या का औचित्य सिद्ध करने के लिए वे उन्हें पुलिस का मुखबिर घोषित कर देते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी हत्या नहीं की जिसका निशाना समाज का कोई बहुत बड़ा शोषक या दबंग किस्म का व्यक्ति हुआ हो या जिसके मारे जाने के बाद आम जनता ने राहत की सांस ली हो.

सच्चाई यह है कि कम से कम झारखंड में सभी अवैध धंधों में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी हो चुकी है. विकास योजनाओं की राशि में एक ख़ास प्रतिशत लेकर वे प्रखंड स्तरीय भ्रष्टाचार के तंत्र को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं. कोयला, लोहा, केंदु पत्ता, कत्था आदि के अवैध व्यवसाय में उनका हिस्सा तय है. उनके संरक्षण के बिना ये धंधे नहीं चल सकते. उनके प्रभाव के 11 ज़िलों में अफ़ीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है. एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट में इसका ख़ुलासा हो चुका है. उनका मुख्य उद्देश्य अब आतंक फैलाकर धन इकट्ठा करना बन चुका है. अफ़ीम व कोयला तस्कर माओवादियों के भामाशाह बन चुके हैं. अवैध धंधों से जमा की गई राशि ने उनके संगठन के अंदर वित्तीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है. एरिया कमांडर और अन्य ज़िम्मेवार पदधारी नक्सलियों के लेवी का पैसा लेकर भाग जाने की ख़बरें आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं. जिन सिद्धांतों को लेकर उनका संघर्ष शुरू हुआ था अब वह पीछे छूट गए हैं. फ़ौजी दस्ते जब राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो उनके आपराधिक गिरोह में तब्दील हो जाने की आशंका रहती है. झारखंड के माओवादियों के साथ संभवत: यही हुआ है.

उधर सरकार के आपरेशन ग्रीन हंट चलाने की घोषणा अब चर्चा से बाहर हो चुकी है. झारखंड सरकार के अंदर भी माओवादियों के संरक्षक अच्छी तादाद में मौजूद हैं. वे परोक्ष रूप से इन्हें सरकारी व पुलिसिया कार्रवाई से बचाने और नक्सल विरोधी अभियान की गति धीमी रखने का प्रयास कर रहे हैं. कई राजनीतिक दलों के नेता इनके प्रति नरम रुख़ रखते हैं. नक्सली हिंसा से निबटने में यह एक बड़ी बाधा है.

feedback@chauthiduniya.com

पंचायती राज व्यवस्था का मज़ाक़

पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, उसका ज़मीनी सच किसी से छुपा नहीं है. दरभंगा ज़िले के बिरौल प्रखंड स्थित रामनगर पंचायत के मुखिया ने पंचायती राज व्यवस्था का ऐसा हश्र किया, जिसे किसी ने सोचा तक नहीं होगा. मुखिया ने तीन-तीन नामों पर सरकारी लाभ हासिल करके पंचायती राज व्यवस्था का मज़ाक़ उड़ाया है. बीते पांच वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था का क्या हश्र हुआ, इसका जीता-जागता उदाहरण है दरभंगा ज़िले की रामनगर पंचायत. इस पंचायत के मुखिया ने पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर लीं. मुखिया ने तीन नामों पर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया और वहीं एक ही कार्य को कई योजनाओं से करके भारी लाभ कमाया. इस मामले में मुखिया पर जांच भी बैठी और यह बात सच साबित होने पर तत्कालीन ज़िलाधिकारी ने मुखिया पर कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन जब तक कार्रवाई होती, तब तक पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया और मुखिया एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में लग गए.

ज़िला मुख्यालय से करीब 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरौल प्रखंड क्षेत्र के रामनगर पंचायत में इंदिरा आवास, मनरेगा, बीआरजीएफ, बारहवें वित्त आयोग, शिक्षक नियोजन आदि योजनाओं में मुखिया पर भारी अनियमितता बरतने का मामला सालों भर चर्चा में रहा. मनरेगा योजनाओं में वर्ष 2006-07 से लेकर 2010-11 तक लाखों रुपये की अवैध राशि की निकासी होने की जांच स्थानीय लोगों ने निगरानी विभाग से कराने की मांग की. तत्कालीन एसडीओ ने जांच करने के लिए डीडीसी को प्रतिवेदन भी भेजा, लेकिन डीडीसी ऑफिस में उक्त फाइल को दबा दिया गया. इस पंचायत में वर्ष 2007-08 में एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही योजना को दो बार करने, पुन: अगले वित्तीय वर्ष में दूसरी योजना के तहत सड़क निर्माण दिखाकर लगभग 10 लाख रुपये की राशि को बंदरबांट करने, मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2007-08 में एहसान खां के घर से पटनियां स्कूल तक मिट्टी-खरंजा कार्य योजना संख्या 26 दिखाकर 2.50 लाख रुपये उठा लेने, फिर उसी सड़क में नेहाल खां के घर से साहेबान चौक तक मिट्टी खरंजा कार्य मनरेगा योजना संख्या: 18 से 30 के तहत दो बार करने और 94-94 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान पाने, उसी सड़क पर योजना संख्या-10 के नाम पर पुन: 34 हज़ार रुपये की निकासी कर लेने का आरोप लगाया गया. मनरेगा के तहत इस मार्ग पर लगभग 5 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई. ठीक एक वर्ष बाद उसी मार्ग पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से आरसीसी निर्माण कर 4 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया. इसी योजना के तहत साहेबान चौक से सड़क तक मिट्टीकरण योजना के प्राक्कलन से चार गुना अधिक योजना संख्या-35 सुरा पोखर से करहरी मुख्य सड़क तक मिट्टीकरण का भुगतान किया गया. योजना का प्राक्कलन 24,420 रुपये का ही था,

रामनगर पंचायत

अरुण महतो

जबकि भुगतान 1 लाख 14 हज़ार रुपये का किया गया. मनरेगा मज़दूरों के निबंधन में भी भारी गोल-माल का मामला उभरा, जिसमें एक ही निबंधन संख्या पर दो अलग-अलग समुदाय के मज़दूरों के नाम अंकित करके भारी लाभ उठाने का मामला भी प्रकाश में आया. मनरेगा कार्यालय के रिकॉर्ड्स व पंचायत के अहिलवाड़ा डाकघर में कुल 817 जॉब कार्डधारियों का खाता खोला गया, परंतु पंचायत में कई मज़दूरों ने शिकायत की है कि उनके खाते से फ़र्ज़ी निकासी कर ली गई. अधिकांश मज़दूर तो ऐसे हैं, जिनके पासबुक उनके पास है फिर भी राशि की निकासी हो गई. पंचायत के लालो यादव का खाता संख्या-1254287 है, इसमें 2296 रुपये जमा हैं, फिर अन्य खाता संख्या-1801887 से लालो यादव के खाते से पैसे की निकासी होने का मामला सामने आया. इतना ही नहीं इंदिरा आवास योजना में बीपीएल अंक-4 वाले लाभार्थियों की संख्या अधिक है, फिर भी 8 से लेकर 13 अंक वाले बीपीएल लाभार्थियों को अवैध राशि लेकर लाभ देने का मामला सामने आया. इस संबंध में डीडीसी दरभंगा द्वारा बीडीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया. फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ. बाढ़ से निजात के लिए पंचायतों को दो-दो नाव ख़रीददारी का निर्देश मिला, लेकिन इस पंचायत में काग़ज़ पर ही नाव की ख़रीददारी कर ली गई. इस पंचायत के अहिलवाड़ा पंचायत टोल में पूर्व सांसद के एच्छिक कोष से दस वर्ष पूर्व बनाए सामुदायिक भवन के नाम पर निर्माण दिखाकर 98 हज़ार रुपये की निकासी करने का मामला भी प्रकाश में आया. पंचायत के मुखिया ने अपने तीन नामों का अभिलेखीय उपयोग कर पांच वर्षों में लाखों रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली. जब सीट आरक्षित हुई तो मुखिया अरुण महतो पंचायत में ही शिक्षामित्र से इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़ते हुए विजयी हुए और उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से जो अपनी चल-अचल संपत्ति घोषित की, तब की और आज की संपत्ति पर नज़र डालें तो मात्र पांच वर्षों में ही मुखिया की हैसियत तीन सौ गुना बढ़ गई है. उन्होंने मुखिया बनने के बाद अपने तीनों नाम अरुण महतो, अरुण कुमार महतो, पिता गंगो महतो और अरुण कुमार चौधरी, पिता गंगा चौधरी का इस्तेमाल कर ख़ूब लाभ उठाया. जब प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया, तब जाकर तत्कालीन डीएम संतोष कुमार मल्ल द्वारा लगभग पंद्रह महीने बाद पंचायती राज के प्रधान सचिव को इस मुखिया को पदच्युत करने हेतु प्रतिवेदन भेजा है. सच तो यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जनता मालिक होते हुए भी कंगाल हो गई और कई जनप्रतिनिधि कंगाल होते हुए भी मालामाल हो गए.

मीनाक्षी
feedback@chauthiduniya.com

नलकूप बंद, खेती चौपट

सुशासन की सरकार में कृषि के विकास के लिए किए जा रहे दावों की सच्चाई यह है कि बक्सर ज़िले में कुल 199 राजकीय नलकूपों में 161 नलकूप वर्षों से बंद पड़े हैं. वहीं नाबार्ड द्वारा लगाए गए 78 नलकूप बिजली के अभाव में दो साल से चालू नहीं हो रहे हैं. इसका सबसे ज़्यादा असर खेतों की सिंचाई पर पड़ रहा है.

धान का कटोरा कहे जाने वाले बक्सर ज़िले में परंपरागत तथा आधुनिक सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. इसका सीधा असर ख़रीफ़ तथा रबी की फ़सलों के उत्पादन पर पड़ रहा है. भले ही बिहार का आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन खेती पर निर्भर रहने वाली 85 प्रतिशत आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ती जा रही है. यही वजह है कि किसान खेती से मुंह मोड़ने लगे हैं. खेती की आधारभूत संरचना ध्वस्त हो गई है. वर्षों पूर्व लगे राजकीय नलकूपों में मात्र 38 नलकूप ही चालू हैं. शेष 161 राजकीय नलकूप पिछले 20-25 वर्षों से बंद पड़े हैं. कहीं मोटर नहीं है, कहीं बिजली के अभाव से बंद हैं तो कहीं तकनीकी गड़बड़ी है. किसान अधिकारियों के पास दौड़ लगाकर थक गए, लेकिन सुशासन की सरकार में बंद नलकूप चालू नहीं हुए. इतना ही नहीं सिंचाई के लिए बक्सर ज़िले में करोड़ों रुपये ख़र्च कर 78 नए नलकूप लगाए गए. इसके लिए हौज़ तथा सिंचाई के लिए नालों का निर्माण भी किया गया. इसको चालू करने के लिए विद्युत विभाग में 57 लाख रुपये जमा भी कर दिए गए, लेकिन दो साल बाद भी विभाग द्वारा नलकूपों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया. किसान इसके लिए भी दौड़े, पर विभाग के अधिकारियों ने तार-पोल न होने की बात कहकर किसानों को टरका दिया. नाबार्ड द्वारा ख़र्च किए गए करोड़ों रुपये का सच यही है कि किसानों को दो वर्षों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. उधर, नलकूप लगाने के लिए किसान अपनी ज़मीन देकर अफ़सोस कर रहे हैं. कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी प्रो. बलिराज ठाकुर बताते हैं कि कृषि के विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सुशासन की सरकार की घोषणाएं झूठी हैं. नलकूप के करोड़ों रुपये बेकार हो गए, पर लापरवाह नौकरशाहों ने किसानों की पीड़ा नहीं सुनी. ज़िले में नलकूप विभाग के मुलाज़िमों के वेतन पर सरकार करोड़ों रुपये ख़र्च कर रही है. दूसरी ओर वर्षों से बंद पड़े नलकूपों पर ऑपरेटर बैठे-बैठे अपना वेतन ले रहे हैं. यही वजह है उत्पादन साल दर साल कम हो रहा है.

जय मंगल पाण्डेय
feedback@chauthiduniya.com

सरेयामन झील उपेक्षा से बदहाल

पश्चिम चंपारण ज़िला मुख्यालय बेतिया के नज़दीक कुछ मील दूरी पर स्थित बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना क्षेत्र अंतर्गत सरेयामन झील व उदयपुर जंगल पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार का अब ध्यान नहीं रहा. यह वही स्थल है जहां देश की आज़ादी के लिए भारत के नामचीन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कमल नाथ तिवारी, केदार मणि शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांति का ताना बाना बुनते थे. प्राकृतिक संपदा से हरा भरा यह क्षेत्र कश्मीर की डल झील की तरह होते हुए भी उपेक्षा झेल रहा है. एक समय था जब बेतिया राज के महाराजा रोज़ सुबह इस झील का ताज़ा पानी मंगाकर पीते थे. इस पानी से उनका पाचनतंत्र मज़बूत होता था. इस प्राकृतिक संपदा में देश विदेश के पक्षियों और जंगली जानवरों ने अपना रैन बसेरा बना रखा है. सत्तर के दशक के बाद दस्यु सरगनाओं ने भी अपने छिपने का ठिकाना बना रखा था. प्राचीन समय से लेकर अब तक देश विदेश के पक्षी हज़ारों मील उड़ान भरके अक्टूबर माह से लेकर फ़रवरी माह तक अपना रहने का आशियाना बनाते हैं. यहां के मनोरम दृश्य को देखकर बिहार सरकार ने पक्षी अभ्यारण अस्सी के दशक में घोषित किया. पक्षी अभ्यारण घोषित करने के लिए तो कर दिया गया, किंतु उसके बाद कुछ नहीं हुआ. अगर पर्यटन दृष्टिकोण से सरकार ध्यान दे तो पहले से ज़्यादा पर्यटक यहां आएंगे और सरकार के राजस्व में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी.

सरेयामन झील और उदयपुर जंगल प्राचीन संपदाओं से हरा भरा क्षेत्र है. इसके आस पास के क्षेत्रों में लौरिया के नंदनगढ़, चानकीगढ़, सहोदरा स्थान, बाल्मीकि स्थान, माता सीता की तपो स्थली, सोमेश्वर स्थान और श्रृंखलाबद्ध इसकी पहाड़ियां मौजूद हैं. बेतिया राज के महाराजा और रानी भी किसी ख़ास उत्सव पर यहां आते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां उचित देखरेख न होने से पक्षियों की संख्या में कमी आई है. यहां के लोगों को इस बात का दुख है कि सुशासन की सरकार में भी इस अभ्यारण के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के निदेशक बी चंद्रशेखर बताते हैं कि 2009-10 सत्र में 38 लाख रुपये का प्रतिवेदन विकास करने के लिए बिहार सरकार के पास भेजा गया था. जिस पर कार्यवाही अविलंबित है. वहीं चंपारण साहित्य परिषद के महासचिव अखिलेश ठाकुर का कहना है कि इसके विकास के लिए बिहार सरकार को एक पैकेज जारी करना चाहिए.

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

सावधानी न बरती तो खगड़िया जलकर राख हो जाएगा

राजेश सिन्हा

सूबे में सबसे अधिक पिछड़ा इलाक़ा खगड़िया अग्निकांड के मामले में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला ज़िला है. लगभग प्रतिवर्ष दर्जनों घर जलकर ख़ाक हो जाते हैं. घटना के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और मातमपुर्सी के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं. राहत के नाम पर प्रभावित परिवार के लोगों के हाथों में चंद रुपये और कुछ मुट्ठी अनाज थमा दिया जाता है, लेकिन अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के मामले में अपने भोथरे हो चुके हाथों से कुछ भी करना नहीं चाहते हैं. इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि सात नदियों से घिरे इस ज़िले के लोग अग्निकांड के समय पानी-पानी के लिए तरस जाते हैं. अग्निशमन विभाग की व्यवस्था से दहशतज़दा लोगों का कहना है कि अगर कभी भीषण अग्निकांड की घटना घटी तो जलकर राख हो सकता है खगड़िया! कई बार अग्निदेव के रौद्र रूप को देखकर सिहरने वाले लोगों की सिहरन अभी से बढ़ गई है. अग्निकांड की घटना होने पर आग पर क़ाबू पाने वाला विभाग भी बौना पड़ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि खगड़िया का अग्निशमन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है. विभाग के पास न ही पर्याप्त मात्रा में दमकल गाड़ियां हैं और न ही कर्मचारी. बावजूद इसके यह अलग बात है कि पूरे ज़िले के लोगों को अग्निदेव के प्रकोप से बचाने का भरपूर दावा अब तक किया जाता रहा है. पिछले वर्ष भी प्रशासनिक पदाधिकारी दुरुस्त अग्निशमन व्यवस्था का ढोल पीटते रहे, लेकिन दर्जनों बस्तियां जलकर राख हो गईं. लाखों रुपये की संपत्ति बर्बाद हुई, व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति भी हुई. दमकल की गाड़ियां या तो पहुंची नहीं और अगर पहुंची भी तो गांव-गांव जलकर राख हो चुके थे. लगभग सभी अग्निकांड की घटनाओं के समय दमकल की गाड़ियों में पानी का टोटा पड़ गया था. विभागीय अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ज़िले में महज़ एक ही पानी टंकी रहने के कारण पानी का टोटा पड़ जाता है. बावजूद इसके प्रशासनिक अमलों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है. नतीजतन आज भी अग्निशमन विभाग बदहाल है. बार-बार मिल रही शिकायत की सत्यता के लिए चौथी दुनिया द्वारा विभागीय व्यवस्था का मुआयना किया गया. शहर से लगभग दो किलोमीटर दूर बाज़ार समिति प्रांगण में फायर स्टेशन, खगड़िया का बोर्ड लगा था और कार्यालय के बाहर एक छोटी अग्निशमन गाड़ी सहित तीन दमकल की गाड़ियां लगी थी. दमकल गाड़ियों की हालत के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया गया कि तीन वाहनों में से दो बेहतर स्थिति में हैं, जबकि एक वाहन ख़राब है. अधिक जर्जरता के कारण वाहन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उनके पास अपना कार्यालय भवन भी नहीं है. कई माह से वेतन के लिए लालायित कर्मचारियों का कहना था कि भूखे पेट ही सही सभी विभागीय कर्मी आग पर क़ाबू पाने के मामले में पीछे नहीं हटते, लेकिन बिना पानी के आग पर क़ाबू पाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह बताने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है. कार्यालय प्रभारी आरएन रजक ने बताया कि महज़ दो दमकल गाड़ियों के दम पर दो अनुमंडल और सात प्रखंड के लोगों को आग से होने वाले जान-माल की क्षति से बचाना कितना संभव है! वैसे भी सृजित पद के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति न होने के कारण चार गृह रक्षकों से सहयोग लिया जा रहा है. इन प्रशिक्षित जवानों को जब तक थोड़ा बहुत प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तब तक उनका स्थानांतरण हो जाता है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक दिक्क़त तब आती है जब आवश्यकता के समय पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है. खगड़िया शहर में एक ही पानी टंकी है. लगभग एक माह से शहर के पानी टंकी का नल ख़राब पड़ा था. पीएचडी विभाग के अधिकारियों से जब नल ठीक कराने की गुहार लगाई गई तो उन्होंने कहा कि विभाग को इसके लिए लिखा गया है, राशि आवंटित होते ही नल ठीक करा दिया जाएगा. हालांकि जब इस बात की जानकारी नवपदस्थापित ज़िलाधिकारी को मिली तो उन्होंने त्वरित गति से इसे ठीक कराया. कार्यालय प्रभारी रजक का कहना था कि अगर ज़िले को अग्निदेव के कोप से सुरक्षित रखना है तो सर्वप्रथम वाहनों की संख्या में इज़ाफ़ा करते हुए जगह-जगह पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए. अगर संभव हो तो कार्यालय परिसर में ही पानी टंकी की व्यवस्था की जाए, ताकि जब ज़रूरत पड़े, पानी की व्यवस्था हो जाए. बहरहाल, गर्मी के मौसम में पछुआ हवा को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा अग्निशमन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा या नहीं, यह तो प्रशासनिक पदाधिकारी ही जानें. लेकिन इतना तय है कि इस वर्ष भी अग्निशमन व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो कई परिवार न केवल अपना आशियाना गंवाने के लिए मजबूर होंगे बल्कि अपनों को खोएंगे भी.

feedback@chauthiduniya.com

हम मकान नहीं घर बनाते हैं...

Yash Raj Enterprises Pvt. Ltd.

excellence in Real Estate...

An ISO 9001:2008 Certified Company

• PROMOTER • DEVELOPER • MARKETER • SERVICE PROVIDER

9234601786, 9234602786, 9234603786

E-mail: yashraj221@gmail.com

Website : www.yashrajenterprises.com

एक नज़र

हैप्पी साइंस का फैलता संसार

सूर्य और जीवन की नई व्याख्या करने वाले जापान के आध्यात्मिक गुरु रयूहो ओकावा के हैप्पी साइंस का संसार तेज़ी से फैलता जा रहा है. भारत में भी आध्यात्मिक गुरु मास्टर ओकावा के विचार, उनकी संस्था हैप्पी साइंस के कार्यों से प्रभावित होकर हज़ारों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं. विगत 6 मार्च को तथागत् की तपोभूमि बोधगया के ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में हैप्पी साइंस की भारत बोधगया शाखा द्वारा बंसत उत्सव में आध्यात्मिक गुरु ओकावा का प्रवचन सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, तब लगा कि हैप्पी साइंस और ओकावा के अनुयायी तेज़ी से भारत में ही बढ़ रहे हैं. *-सुनील सौरभ*

बिजली के बिना उद्योग कैसे चलेगा

बिहार में विद्युत व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर प्रोवेन्सियल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सह उत्तर बिहार के महासचिव उदय शंकर जायसवाल ने गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस हालत में उद्यमियों को बिहार में पूंजी निवेश कर पाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिजली के सवाल पर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और केन्द्र मूक दर्शक बना है. जायसवाल ने बताया कि जनरेटर के सहारे उद्योग चला पाना मुश्किल है. उन्होंने यह भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज किसानों की हितकारी व संरक्षक संस्था है, इसके बावजूद सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे में किसानों की भलाई सोचना बेवक़ूफ़ी है.

कुष्ठ रोगी रविंद्र को न्याय नहीं मिला

महनार प्रखंड के चमरहरा गांव निवासी कुष्ठ रोगी रविंद्र सिंह के साथ समाज के अलावा सरकार भी अछूत व्यवहार कर रही है. रविंद्र सिंह आज से 25 वर्ष पूर्व कुष्ठ से पीड़ित हुए, कई जगह दिखवाया पर लाभ नहीं हुआ. वर्तमान में वह मुजफ्फ़रपुर तक गए, किंतु सरकार के कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाने वालों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया. आस-पास के लोगों के ताने सुन कर रविंद्र सिंह ने गांव से दूर अपनी झोपड़ी बसा ली तथा अघोषित सामाजिक बहिष्कृत जीवन व्यतीत करने लगा. कुछ जागरूक लोगों ने उसे नरेगा के तहत काम भी दिलवाया, परंतु रविन्द्र का आरोप है कि उचित मज़दूरी नहीं मिली और एक दलाल ने कमीशन खा लिया है. इस संबंध में नरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच करवाई जाएगी.

समाजसेवा के जुनून में मुखिया जी कुंवारे हैं

समाजसेवा का जुनून एक मुखिया पर इस क़दर सवार हुआ कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपना जीवन आमजन के नाम कर दिया है. वैशाली ज़िले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड अंतर्गत पोहियार पंचायत के मुखिया शिवकुमार उर्फ़ मंटु सिंह प्रथम बार 2001 में मुखिया बने तथा उन्होंने ग्रामीणों की कष्टदायक स्थिति देख कर विवाह न करने का निर्णय ले लिया एवं समाजसेवा में लीन हो गए. उनकी त्याग भावना को देखते हुए गांव वालों ने 2006 में उन्हें पुन: मुखिया चुना. वर्तमान में मंटु सिंह 38 वर्ष के हो चुके हैं तथा अभी भी अपने प्रतिज्ञा पर अड़े हैं. हालांकि गांव के कई लोगों की राय है कि मुखिया जी को अब घर बसा लेना चाहिए. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

महनार की गंदगी पर नगर पंचायत मौन

महनार नगर पंचायत की स्थिति देखकर लोग यही टिप्पणी दे रहे हैं कि सिर्फ़ लेना जानती है देना नहीं जानती. यह संस्था महनार नगर की हृदय स्थली मदन चौक कचरे के ढेर से पटा है. स्टेशन रोड के दो नाले भरे हैं और सड़क पर पानी बह रहा है. न्यू रोड में भी यही स्थिति है और सृष्टि कंप्यूटर के निकट सड़क पर गंदा पानी बह रहा है. पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर कचरे से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली मानो यह कर्मी-पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं. विदित हो कि नगर पंचातय की टैक्स द्वारा लाखों रुपये वार्षिक आय है. *-अंजुम परवेज़*

प्रधानाध्यापक को शिक्षा रत्न और गोल्ड मेडल

संभवत: सूबे का इकलौता वित्त रहित विद्यालय है, जहां के प्रधानाध्यापक कैलाश सिंह को बालिका शिक्षा में बढ़ावा दिए जाने के कारण ही शिक्षा रत्न तथा गोल्ड मेडल के अवार्ड से नवाजा गया. बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर प्रखंड के दियारा क्षेत्र के बलुआं गांव में बी.के.डी.डी. बालिका उच्च विद्यालय की 1982 में स्थापना कर प्रधानाध्यापक कैलाश सिंह ने हज़ारों बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य किया. वित्त रहित विद्यालय को स्थापना की अनुमति भी प्राप्त है. दियरा क्षेत्र में लगभग 30वर्षों से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने को एवज में ही इंडियन इकोनोमी डेवलपमेंट एसोसिएशन (इडरा) दिल्ली द्वारा प्रधानाध्यापक कैलाश सिंह को संयुक्त रूप से शिक्षा रत्न तथा गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया. दिल्ली में ही एक समारोह में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति तथा पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह द्वारा यह सम्मान दिया गया. वहां से लौटे प्रधानाध्यापक सिंह ने बताया कि इस अवार्ड से बालिक शिक्षा के विकास तथा महिला सशक्तिकरण के साथ ही विद्यालय में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है. मेरा प्रयास है कि इस दिशा में अधिकाधिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं. *-जयमंगल पाण्डे*

A. KUMAR WISHES YOU A HAPPY HOLI

Join **EXPERT BANK COACHING** for BANK, RLY, SSC, AIR FORCE, NAV Y, ARMY

Join **MODERN STUDY CENTRE** for English Classes (XI, XII, Spoken & Competitive)

VENUE-KASHIPUR, SAMASTIPUR

A KUMAR CHAIRMAN CUM FACULTY : ENGLISH

एक बड़ी हक़ीक़त यह है कि गौतम बुद्ध के लगभग 1500 साल बाद तक अनगिनत बौद्ध विहारों की मौजूदगी के बावजूद हिंदुस्तान के किसी भी भाग या क्षेत्र का नाम बिहार नहीं था.

उत्सव मनाएं या शोक

अशरफ़ अस्थानवी

बिहार में हालांकि अभी जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं है. बिहार अब भी पतझड़ के दौर से गुज़र रहा है. बिहार में बहार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल को अपार जनसमर्थन प्राप्त हो और वह रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्तासीन हुआ हो तो जश्न के हज़ारों बहाने ढूंढे जा सकते हैं. नीतीश सरकार को इसी तरह का एक बहाना हाथ लग गया है. इस शताब्दी वर्ष को बिहार उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. बिहार उत्सव का धमाल यानी जश्ने-बिहार 22 मार्च से शुरू हो गया और पूरे साल भर तक चलता रहेगा. इस जश्न के समापन के अवसर पर अगले वर्ष 18 और 19 फ़रवरी को बिहारियों की दो दिवसीय कांफ्रेंस होगी, जिसमें देश तथा विदेश से बड़ी संख्या में बिहार मूल के प्रतिनिधि भाग लेंगे.

शताब्दी समारोह में यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि बिहार का इतिहास केवल एक सौ वर्ष में सीमित है. बिहार का इतिहास सदियों पुराना है. हालांकि, बिहार का नामकरण कब तथा कैसे हुआ, इस बारे में तस्वीर अभी पूरी तरह साफ़ नहीं है. वैसे बिहार के नामकरण के संबंध में पूरे विश्वास से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. चौदहवीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई किताब तबक़ात-ए-नासरी में पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किसी भू-भाग के नाम के रूप में किया गया है. समझा जाता है कि उस समय के फ़ारसी कवियों ने किसी विशेष भू-भाग के बेमिसाल वातावरण और लगभग हर मौसम में वहां पाई जाने वाली बहार के आनंद के मद्देनज़र इस जगह को बहार का नाम दिया है और बाद में बहुत अधिक प्रयोग से शब्द बहार का रूप बदल कर बिहार हो गया है. मगर इस राय में अधिक दम नहीं है. इसके मुक़ाबले यह विश्वास अधिक सटीक लगता है कि भारत वर्ष में बौद्ध धर्म के विकास के क्रम में भिक्षुओं द्वारा जगह-जगह विहार स्थापित किए जाने लगे थे. विहारों की स्थापना तथा उनके नामों के अधिक प्रचलन का प्रभाव विशेष भू-भाग पर पड़ा होगा. इसी कारण क्षेत्र विशेष का नाम बिहारों वाला क्षेत्र पड़ गया होगा और फिर वही क्षेत्र कालांतर में बिहार नाम से मशहूर होकर आज आज़ाद भारत का राज्य बिहार बन गया है. हालांकि यह भी एक बड़ी हक़ीक़त है कि गौतम बुद्ध के लगभग 1500 साल बाद तक अनगिनत बौद्ध विहारों की मौजूदगी के बावजूद हिंदुस्तान के किसी भी भाग या क्षेत्र का नाम बिहार नहीं था. जिस समय बिहार समेत पूरे देश में अंग्रज़ों को भगाने और आज़ादी हासिल करने के लिए संघर्ष चल रहा था उन्हीं दिनों देश के इस हिस्सों में जिसे आज हम बिहार कहते हैं, बिहार को बंगाल से अलग करने का समानांतर आंदोलन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा और डॉ. सैयद महमूद जैसे युवाओं के नेतृत्व में चल रहा था और इसी आंदोलन के नतीजे के रूप में 22 मार्च, 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ और फिर 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ.

बंगाल से अलग हुए बिहार तथा बिहार से किनारा हो चुके उड़ीसा के बाद भी राज्य अपार खनिज और प्राकृतिक संपदा से मालामाल था. बिहार की इस संपदा पर सब की गिद्ध दृष्टि लगी थी. मगर इसके विकास पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया. 21वीं सदी की शुरुआत में इस राज्य को एक बार फिर राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा. आदिवासियों के विकास के नाम पर एक नया राज्य झारखंड वजूद में आया. झारखंड बनने के बाद राजनीतज्ञों ने किस तरह लूटपाट मचाई यह सर्वविदित है. उस समय जिस राजनीतिक दल का केंद्र पर क़ब्ज़ा था, उसी ने अपने तुच्छ उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि तैयार की थी और राज्य के नागरिकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि राज्य के बंटने से बिहार को कोई नुक़सान नहीं होने दिया जाएगा. झारखंड बन गया, ख़ूब अबीर गुलाल उड़ाए गए. भाजपा के बाबू लाल मरांडी मुख्यमंत्री बन गए. भाजपा के क़द्दावर लोगों के साथ-साथ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जश्न मनाने में लगे थे. मगर आज वही बिहार पैकेज के लिए राजनीतिक पैंतराबाज़ी करने में लगे हैं. मगर आज वह क्यों इस मुग़ालते में हैं कि बिहार की जनता की याद्दाश्त बिल्कुल कमज़ोर है. जिस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उस राज्य की जनता को यह अच्छी तरह याद है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार को बांट दिया और जब बिहार को विशेष पैकेज का वादा पूरा करने का समय आया तो सबने अंगूठा दिखा दिया. आज बिहार को विशेष पैकेज के नाम पर राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश करने वाले नीतीश कुमार को पहले यह बताना होगा कि केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में विशेष पैकेज के मामले में स्वयं उनकी क्या भूमिका थी.

आज राज्य की एनडीए सरकार ख़ूब धूमधाम से जश्ने-बिहार के आयोजन की तैयारी में जुटी है. कहा जाता कि इससे बिहारियत का एहसास जागेगा, लेकिन जश्ने-बिहार के आयोजन का चाहे जो भी उद्देश्य हो, यह तभी समस्त बिहारवासियों के लिए जश्न साबित हो सकेगा जब इंसाफ़ का नारा साकार हो सकेगा. अभी तो आम लोगों के साथ न तो न्याय हो रहा है और न ही ईमानदारी से विकास. राज्य के विकास के लिए विशेष पैकेज ज़रूरी है. दलीय राजनीति से उठकर सब लोगों को इसके लिए कोशिश करनी होगी और जब तक यह कोशिश कामयाब नहीं होती है तब तक जश्ने-बिहार का आयोजन करके पतझड़ के प्रकोप से राज्य की आम जनता को उबार पाना नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार का इतिहास सदियों पुराना है. हालांकि बिहार का नामकरण कब और कैसे हुआ, इस बारे में तस्वीर अभी पूरी तरह साफ़ नहीं है. वैसे बिहार के नामकरण के आधार के संबंध में पूरे विश्वास से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. चौदहवीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई किताब तबक़ात-ए-नासरी में पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किसी भू-भाग के नाम के रूप में किया गया है.

अनुभव और उत्साह की जंग

मुन्नी देवी | प्रोमिला सिंह | सलामत अंसारी | राम प्रसाद | सुनील रंजक | पप्पू पटेल

सबसे अहम सवाल तो उन पूर्व पार्षदों को लेकर उठ रहा है, जो पिछले चुनाव में कम मतों के अंतर से हारे थे और इस बार बड़ी तैयारी के साथ खम ठोकने को खड़े हैं.

सासाराम

कहावत है कि जंग में जब जोड़ को जोड़ न मिले तो जंग बेमज़ा हो जाती है. शायद इसी कहावत के मद्देनज़र इस बार रोहतास ज़िले के पंचायती राज में मंझे हुए कुछ पुराने खिलाड़ी और कुछ नए योद्धा अलग-अलग क्षेत्रों में ताल ठोक कर लड़ाई को रोचक बनाने में जुटे हुए हैं. ज़िला परिषद् के चुनाव में उतरने वाले योद्धाओं की फ़ेहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिसे देखकर यह कहना ग़लत नहीं होगा कि जंग कांटे की होगी. एक तरफ़ रोहतास ज़िला परिषद् की पूर्व सदस्य सह ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष प्रोमिला सिंह मैदान में हैं तो दूसरी तरफ़ सासाराम दक्षिणी से ज़िला परिषद के पूर्व अध्यक्ष चंद्र देव बिंद एवं ज़िला परिषद् के उपाध्यक्ष सलामत अंसारी आमने-सामने हैं. इसी क्षेत्र से वर्तमान सदस्य पारस गुप्ता की लड़ाई इन दोनों दिग्गजों के बीच त्रिकोण में जा फंसी हैं. ज़िला परिषद् अध्यक्ष महारानी सुनीता गंधा, पूर्व उपाध्यक्ष पूनम देवी, बिक्रमगंज की जुझारू सदस्य अरुणा देवी, करगहर पश्चिमी की पार्षद इंदु देवी, सासाराम उत्तरी की पार्षद शांति देवी, करगहर पूर्वी के पार्षद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पटेल के अलावा चेनारी से मंजू देवी, कांग्रेस नेत्री मीरा देवी, चेनरी उत्तरी के पार्षद सुनील रंजक एवं इनके निकटतम विरोधी प्रभात रंजक सहित कई दिग्गज मैदान में हैं. सबसे अहम सवाल तो इन पूर्व पार्षदों को लेकर उठ रहा है, जो पिछले चुनाव में कम मतों के अंतर से हारे थे और इस बार बड़ी तैयारी के साथ ख़म ठोकने को खड़े हैं. इनमें बिक्रमगंज दक्षिणी के अशोक सिंह उर्फ़ लाले सिंह, बिक्रमगंज उत्तरी के गुप्तेश्वर मिश्रा, शिवसागर दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे संजय गुप्ता, काराकाट से चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी में बैठे ज़िला परिषद् के पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र सिंह आदि शामिल हैं. वैसे कुछ पार्षद चुनाव न लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि इनमें से कुछ गत विधानसभा चुनाव लड़ चुके और कुछ अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र ऐसा मन बनाए हुए हैं. ज़िला परिषद् के उपाध्यक्ष सलामत अंसारी स्वयं सासाराम दक्षिणी एवं उनकी पत्नी सासाराम उत्तरी से चुनावी मैदान में हैं, जबकि नौहट्टा, रोहतास एवं तिलौथू से क्रमश आरुणी गुप्ता, रंग लाल डोम एवं मीरा भारती भी चुनावी मैदान में उतरने को कमर कसे हैं.

करगहर दक्षिणी की पूर्व ज़िला पार्षद सह कांग्रेस अध्यक्ष प्रोमिला सिंह नामांकन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहती हैं कि क्षेत्र का विकास केवल बातों से नहीं होता. इसके लिए हर घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेना ज़रूरी होता है. इसीलिए वह पिछले पांच वर्षों तक चुनाव हारने के बाद भी लगातार मतदाताओं के संपर्क में रहीं. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में चेहरे नहीं, बल्कि प्रत्याशियों के विचार एवं विकास मुद्दा बनेगा. वहीं ज़िला परिषद् के उपाध्यक्ष सलामत अंसारी की मानें तो विकास कार्यों के कारण ही वह लगातार दो बार ज़िला परिषद् के सदस्य रहे और इस बार भी अपनी जीत तय मानते हैं. यह अलग बात है कि पहली बार वह चेनारी उत्तरी से चुने गए थे. दूसरी बार शिवसागर दक्षिणी से लड़ने के बाद हार गए, लेकिन तत्कालीन ज़िला पार्षद बेबी कुमारी की आग में झुलसने से मौत के बाद कराए गए उपचुनाव में विजयी रहे. बिक्रमगंज दक्षिणी से चुनाव लड़ने जा रहे अशोक सिंह उर्फ़ लाले सिंह कहते हैं कि इस बार वह जनता की मांग पर चुनाव मैदान में हैं. करगहर पश्चिमी से चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी की मानें तो क्षेत्र का रुका हुआ विकास उनसे देखा नहीं गया तो वह भी चुनाव मैदान में कूद पड़ीं. मुन्नी देवी कहती हैं कि चुनाव जीतने के बाद हर ग़रीब के घर में रोशनी पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है. पूर्व पार्षद सह शिवसागर दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे भाजपा के ज़िला अध्यक्ष संजय गुप्ता कहते हैं कि उनको क्षेत्र की जनता ने यहां सेवा का मौक़ा दिया तो आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र रोहतास ज़िले में मिसाल बनेगा. इन दिग्गजों के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घमासान रोचक होने वाला है. देखना यह है कि मतदाताओं की चुप्पी क्या गुल खिलाती है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

हम निम्नलिखित में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी
मास्टर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक*
मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी*
एम. एड. (स्पेशल एजुकेशन)*

स्नातक स्तरीय पाठ्क्रम
बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी
बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी
बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन)
बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ रेडियोइमेजिंग टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी

डिप्लोमा पाठ्यक्रम
डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी
डिपलोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी
डिप्लोमा इन प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक
डिप्लोमा इन हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट
डिप्लोमा इन ओ.टी.असिस्टेन्ट
डिप्लोमा इन इ. सी. जी.
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसींग
डी.पी.टी./डी.ओ.टी. के लिये १ वर्षीय अव्रीज्ड डिग्री इन
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290, www.iiher.ac.in

Anil Sulabh
Director-in-Chief

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 04 अप्रैल-10 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

सांसद निधि से भ्रष्टाचार बढ़ा

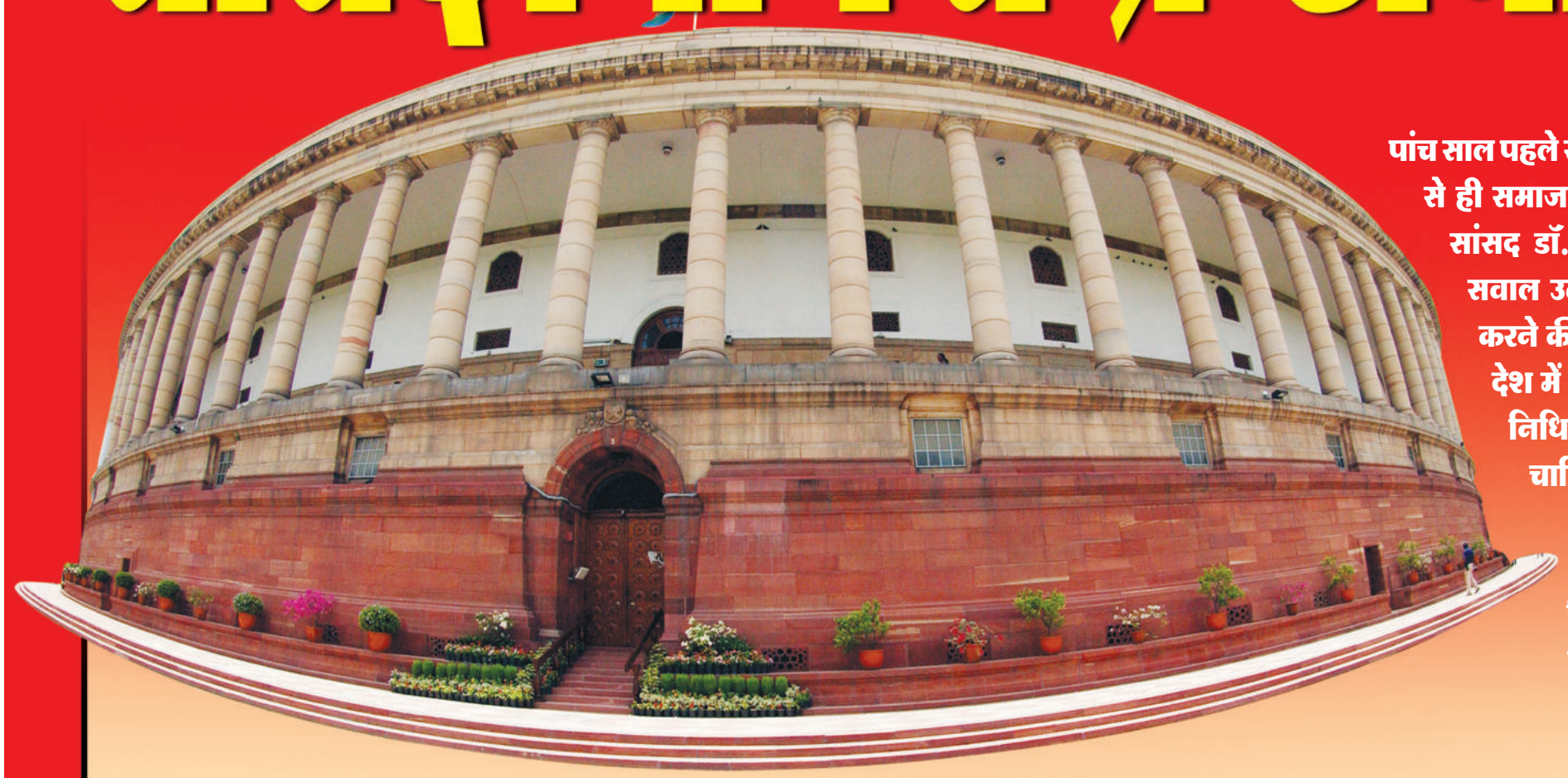

पांच साल पहले सामने आए सांसद निधि घोटाले के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद डॉ. रामगोपाल यादव इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं. वह सांसद निधि को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि देश में फैले भ्रष्टाचार को रोकना है तो सांसद निधि को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए. किसी व्यक्ति को सौ साल तक भी सांसद बने रहने दिया जाए तब भी वह इस भ्रष्ट व्यवस्था के तहत सांसद निधि से अपने इलाक़े का समुचित विकास नहीं करा सकता.

दिनेश शाक्य

सभी सियासी दलों के सांसद जहां सांसद निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिए जाने से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद डॉ. रामगोपाल यादव इसे ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. पांच साल पहले सामने आए सांसद निधि घोटाले के बाद से ही वह इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं. उनकी मांग ने एक नई बहस को शुरू कर दिया है. डॉ. यादव काफ़ी समय से सांसद निधि योजना को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर सांसदों को एकमत करने में तो वह कामयाब नहीं हो पाए, पर इतना ज़रूर है कि तमाम दलों के कुछ सांसद उनके साथ खड़े हो गए हैं. हालांकि यह संख्या उतनी नहीं है जितनी सांसद निधि का समर्थन करने वालों की है. सांसद निधि में बढ़ोतरी करने को सपा सांसद ने यूपीए सरकार की रणनीतिक चाल बताते हुए इसे समूल ख़त्म करने की मांग करके जहां ख़ुद को सुर्खियों में ला दिया है, वहीं इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है. सपा सांसद ने सरकारी राशि को सही ढंग से इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया है. देखा जाए तो डॉ. रामगोपाल यादव ने बात मुद्दे की उठाई है. उनकी मानें तो सांसद निधि को बढ़ाए जाने से आने वाले दिनों में सांसदों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी. उन्होंने शंका व्यक्त की है कि जब सांसद अपने इलाक़े के दौरे पर जाएंगे तो निश्चित रूप से इलाक़े के लोग उनके घेराव को तैयार हो जाएंगे. सपा सांसद का मानना है कि पहले ही सभी दलों के सासंदों पर बेईमानी के आरोप लगते रहे हैं. जब सासंद निधि दो करोड़ थी, तब ही सांसदों को बेईमान कहकर पुकारा जाता रहा है, अब तो यह राशि पांच करोड़ रुपये की रक़म सांसदों के ऊपर और भी गंभीर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त समझी जा सकती है. उनका कहना है कि अगर देश में फैले भ्रष्टाचार को रोकना है तो सांसद निधि को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए. किसी भी व्यक्ति को अगर सौ साल तक भी सांसद बने रहने दिया जाए तब भी वह इस भ्रष्ट व्यवस्था के अंतर्गत सांसद निधि से अपने इलाक़े का समुचित विकास नहीं करा सकता. डॉ. रामगोपाल यादव पहले भी तीन बार लोकसभा अध्यक्ष से लेकर वित्तमंत्री तक को सांसद निधि ख़त्म करने के लिए पत्र लिख चुके हैं. अब जबकि निधि को और बढ़ा दिया गया है तो उन्होंने रोष प्रकट करते हुए सांसद निधि को ख़त्म करने की मांग को लेकर चौथी बार पत्र लिखने की बात कही है. सपा नेता का कहना है कि देशभर में सांसद निधि के दुरुपयोग के कारण जनता सांसदों को बेईमान समझती है. इतना ही नहीं कई जगहों से तो इस तरह की शिकायतें भी सामने आती रही हैं कि सांसदों ने अपने इलाक़े में कामकाज के बदले में 40 फ़ीसदी तक कमीशन लेकर सांसद निधि के धन का वितरण करने की सिफ़ारिश की है. इसके सबूत भी हैं, लेकिन मजाल है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जब से 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया है तब से केंद्र की यूपीए सरकार की किरकिरी हो रही थी. ऐसे में यूपीए सरकार के सामने सभी दलों के सांसदों को अपने साथ मिलाकर रखना किसी चुनौती से कम नहीं था. इससे निपटने के लिए यूपीए सरकार ने सांसदों को पांच करोड़ का सांसद निधि पैकेज देकर एक तीर से कई शिकार कर डाले. एक तो यूपीए के रणनीतिकारों का यह मानना सही हो सकता है कि हर सांसद को पांच करोड़ रुपये निधि के तौर पर ख़र्च करने के लिए देकर उनका मुंह बंद करने का इससे बेहतर मौक़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा जब कोई बड़ा लालच सांसदों को मिल जाएगा तो वे सरकार का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे. यह क़दम सरकार ने बड़े घोटालों से ध्यान हटाने के लिए ही उठाया है.

सांसद निधि की असल हक़ीक़त यह समझी जाती है कि अधिकतर सांसद अपने क़रीबी ठेकेदारों को काम दिलवाकर उनसे कमीशन के तौर पर रक़म हासिल करते हैं. ऐसी शिकायतें अमूमन आती रहती हैं. इतना ही नहीं कई सांसदों ने निधि का इस्तेमाल अपने स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण के लिए भी कर लिया. ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों का हाल ख़ुद-ब-ख़ुद समझा जा सकता है कि एक सांसद का समय पूरा होते ही सड़क का काम भी समाप्त हो जाता है. इससे इस बात को बख़ूबी समझी जा सकती है कि सांसद निधि से निर्माण किस तरह का होता है. सपा नेता का मानना है कि अगर सांसद, निधि का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उनका अगले चुनाव का रास्ता आसानी से तय हो सकता है, लेकिन कुछ तो सांसद ही सासंद निधि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते और कुछ परिस्थितियां नहीं करने देतीं. अत: जैसा निर्माण सांसद करवाते हैं वैसी ही उनकी चुनाव में हालत हो जाती है. डॉ. रामगोपाल यादव यह कहने से नहीं चूकते कि उनकी सांसद निधि ख़त्म करने की मांग के कारण कई सासंद उनसे ख़फ़ा हैं और उनका बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं. क़रीब पांच साल पहले सामने आए सांसद निधि घोटाले के बाद से ही इस योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं. डॉ. रामगोपाल यादव ने भी इस संबंध में वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी को भी पत्र लिखा था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि सांसद निधि को ख़त्म करो, क्योंकि सांसद निधि के चलते 50 फ़ीसदी सांसदों ने अपनी सीट गंवाई है. सांसद निधि के कारण सांसदों की बहुत बदनामी हुई, लेकिन तब उनकी मांग नक्कारख़ाने में तूती ही साबित हुई. डॉ. रामगोपाल यादव ने इस बार सांसद निधि बढ़ाए जाने का विरोध करने के साथ-साथ इसके समूल ख़ात्मे की मांग को दोहराकर जो एक नई बहस शुरू की है, इस पर सांसद एकमत भले ही न हों लेकिन इस मांग पर यदि अमल होता है तो कहीं न कहीं सांसदों का दामन साफ़ रहने की उम्मीद ज़रूर बलवती होगी. वास्तव में देखा जाए तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण सांसद ही हैं. जनता अच्छे से जानती है कि उनको अपने कार्य के लिए कितना वेतन और भत्ता मिलता है? लेकिन देखते ही देखते इनके महल खड़े हो जाते हैं. जनता के पैसे से ये करोड़ों की अचल संपत्ति बना लेते हैं अच्छा ख़ासा बैंक बैलेंस तैयार कर लेते हैं. ये पैसे आम जनता से कर के रूप में वसूला जाता है, देश के विकास के लिए, लेकिन देश का विकास ये कितना करते हैं पता नहीं पर इनका विकास ज़रूर हो जाता है. भ्रष्टाचार में डूबे सांसदों की मांग वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने मानकर देश की जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. सांसद निधि की इस बढ़ोतरी से प्रतिवर्ष दो हज़ार तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ ख़जाने पर पड़ेगा. सभी जानते हैं कि विकास के लिए आ रहे इस पैसे का बंदरबांट हो जाता है.

इस निधि की बढ़ोतरी से वास्तव में कमीशनख़ोरी को ही अधिक बढ़ावा मिलेगा. सांसद निधि बढ़ाए जाने के निर्णय से पहले क्या सरकार ने यह जांच कराई कि वास्तव में सांसद अपने विवेकाधीन कोष का लाभ ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं? क्या किसी सरकारी एजेंसी से जांच करवाई गई है कि सांसद निधि की बहुत सारी राशि ऐसी संस्थाओं को रेवड़ी की तरह बांट दी जाती हैं जिनसे व्यक्ति का निजी हित सधता है? चाहे वह वोटों के रूप में हो या कमीशनख़ोरी के रूप में. कमीशनख़ोरी के कई मामले ऐसे आ चुके हैं. अगस्त 2010 में सांसदों का वेतन 16 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया गया. सासंदों के प्रतिमास मिलने वाले कार्यालय ख़र्च की सीमा 20 हज़ार से 40 हज़ार रुपये तथा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वाहन ख़रीदने के लिए सांसदों को मिलने वाले ब्याज़मुक्त क़र्ज़ की सीमा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई तथा वाहनों का रोड माइलेज रेट 13 रुपये प्रति किलामीटर से 16 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया. फ़ायदा सांसदों की पत्नियां को भी मिलेगा. अब वो चाहे जितनी बार फर्स्ट क्लास या एक्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र कर सकेंगी. पेंशन लाभ भी 8 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया.

feedback@chauthiduniya.com

डॉ. रामगोपाल यादव

सांसद के वेतन-भत्ते

मूल वेतन	50 हज़ार रुपये
दैनिक भत्ता	02 हज़ार रुपये
दफ्तर ख़र्च	40 हज़ार रुपये
चुनाव क्षेत्र भत्ता	40 हज़ार रुपये

सांसद निधि की असल हक़ीक़त यह समझी जाती है कि अधिकतर सांसद अपने क़रीबी ठेकेदारों को काम दिलवाकर उनसे कमीशन के तौर पर रक़म हासिल करते हैं. ऐसी शिकायतें अमूमन आती रहती हैं. इतना ही नहीं, कई सांसदों ने निधि का इस्तेमाल अपने स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण के लिए भी कर लिया. ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों का हाल ख़ुद-ब-ख़ुद समझा जा सकता है .

प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के माध्यम से होता है स्थानांतरण के कारण की व्याख्या का काम उनका है, पर ऐसा किया नहीं जाता.

मायावती के तिलक, तराजू और तलवार...जैसे तीखे नारे बसपा के बैनरों पर लिखे और सभाओं में गूंजते सुनाई पड़ते थे. तीखी आलोचना के कारण ही वह पिछड़े वर्ग में लोकप्रिय हो गई थीं.

बसपा में सोशल इंजीनियरिंग नाकाम

राजेंद्र सारथी

मायावती आजकल दलितों और ब्राह्मणों को लेकर पसोपेश की स्थिति में हैं. वह विचलित हैं कि ब्राह्मण समाज बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस से जुड़ने जा रहा है. सच्चाई भी यही है कि ब्राह्मणों का बसपा से मोहभंग हो गया है, यही नहीं अब दलित भी बसपा से मुंह मोड़ रहे हैं. इसकी वजह बसपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच बढ़ती तनाव है. हालत यह है विधायक अपनी जाति के कार्यकर्ताओं का काम करने में ही रुचि दिखा रहा है, बाक़ी कार्यकर्ताओं के साथ टरकाऊ रवैया अपना रहे हैं. मायावती ने अपनी पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग का फ़ार्मूला लागू करके वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी. इससे पहले मायावती सिर्फ़ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की नेता थीं और अगड़ी जाति के लोगों और पार्टियों को वह मनुवादी कहती थीं. उनके तिलक, तराज़ू और तलवार...जैसे तीखे नारे बसपा के बैनरों पर लिखे और सभाओं में गूंजते सुनाई पड़ते थे. अपनी तीखी आलोचना के कारण ही वह अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग में बेहद लोकप्रिय हो गई थीं. वर्ष 1995, 1997 और 2002 में भाजपा और सपा के साथ चुनाव के बाद के गठबंधन में उन्हें मुख्यमंत्री बनने के तीन बार अवसर मिले. मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती को महसूस हुआ कि जब तक सर्वसमाज के लोगों की भागीदारी उनकी पार्टी में नहीं होगी, तब तक उन्हें अकेले दम पर सरकार बनाने वाला पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता. एक सत्य यह भी था कि सत्ता में बैठे अधिकारीगण भी सर्वजातियों से थे, इसलिए उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन में अगड़ी जाति के कई अधिकारी बाधक बन जाते थे. इस पर मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फ़ार्मूला लागू किया और अगड़ी जाति के लोगों को पार्टी में प्रवेश के साथ महत्व देना भी शुरू किया. इस फ़ार्मूले को लागू करने में उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक फेरबदल करके पार्टी का विस्तार किया और पार्टी का चेहरा ऐसा बनाया कि सबको दिखाई दे कि बहुजन समाज पार्टी में सही मायने में सर्वसमाज प्रतिष्ठापित है. बसपा सुप्रीमो ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के फ़ार्मूले के तहत पार्टी में मुसलमानों को भी तरजीह देने की कोशिश की. 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 20 ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाया गया था. 14 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए थे. प्रदेश की 80 में से 17 सीटें संवैधानिक व्यवस्था के तहत पहले से ही अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित थीं. बसपा ने छह महिलाओं को भी लोकसभा चुनाव में उतारा था. सभी राजनीतिक दलों ने सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए अपनी पार्टी के दरवाज़े खोल रखे थे. हालांकि कांग्रेस को ब्राह्मण समाज, वाल्मीकि समाज, आंशिक रूप से मुस्लिम और क्षत्रिय-राजपूत समाज की पार्टी माना जाता रहा है. इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज, कट्टर हिंदूवादी मानसिकता वाले समाज, आदिवासी समाज, कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशी चिंतन वाली समतावादी पार्टी, बसपा को अनुसूचित वर्ग की पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल को जाट समाज की पार्टी, समाजवादी पार्टी को यादव समाज की पार्टी माना जाता है. राजनीतिक दृष्टि से मायावती की यह एक सार्थक पहल थी. इसका पूरे प्रदेश में सर्वत्र स्वागत हुआ और 2007 के चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसने बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत दे दिया था. बहुजन समाज पार्टी में लागू हुए सोशल इंजीनियरिंग के फ़ार्मूले का नुक़सान कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा. भारी संख्या में ब्राह्मण, मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोग जो कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, टूटकर बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे. वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी का ऊपरी ढांचा जो भी हो आंतरिक रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का ही दख़ल सर्वाधिक दिखाई देता है. इसे लेकर पिछड़े, दलित एवं अपसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ताओं में काफ़ी समय से असंतोष फैला हुआ था. उन्होंने कई बार अपनी यह पीड़ा ऊपर पार्टी सुप्रीमो तक पहुंचाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. अब उत्तर प्रदेश का लक्ष्य भेदने के लिए 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया. 2012 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राहुल गांधी कई बार उत्तर प्रदेश में दौरे कर चुके हैं और इन दौरों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति दलित और पिछड़े वर्ग को आकर्षित कर गई है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.पी.एल. पुनिया ने उत्तर प्रदेश में किए जा रहे सम्मेलनों का असर भी दिखाई दे रहा है. उधर, प्रदेश के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार हाल ही में कांग्रेस के साथ फिर से खड़े हो गए हैं. इटावा, एटा, मैनपुरी, फतेहपुर और कानपुर देहात ब्राह्मणों की पट्टी के रूप में जाना जाता है. कांग्रेस अब कन्नौज को केंद्र में रखकर ब्राह्मणों को नए सिरे से जोड़ने की मुहिम में जुटने जा रही है. सतीश मिश्र की भी अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है. कुछ समय पहले मायावती ने दलितों को संदेश देने के लिए सतीश मिश्र को हाशिये पर भेज दिया था. कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग में जुटे अमरेश मिश्र का कहना है कि आज़ादी से काफ़ी पहले से प्रदेश के ढाई सौ से अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और किन्हीं कारणों से उन्होंने पार्टी से मुंह मोड़ लिया था अब फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, यह पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है. बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल में यही ब्राह्मण बिरादरी कांग्रेस की रीढ़ रही है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नज़र आ रहे हैं. विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो उस समय ही पता चलेगा. बहरहाल अन्य दल भी सोशल इंजीनियरिंग के फ़ार्मूले पर काम करने में जुटे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी ठेकों पर ज़हरीली शराब!

महेंद्र अवधेश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में कांठ कस्बे के नज़दीक स्थित महमूदपुर फ़ौ गांव में ज़हरीली शराब से हुई दो युवकों की मौत ने एक बार फिर शासन-प्रशासन के उन सारे दावों की पोल खोल दी है कि वह ज़हरीली शराब बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त है. ऐन होली के दिन यानी 19 मार्च की सुबह महमूदपुर फ़ौ गांव में उस समय मातम में डूब गया, जब लोगों को यह पता चला कि ज़हरीली शराब पीने से गांव के चेतराम सिंह के पुत्र 32 वर्षीय चंद्र किरन और गुलज़ार के पुत्र मलखान की मौत हो गई. यह मिस इंडिया मार्का शराब सरकारी ठेके से ख़रीदी गई बताई जाती है और बोतल निर्माता इस पर यूवायो केमिकल्स लिमिटेड अलीगढ़ दर्ज है. शराब पीते ही दोनों युवकों की आंखों में अंधेरा छाने लगा, जानकारी मिलने पर घरवाले जब उन्हें निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए तो वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. चंद्र किरन और मलखान के परिवारों की माली हालत काफ़ी ख़राब बताई जाती है और ये मज़दूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं. मालूम हो कि सूबे में ज़हरीली शराब बनाने-बेचने का धंधा काफ़ी समय से खुलेआम चल रहा है. होली, दीवाली और नए साल के मौक़े पर शराब के नाम पर ज़हर बेचने वाले सौदागर लगभग हर बार कई निर्दोष लोगों की मौत की वजह बनते हैं. जब कोई घटना प्रकाश में आती है तो शासन-प्रशासन सक्रिय हो जाता है और कुछ दिनों तक कार्रवाई का ढोल पीटने के बाद ख़ामोशी की चादर ओढ़ लेता है. महमूद माफ़ी गांव में इन दो दलित युवकों की मौत के बाद जब जनता सड़क पर उतर आई तो मौक़े की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने संबंधित सरकारी शराब के ठेके के दो सेल्समैनों को हिरासत में ले लिया. आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त छापे में पाया गया कि जो शराब बेची जा रही थी, उस पर बैच नंबर तक अंकित नहीं था और ठेके में स्टाक भी रिकार्ड से ज़्यादा था.

मुरादाबाद के एसपी देहात डॉ. अरविंद ने ख़बर पाते ही मौक़े का मुआयना किया और उन्होंने अन्य स्थानों पर भी छापेमारी के निर्देश दिए. ज़िलाधिकारी राजशेखर के अनुसार, ठेके से शराब के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं. उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासन न सिर्फ़ सख़्त कार्रवाई करेगा, बल्कि पूरे जनपद में अवैध रूप से शराब बेचने-बनाने वालों के ख़िलाफ़ सघन अभियान भी चलाया जाएगा. क्षेत्रीय विधायक हाजी रिज़वान अहमद ख़ां और उप ज़िलाधिकारी डी के चौधरी ने भी महमूदपुर का दौरा कर प्रभावित परिवारों को यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया.

सवाल तो यह है कि सरकारी शराब ठेके पर ज़हरीली शराब आई कैसे? क्या सरकारी ठेकेदार ज़हरीली शराब भी बनाते हैं या ज़हरीली शराब बनाने वालों से उनके संबंध हैं? अक्सर त्योहारों के मौक़े पर ऐसे हादसे पेश आते हैं, यह जानकारी होने के बावजूद ज़िला प्रशासन ने होली से पूर्व सरकारी ठेकों में मौजूद शराब से संबंधित रिकार्ड, मात्रा और बैच नंबर आदि की जांच करने की ज़हमत क्यों नहीं उठाई? अवैध शराब भट्ठियां किसके इशारे पर चल रही हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? बीते वर्ष दीवाली के मौक़े पर भी मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के ताजपुर मिलक गांव में दो लोग ज़हरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठे थे. इससे पूर्व फ़रवरी 2010 में गढ़मुक्तेश्वर के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्लौर में ज़हरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी. आंकड़े बताते हैं कि बीते एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में ज़हरीली शराब पीने से लगभग तीन सौ से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

हालांकि शासन सिर्फ़ 58 लोगों के मरने की ही पुष्टि करता है. प्रतापगढ़ में 3, भदोही में 8, इलाहाबाद में 13, बुलंदशहर में 19 और मिर्ज़ापुर में 23 लोग ज़हरीली शराब के शिकार हो चुके हैं और लगभग एक सैकड़ा लोगों की आंख की रोशनी चली गई. राज्य के आबकारी महकमे ने इन मामलों को लेकर न सिर्फ़ अपने आठ अफ़सरों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही की, बल्कि इलाहाबाद के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर छत्तीसगढ़ निर्मित और मध्य प्रदेश से तस्करी करके लाई गई शराब भी बरामद की. विभाग ने अपनी नई आबकारी नीति को लेकर शासन के समक्ष कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिनके तहत कहा गया है कि ज़हरीली शराब के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वालों को उम्रक़ैद और दस लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा हो, और 21 वर्ष से कम उम्र के शख़्स को शराब न बेची जाए.

विभाग का मानना है कि शराब माफ़िया और सिंडिकेट अधिक लाभ के लालच में छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हरियाणा से तस्करी करके लाई गई शराब अवैध रूप से बेचता है. सूत्रों का कहना है कि तस्करी की सस्ती शराब जब कम पड़ जाती है तो सिंडीकेट ज़हरीली शराब बेचने से भी परहेज़ नहीं करते. सरकारी ठेकों से बिकी शराब से हुई मौतें इसका प्रमाण हैं. राज्य सरकार ने अभी पिछले दिनों ही विधानसभा में स्वीकार किया था कि बीते एक साल में ज़हरीली शराब 87 लोगों की जान ले चुकी है. अवैध भट्ठियों पर बनने वाली कच्ची शराब का कारोबार भी त्योहारों पर बढ़कर दोगुना-तिगुना हो जाता है. इलाहाबाद, फैजाबाद, सहारनपुर, बहराइच, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और जालौन आदि जनपदों में कच्ची शराब की खपत बड़े पैमाने पर होती है. बहरहाल, शासन-प्रशासन की उदासीनता के चलते अवैध शराब बनाने-बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं, वे धड़ल्ले से ज़हरीली शराब सरकारी ठेकों के ज़रिए बेच रहे हैं और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

m_avdhesh@chauthiduniya.com

सलाख़ों के पीछे क़ैद ज़िंदगी

शिखा जौलान

जेल का जीवन आम जीवन से किस क़दर अलग होता है, ये वे लोग बेहतर जानते हैं जो मज़बूत सलाख़ों के पीछे क़ैद होकर अपना जीवन बिता रहे हैं या फिर बिता चुके हैं. जेलों में ख़ूंखार अपराधियों के साथ-साथ अनेक सामान्य सज़ायाफ्ता तथा विचाराधीन क़ैदी मौजूद हैं, जिनमें से कई बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं तो कई स्वयं को इन सलाख़ों के पीछे ही सुरक्षित मानते हैं. फ़र्ज़ी मुक़दमों के तहत जेल की सलाख़ों के पीछे पहुंचे विचाराधीन क़ैदी बाहर आने पर जेल का जीवन नारकीय बताते हुए कहते हैं कि वहां हर मोड़ पर रुपया बोलता है. ऐसे ही सहारनपुर ज़िला जेल से कुछ लोग जो ज़मानत पर छूटे या फिर न्यायालय के ज़रिए बरी कर दिए गए, उनसे पूछताछ के दौरान जेल की जो कहानी उभरकर सामने आई, वह वास्तव में चौंकाने वाली है. जेल में बंद यदि किसी क़ैदी से मुलाक़ात करनी हो तो पहले दो रुपए की पर्ची कटती है, जिसके माध्यम से मिलने आए तीन लोग मुख्य द्वार से अंदर जा सकते हैं. पहले दो लोगों के अंदर जाने का प्रावधान था. यदि एक पर्ची पर तीन से अधिक लोग मुख्य द्वार से अंदर जाना चाहेंगे तो फिर प्रति व्यक्ति से 100 से 200 रुपए सुविधा शुल्क लिया जाएगा. वहीं स्पेशल मुलाक़ात के 500 रुपए लिए जाते हैं और यह मुलाक़ात मात्र 15 मिनट की हो पाती है. वैसे तो मुलाक़ात का समय एक घंटे का निर्धारित है, लेकिन तीन गेट पार करने में काफ़ी समय लग जाता है. मुलाक़ात के बाद जब बंदी वापस अपनी बैरक में जाएगा, तब उससे सुविधा शुल्क अलग से लिया जाता है. यह रक़म जेलर, डिप्टी जेलर, हैड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल में बंटती है. मात्र रविवार को सरकारी स्तर पर मुलाक़ात का प्रावधान है. इस दिन सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता.

ज़िला जेल में वर्तमान समय में लगभग 1200 क़ैदी मौजूद हैं, जिसमें से लगभग डेढ़ सौ सज़ायाफ्ता हैं. 50 क़ैदी उम्रक़ैद काट रहे हैं, जबकि अन्य विचाराधीन हैं. यहां कुल आठ बैरक हैं जिसमें से एक बैरक की क्षमता 60 से 70 क़ैदियों को रखने की है, जबकि एक बैरक में 100 से 150 के बीच क़ैदियों को रखा गया है. मच्छर यहां बहुतायत में हैं जिससे अक्सर यहां के क़ैदी मलेरिया के शिकार हो जाते हैं. सज़ायाफ्ता तथा विचाराधीन महिला क़ैदियों के बैरक अलग हैं जिनके ऊपर शमा

नामक रायटर की तैनाती है जो अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के तहत उम्रक़ैद काट रही है. रायटर यानी बंदी रक्षक चाहे वे पुरुष हों अथवा महिला, उन्हें कई काम सौंपे गए हैं, जैसे सुबह 5 बजे बैरक से क़ैदियों को निकालकर उनकी गिनती करवाना, रिश्तेदारों तथा परिचितों से क़ैदियों की मुलाक़ात कराना, कौन से क़ैदी की न्यायालय में कब तारीख़ है या कौन-सा क़ैदी कब छूट रहा है, इसका लेखा-जोखा तथा संपूर्ण ज़िम्मेदारी रायटर की है. रायटर भी उसे ही नियुक्त किया जाता है जो थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा हो और नाम, पते, साफ़-सुथरे ढंग से लिख सके. आठों बैरकों में आठ रायटर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें चंद्रकांता तथा विजयकांत नामक दो भाई भी हैं जो यहां आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र बैरक आठ में शातिर हिंदू अपराधियों को तथा बैरक नंबर एक में शातिर मुस्लिम अपराधियों को रखा जाता है. बैरक नंबर 5 और 7 में इन क़ैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है जो शरीर से और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं. धन की कमी के कारण उनकी बाहरी लोगों से मुलाक़ात भी नहीं कराई जाती. यदि क़ैदियों को मिलने वाले भोजन की बात करें तो यहां क़ैदियों को सुबह मात्र एक कप चाय दी जाती है वह भी जिसको मिली ठीक है और जो इससे वंचित रह गया, उसकी अपनी क़िस्मत है. एक दिन में दो बार भोजन देने की व्यवस्था है और वह भी दाल-रोटी. दाल में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. मंगलवार तथा रविवार को सिर्फ़ चने दिए जाते हैं. यदि स्पेशल भोजन करना हो तो प्रतिमाह 5 सौ से 7 सौ रुपए अदा करने पड़ते हैं. हैरत की बात यह भी है कि यहां आयोजित भंडारे का ठेका भी 10 से 20 हज़ार के बीच छूटता है. भंडारे के अलावा सर्किल पुताई, झाड़ू, बग़िया तथा गिरधर, बढ़ई के काम में क़ैदियों को लगाया जाता है जिसका उन्हें मेहनताना तक नहीं मिलता. यहां मौजूद कैंटीन से यदि कोई क़ैदी कुछ भी सामान मांगता है तो उससे मनमानी रक़म वसूल की जाती है, जबकि सामान लाने के रुपए अलग से वसूले जाते हैं. मशक्कत के नाम पर भी यहां गड़बड़झाला है. 13 सौ रुपए अदा करने पर मशक्कत में 10 दिनों तक कोई काम नहीं कराया जाता. यहां तक कि गिनती भी नहीं की जाती. अधीक्षक, जेलर या डिप्टी जेलर द्वारा की गई पूछताछ में कुछ क़ैदी ख़ौफ़ के कारण सच्चाई बताने से भी कतराते हैं. यह हालत तब है जब डी.एम. तथा एस.एस.पी. समय-समय पर जेल का दौरा करते हैं. ज़िला कारागार से ज़मानत पर छूटे अथवा बरी हुए क़ैदियों की मानें तो वास्तव में यहां ज़बरदस्त धांधली है जिससे सलाखों के पीछे जीवन काट रहे क़ैदी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ख़ूंखार अपराधियों का आतंक

ज़िला सहारनपुर जेल में जहां अनेक ख़ूंखार अपराधी आज भी सज़ा भुगत रहे हैं, वहीं कई अन्य विभिन्न जेलों में स्थानांतरित होकर यहां से जा चुके हैं जिनकी यहां कभी तूती बोलती थी. हत्या, अपहरण तथा रंगदारी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाला मुज़फ्फ़रनगर का नईम कुरैशी ज़िला जेल में सज़ा भुगत रहा है. कैराना का कुख्यात सालिम बाबा जिस पर एक दरोग़ा की हत्या के अलावा अनेक संगीन मुक़दमे दर्ज है, यहां से अन्य जेल में स्थानांतरित हो चुका है. सलीम काला जिसे पुलिस ने स्टेशन से गिरफ्तार किया था, वह भी किसी अन्य जेल में भेज दिया गया. कुख्यात नफ़ीस कालिया का शार्प शूटर कैलाशपुर निवासी रिहान गुलज़ार जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, हरिद्वार का देवेंद्र उर्फ़ देव, तीन बार गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध बॉबी त्यागी, नोएडा से पकड़ा गया विक्की त्यागी, हमजागढ़ गंगोह का कुख्यात माहिर, जो एक झगड़े में पहली बार जेल गया और ज़मानत पर छूटने के बाद अपराधी बन गया. गंगोह स्थित मोटर साइकिल शोरूम में गोली चलाने का भी उस पर आरोप है. नानौता का जावेद और रिहान जिन पर एक दरोग़ा की हत्या का आरोप भी लगा. रिहान साक्ष्य के आधार पर रिहा हो गया, लेकिन जावेद अब भी सलाख़ों के पीछे है. गंगोह का ब्रह्मचारी जो वर्ष 2008 में फास्ट ट्रैक कोर्ट से बरी हुआ, वहीं कुख्यात बुद्धू काला तथा इसी के गैंग का अख्लाक़ उर्फ़ भूरा पुलिस एनकाउंटर में मारे गए. उनके अलावा कई अन्य शातिर अपराधी सहारनपुर ज़िला जेल में पहुंचे, जिनमें से कई स्थानांतरित होकर यहां से जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य आज भी सलाख़ों के पीछे अपना जीवन काट रहे हैं. पुराना चिलकाना बस स्टैंड के समीप मिंटू सिद्दीक़ी की हत्या कर बेरहमी से इसके छोटे-छोटे टुकड़े करने वाले दुर्दांत अपराधी इखलाख जिसकी फांसी की सज़ा उम्रक़ैद में तब्दील हो गई थी. यह तब्दीली वर्ष 1999 में उच्च न्यायालय से हुई. सज़ा पांच लोगों को हुई थी, जिनमें तीन लोग बरी हो गए, जबकि दो अभी भी आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं जिनका मामला उच्च न्यायालय से ख़ारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इखलाख आज ज़िला जेल में स्थित कैंटीन का संचालक बना हुआ है. सभ्य समाज से अलग होकर जेल में जीवन यापन करने वाले इन अपराधियों के चेहरों पर प्रतिशोध की ज्वाला के साथ-साथ ख़ाकी को लेकर नफ़रत के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता.

फ़िरोज़ाबाद में पानी की किल्लत

फ़िरोज़ाबाद जनपद में पेयजल की भारी किल्लत है. लोग अशुद्ध एवं दुर्गंधयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं. इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. हालत यह है कि नारखी क्षेत्र के गांव खैबर में विषाक्त पानी के इस्तेमाल से गांव के अधिकांश लोग कुबड़े हो गए है. कोई भी व्यक्ति इस गांव में वैवाहिक संबंध करने के लिए नहीं जाता. इस गांव को अब गांगनी पेयजल परियोजना से जोड़ा गया है.

जनपद में भू-गर्भ जल स्तर 2.8 मीटर प्रतिवर्ष की गति से गिरता जा रहा है. फ़िलहाल ज़िले में भूगर्भ जल स्तर दो सौ फीट से दो सौ चालीस फीट नीचे है. कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों और घरों में लगे सबमर्सिबल पंपों से अंधाधुंध पानी खींचा जा रहा है. इस कारण भूगर्भ जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है. पानी की समस्या के समाधान को लेकर नगर पालिका परिषद के पास जलापूर्ति का अन्य कोई स्त्रोत न होने के कारण उसने भी स्थान-स्थान पर नलकूप लगा दिए हैं जिसके कारण भी भूगर्भ जलस्तर में भारी गिरावट आई है. नगर पालिका द्वारा लगाए गए अधिकांश नलकूप सूख चुके हैं. उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है, जो थोड़े-बहुत नलकूप पानी उगल भी रहे हैं तो उनका पानी अशुद्ध है, पीने योग्य नहीं है. अधिकांश शहरवासी दूषित पानी पीने को विवश हैं. विकास के नाम पर शहरभर में कंक्रीट के जंगल खड़े नज़र आते हैं. शहर में जितनी भी कालोनियां बनी हैं उनमें भी वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है. शहर के तालाब भी समाप्त कर दिए गए हैं. उन जगहों पर आबादी बस गई है. यहां तक कि नाले-नालियां भी पक्के हैं. बारिश का पानी ज़मीन के अंदर न जाकर नाले-नालियों के द्वारा बह जाता है. भू-जलस्तर ज़रा भी नहीं बढ़ पाता. जनपद के कुछ क्षेत्रों में खारा पानी है और जलस्तर भी 60-65 प्रतिशत घटा हुआ है. यदि आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ष 2000-01 में जलस्तर 40 फीट था यानी 2 फीट जल स्तर गिरा, वर्ष 2002-03 में जलस्तर 42.50 फीट था यानी जलस्तर ढाई फीट गिरा, वर्ष 2003-04 में जलस्तर 46 फीट हो गया यानी साढ़े तीन फीट जलस्तर गिरा. इसी प्रकार 2004-05 में जलस्तर 45 फुट था यानी जलस्तर में तीन फीट की गिरावट आई. वर्ष 2006-07 में जलस्तर 52 फीट हो गया यानी जलस्तर तीन फीट नीचे गिरा, वर्ष 2009-2010 में जलस्तर में भारी गिरावट हुई जिससे जल स्तर बहुत नीचे चला गया. इस समय फ़िरोज़ाबाद शहर में क़रीब 1400 हैंडपंप हैं, जिसमें से अधिकांश हैंडपंपों ने पानी उगलना बंद कर दिया है. कुछ हैंडपंप ऐसे है जो हिचकोलों के साथ पानी उगल रहे हैं. ऐसे हैंडपंप बंद होने की कगार पर खड़े हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानत: 24386 हैंडपंप हैं, जिनमें से क़रीब 1400 से अधिक रीबोरिंग की स्टेज पर खड़े हैं. जल निगम की 19 पेयजल परियोजनाओं में कुछ परियोजनाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं, जिनमें गांगनी, भीकनपुर, मदनपुर तथा नियामतपुर पेयजल परियोजना शामिल है. पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार कुल परियोजनाओं में 33 नलकूप अधिस्थापित हैं, जिनमें अधिकांश ख़राब हो चुके हैं. यह सभी नलकूप 15 से 20 वर्ष पुराने हैं. पूर्व में ही 76 गांवों में पेयजल योजना बनाई गई है, जिसके तहत 42 प्रोजेक्ट लगेंगे. जलस्तर के रीचार्ज के लिए सरकारी बिल्डिंग में सिस्टम लगाए गए है. भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शासन-प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उपक्रम नहीं किया गया. वर्षा का पानी सीधे ज़मीन के अंदर जाए, इसके लिए अब काम करना ज़रूरी हो गया है. यदि शीघ्र इस दिशा में कोई प्रभावी क़दम नहीं उठाया गया तो पेयजल की भारी किल्लत शहरवासियों को उठानी पड़ेगी.

शिवम तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

जनता का पैसा कहां जाता है

देवी प्रसाद गुप्त

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी देवी प्रसाद गुप्त जागृत भारत नाम के स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से जनता के पैसे का सदुपयोग कराने का बीड़ा उठाए हुए भारत के गांव-गांव और शहर-शहर में घूम कर जनता को जागरूक कर रहे हैं. वह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं. वे उक्त संगठन के माध्यम से राष्ट्रव्यापी 85 पैसा ढूंढो आंदोलन छेड़े हुए हैं. देवी प्रसाद गुप्त का कहना है कि देश के किसी भी क्षेत्र में विकास न हो पाने के अन्य कारण तलाशने से पहले हमें दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के सार्वजनिक बयानों पर ग़ौर करना चाहिए. तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1986 में स्वीकार किया था कि विकास के नाम पर जो पैसा भेजा जाता है वह गांव तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे ही रह जाता है. इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2001 में यह स्वीकारोक्ति की थी कि विकास मद में व्यय होने वाली राशि का 15 पैसे ही ज़मीन तक पहुंच पाता है.

कांग्रेस के राजकुंवर सांसद राहुल गांधी ने भी इस सत्य को 2007 में स्वीकार किया. अब सोचिए कि जब केंद्र के मुखिया ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं तो विकास न हो पाने के पीछे के अन्य कारणों को तलाशने की बजाय ज़मीन तक न पहुंच पाने वाले 85 पैसे की तलाश ही हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें क्यों नहीं जानना चाहिए कि इसे कौन हड़प रहा है. हालत यह है कि एक रुपए अर्थात् 100 पैसे में से 85 पैसे ग़ायब करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया ने आज मुद्रास्फीति को 20 प्रतिशत के ख़तरनाक आंकड़े के क़रीब पहुंचा दिया है. बढ़ती महंगाई से त्रस्त आम आदमी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है. रोज़ नए घोटाले और उनकी जांच में ख़र्च होने वाली करोड़ों रुपए की रक़म, बड़े-बड़े नामों का सामने आना और फिर इन घोटाले की फाइलों का बंद हो जाना. बयानबाज़ी पर बयानबाज़ी के बीच सबकुछ वैसा ही रहना, और फिर नए घोटाले की गूंज गूंजना. भारत के प्रत्येक नागरिक का अंशदान राजकोष में जमा होता है. एक भिखारी भी यदि माचिस ख़रीदता है तो इस माचिस की क़ीमत का कुछ अंश टैक्स के रूप में राजकोष में जाता है. वही विभिन्न वर्ग और समाज के नागरिकों से एकत्र हुआ राजस्व ही भिन्न-भिन्न मदों में सरकार द्वारा ख़र्च किया जाता है. स्विस बैंक में भारत का जमा धन 1,45,600 करोड़ डालर यानी 72 लाख करोड़ रुपए है. यह इतनी बड़ी रक़म है कि भारत का सारा विदेशी क़र्ज़ उतर जाएगा और फिर भी धन बचा रहेगा. भारत सरकार की संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष की गणना के अनुसार स्विस बैंको में जमा काला धन वहां से मंगवाकर यहां देश की जनता में बंटवा दिया जाए तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में कम से कम 50 हज़ार रुपए आएंगे. स्विस बैंक वहां जमा धनराशि पर ब्याज़ नहीं देता, बल्कि जमाकर्ता से काला धन सुरक्षित रखने के लिए सालाना फ़ीस लेता है. यह वही पैसा है जो उद्योपतियों ने टैक्स के रूप में सरकार को न देकर विदेशी बैंको में जमा करा दिया. पिछले दिनों भारत सरकार के नियोजन मंत्री नारायण स्वामी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोध कुमार सहाय, पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया को इस संबंध में मांगपत्र सौंपकर भारत सरकार से मांग की जा चुकी है कि वह श्वेतपत्र जारी कर देशवासियों को बताए कि 1 रुपए में से 85 पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? जितने ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा इस मांग को शक्ति मिलेगी.

राजेंद्र सारथी
feedback@chauthiduniya.com

प्राइमरी शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति कब बनेगी

अरविंद त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश में मायावती ने इस बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने का काम किया. पूर्व की सरकारों को इस विशेष उद्योग के कारण ख़ासी बदनामी झेलनी पड़ी. प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून के महीने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए जाने जाते रहे हैं. प्रत्येक विभाग की एक ख़ास प्रक्रिया होती है और स्थानांतरण के लिए उचित कारण बताकर प्रत्येक वर्ष लोग इधर से इधर होते हैं. इन ख़ास महीनों में सरकारी कर्मचारियों में परिवारीजननों के साथ स्वयं की बीमारियों आदि के प्रमाण-पत्रों को आवेदनपत्र के साथ सिफ़ारिशों के पत्रों की भरमार होती जाती है. इसके लिए मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, सत्ताधारी दल के संगठन के पदाधिकारियों तथा बाहुबलियों की सिफ़ारिशें होती हैं. बसपा की सरकार में इस सेवा-शुल्क और सिफ़ारिशी पत्र के बल पर सारे काम कराने की छवि को सुधारने की गरज से मायावती ने दो सत्र स्थानांतरण शून्य कर दिए थे, जिससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में ख़ासा तनाव रहा.

बेसिक शिक्षा विभाग में बीटीसी के तहत हुई भर्तियों में पूरे प्रदेश में शिक्षक-शिक्षिकाओं की तैनाती उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों की हुई है. इस सरकार के अतिरिक्त पूर्व में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की सरकारों ने भी भर्तियां की थीं. इन सरकारों ने भर्ती को प्रदेश स्तर पर करते हुए प्रदेश स्तर की मेरिट बना कर किया था. किसी विशेष जनपद में पद रिक्त न होने की दशा में मंडल के दूसरे ज़िले में तैनाती दी गई. आश्वासन दिया गया था कि पद रिक्त होने पर विभागीय कार्रवाई कर प्राथमिकता के आधार पर पहले महिलाओं और फिर अध्यापकों के स्थानांतरण गृह-जनपद में हो सकेंगे. वर्तमान सरकार ने जिलास्तरीय भर्तियां की और नव-चयनितों को दूरस्थ और एकल विद्यालय में कम से कम पांच साल की तैनाती का नियम लागू कर नियुक्ति दी. बेरोज़गारी की मार खाए महिला-पुरुषों की उच्च शिक्षित भीड़ ने पहले किसी तरह की ट्रेनिंग ली फिर तैनाती पाई, लेकिन कार्य-व्यवहार और संस्कृति में परिवर्तन के कारण ये शहरी पीढ़ी स्वयं को व्यवस्थित न कर सकी. कार्य की उपेक्षा की शिकायतें आम हैं. दूसरी तरफ़ ये सभी शिक्षा अधिकारियों को दुधारू गाय लगते हैं. अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक और शारीरिक शोषण अब खुलकर सामने आने लगा है. गांव के लोग भी अक्सर छींटाकशी करते रहते हैं. सीतापुर में एक अध्यापिका की बालात्कार के बाद हत्या का मामला विगत वर्ष सामने आया था.

प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का स्थानांतरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के माध्यम से होता है अर्थात् स्थानांतरण के कारण की व्याख्या का काम उनका है, पर ऐसा किया नहीं जाता. इस पद पर तैनात इंद्रपाल शर्मा की दक्षता और क्षमता का ये उदाहरण काफ़ी है कि वे पूरे प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात एकमात्र आला अधिकारी हैं जो पूर्व की मुलायम सरकार में भी इसी पद पर तैनात थे. आज भी वे माया सरकार के लाडले हैं. स्थानांतरण के इच्छुक अध्यापकों का कहना है कि यदि उनकी इस पद पर विगत वर्षों की तैनाती के काल की संपत्ति की जांच कराई जाए तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ साफ़ हो जाएगा. अभी हाल में ही फ़र्रुख़ाबाद के एक प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात कानुपर की मूल निवासी उमा यादव के पति एडवोकेट विनय यादव ने अपनी पत्नी के सस्पेंड किए जाने और कानपुर स्थानांतरण में आने वाली परेशानियों से आज़िज़ आकर आत्महत्या कर ली. विनय की पत्नी को वहां के एक शिक्षा अधिकारी ने बिना वजह निलंबित कर दिया था. बताया जाता है कि एक स्थानीय सत्ताधारी दल के नेता ने बहाली के लिए दस हज़ार रुपये भी लिए थे. पति-पत्नी रुपये देने के बावजूद बहाली न होने और कानपुर स्थानांतरण न होने से काफ़ी परेशान थे. इसी तनाव में एक दिन विनय ने आत्महत्या कर लिया. उसने अपने सुसाइड नोट में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को भी अपनी आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनका स्पष्ट नामोल्लेख किया था, जबकि मंत्री अपने विभाग से संबंधित मामला न होने से अपनी इस ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे. विनय का मानना था कि उसकी पत्नी की इस स्थिति के लिए मंत्री ज़िम्मेदार हैं. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में गर्माहट लाने वाले इस प्रकरण में आंदोलित वकील बहुत लंबे समय तक अपने रुख़ पर क़ायम न रह सके. इसका कारण स्पषट करते हुए सुसाइड नोट में आरोपों की स्पष्टता न होने की बात वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार शुक्ला कहते हैं. शुक्ल मानते हैं कि अधिवक्ता विनय यदि स्पष्टत: अनंत मिश्रा के बारे में लिख गए होते कि मंत्री क्यों और किस तरह से ज़िम्मेदार हैं तो उसके परिवार की क़ानूनी मदद आसानी से की जा सकती थी और मंत्री को क़ानूनी दायरे में लाया जा सकता था. दूसरी ओर भयभीत और निराश्रित उमा पति को खोने के बाद कोर्ट-कचहरी के बवालों में नहीं पड़ना चाहती. यद्यपि वह सुसाइड नोट को आधार बनाकर शासन और न्यायालय से स्वयंमेव न्याय होने की आशा लगाए है. लगभग इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एक लेखपाल की आत्महत्या में नाम आने पर उसके आला अधिकारियों पर मुक़दमा दर्ज कराए जाने और दूसरी तरफ़ इस मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री से मामला जुड़े होने के कारण प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया रसूखदारों को बचाने का प्रतीत होता है, परंतु मंत्री का नाम सुर्ख़ियों में आने के बाद उमा यादव को इसी दिन बहाल किया जाना जिस दिन उसने अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था, इसका बिना विभागीय प्रक्रिया पूरी किए कानपुर नगर में स्थानांतरण कर दिया जाना ये अवश्य स्पष्ट करता है कि सबकुछ मंत्री के संज्ञान में था. इस मामले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को किसी भी स्तर तक बदलवाने में वे पूरी तरह सक्षम हैं. शिक्षक नेता सुनील कटियार कहते हैं कि बसपा सरकार में पिछड़ी जातियों की काम न होने की घोषणा करने वाले मंत्री की इस दरियादिली का कारण उनका इस मामले में लिप्त होने के लिए पर्याप्त प्रमाण है. शीलू प्रकरण की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए मंत्री अनंत मिश्रा पर मुक़दमा क़ायम कराना चाहिए. श्री कटियार कहते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए मंत्री के नाम संबोधित पत्र फैक्स कर आत्महत्या करना ही सही तरीक़ा है तो स्थानांतरण के लिए प्रदेश में लाखों आत्महत्याएं हो जाएंगी. दूसरी तरफ़ इस घटना से सबक़ न लेते हुए पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग में बाबू और अधिकारियों के स्तर पर भ्रष्टाचार की हद होने लगी है. इसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं होने लगी हैं. इसी तरह फ़र्रुख़ाबाद ज़िले में एक और अध्यापिका ने अपने स्थानांतरण को लेकर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उसकी मांग जिलाधिकारी ने तत्काल पूरी कर दी. प्रदेश सरकार ने भी ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किया है, परंतु अध्यापकों के गृह-जनपद में स्थानांतरण का रास्ता अभी बंद है. सोचने वाली बात तो यह है कि क्या वर्तमान सरकार की संवेदन-शून्यता का यह चरम है कि प्राथमिक अध्यापक और अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए उनका या उनके परिजनों की आत्महत्या ही अंतिम रास्ता रह गया है?

अभी हाल में ही फ़र्रुख़ाबाद के एक प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात कानुपर की मूल निवासी उमा यादव के पति एडवोकेट विनय यादव ने अपनी पत्नी के निलंबित किए जाने और कानपुर स्थानांतरण में आने वाली परेशानियों से आज़िज़ आकर आत्महत्या कर ली. विनय की पत्नी को वहां के एक शिक्षा अधिकारी ने बिना वजह निलंबित कर दिया था.

विनय यादव

feedback@chauthiduniya.com